आवास योजना में उगाही का मामला आया सामने

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में सब के लिए आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आवास योजना में राशि आवंटन कराने को लेकर वार्ड पार्षद व उनके प्रतिनिधि पर 10 हजार रुपये मांगने का आरोप लाभुक के द्वारा लगाया गया है। उक्त मामले को लेकर लाभुक ने जिलाधिकारी महेंद्र कुमार से शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मामला जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में जांच को भेज दिया। जिसके बाद जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद पिंकी देवी ने बताया कि पैसे मांगने का आरोप बिल्कुल निराधार है। जियो टैगिंग की वजह से दूसरी किस्त की राशि लाभुक को नहीं मिल पाया है। आपको बताते चले कि डीएम को दिए आवेदन में पीड़ित लाभुक किशन लाल पासवान ने वार्ड संख्या 28 के वार्ड पार्षद व उनके प्रतिनिधि सुधीर दास पर आरोप लगाया है कि मुझे नगर परिषद के द्वारा आवास आवंटन किया गया था। जिसमें प्रथम किस्त की राशि के आवंटन के एवज में पार्षद प्रतिनिधि सुधीर दास ने डरा धमका कर 10 हजार रुपये ले लिया।उसके बाद दूसरी किस्त की राशि आवंटन के लिए भी वार्ड पार्षद व उनके प्रतिनिधि ने 10 हजार की राशि मांग की।सुधीर दास द्वारा यह कह कर रुपये की मांग की जा रही है कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी को रुपये देना पड़ता है।आप गौर करे कि प्लास्टिक टांग कर एवं खुले आसमान के नीचे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे किशनलाल मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पीड़ित किसनलाल पासवान का कहना है कि जहां अन्य लाभुकों को प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त की राशि भी मिल गई है वहीं मुझे घूस नहीं देने के कारण दूसरी किस्त की राशि नहीं मिल पाया है। गौर करे कि हाउस फॉर आल योजना के तहत जिन-जिन लाभुकों को राशि दी गई है उसमें बहुत बड़ा लूट हो रही है। नगर परिषद किशनगंज से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नगर के कुल 33 वार्डो का लाभुकों की सूची और जिन-जिन लोगो को हाउस फॉर आल के तहत राशि दी गई है उनकी सूची की मांग की गई है।किंतु 4 माह से ऊपर होने चला आवेदक को आज तक नगर परिषद किशनगंज द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराया गया है। जो जांच का विषय है। सूत्र कहता है कि अगर हाउस फॉर ऑल का जांच किया जाए तो उगाही का भंडाफोड़ हो सकता है। यही नही जो लोग किशनगंज के निवासी नही है उन्हें भी राशि दी गई है। आमजनों का कहना है कि उगाही का जब भंडाफोड़ हो जाता है तब जांच करने की बात आती है। जांच के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। ताकि गरीबो का हक के साथ कोई खिलवाड़ नही करे। क्या कहते है नप उपाध्यक्ष जमशेद आलम...आवास योजना व अन्य किसी योजना में अगर जनप्रतिनिधि अथवा नगर परिषद कर्मी द्वारा किसी भी तरह से राशि की मांग की जाती है तो उसकी शिकायत करें। यह जानकारी देते हुए नप उपाध्यक्ष जमशेद आलम ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी व कर्मियों के नाम पर आवास योजना में वार्ड पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा राशि मांगी जा रही है तो लाभुक इसकी शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी को सीधे करें या कार्यालय में करें। इसके लिए नगर परिषद कार्यालय में शिकायत पेटी भी लगाई गई ताकि कोई भी व्यक्ति बेहिचक शिकायत कर सके। उन्होंने कहा कि आवास योजना में किसी प्रकार की राशि किसी को नहीं देनी चाहिए। बताते चलें कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 के लाभुक किशन लाल पासवान ने आवास योजना में प्रथम किस्त की राशि आवंटन के लिए पार्षद प्रतिनिधि को 10 हजार रुपये देने का आरोप लगाया है। जिसकी शिकायत जिला पदाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर मामला जिला लोक शिकायत केंद्र भेजा गया। ●

एस.पी. को आ रहे सांसद के नाम फर्जी कॉल

● धर्मेन्द्र सिंह

पूर्णिया पुलिस कप्तान विशाल शर्मा के मोबाइल पर दोपहर 3 बजकर 30 मिनट में एक अनजान नम्बर से कॉल आता है, हेलो मैं सांसद संतोष कुशवाहा बोल रहा हूँ, आप एसपी बोल रहे है। एसपी ने कहा जी हाँ मैं एसपी बोल रहा हूँ। आप माननीय सांसद जी बोल रहे है, लेकिन आपकी आवाज तो माननीय सांसद जी की नही लग रही है। इतना सुनते ही उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर एसपी विशाल शर्मा ने सांसद संतोष कुशवाहा से बात की तो पता चला कि सांसद ने इस तरह का कोई भी फोन नही किया है। कुछ देर बाद दुबारा फिर उसी अनजान नम्बर से एसपी विशाल शर्मा के मोबाइल नम्बर पर फोन आता है। फिर एसपी ने जब सख्ती से पूछा तो उधर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आपको बताते चलें कि पुर्णिया जिले में अपराध को लेकर पुर्णिया पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा काफी गम्भीर है। इनके आने के बाद अपराधियों की माने तो जैसे कमर ही टूट गई है। फिलहाल पुर्णिया की आवाम काफी शांति महसूस कर रहे है। अपराधी या तो जेल में है या फिर शहर छोड़कर भाग गए है। अपराधी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके है कि पुर्णिया जिले में क्राइम कर बच निकलना नामुमकिन है। खबर लिखने तक अनजान व्यक्ति को पुलिस ढूंढ रही है। वहीं एसपी के तबादले के लिए रचा जा रहा है षडयंत्र आप गौर करे कि जब से पूर्णिया में एसपी विशाल शर्मा का पदस्थापना हुआ है तब से जिले में 2 नम्बरी काम करने वालो का धंधा चौपट हो गया है। सबसे ज्यादा कमर शराब माफिया और जमीन ब्रोकरों की टूटी है। यही वजह है कि अब पूरी ताकत लगाकर पूर्णिया एसपी के तबादले के लिए षडयंत्र रचा जाने लगा है। इसके लिए शहर के कई सफेदपोशो का सहारा भी लिया जा रहा है। पूरा पूर्णिया में यह चर्चा है कि नए एसपी न पैरवी सुनते है न ही उन्हें गलत करने की आदत है। इस वजह से कई दलालो के पेट पर जबरदस्त लात पड़ी है। बैंक लूट कांड, बालगृह गोली कांड हो या फर्नीचर व्यवसायी गोलीकांड सभी का उन्होंने सफल उद्भेदन किया है। कई ऐसे भी कांड है जिनका उन्होंने महज कुछ घंटों में उद्भेदन किया। पदस्थापना के बाद उन्होंने जनता दरबार मे आने वाले लोगो की परेशानी को देखकर उसमे काफी फेरबदल की। अब लोगो के परेशानी को सुनने और उसके निष्पादन के लिए खुद वे थाना में ही जनता दरबार लगा रहे है। इससे गाँव देहात से सफेदपोशो की आमदनी भी बंद हो गई है। इसके अलावा अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे से लेकर पासपोर्ट भेरीफिकेशन जैसे परेशानियों में भी वयापक बदलाव किए। कानून पसंद पूर्णिया एसपी अपने कार्यकाल में कई थानाघ्यक्ष और पुलिसकर्मी को भी गलत आचरण की वजह से सस्पेंड कर चुके है। अमन पसंद पूर्णियावासी को अब पूर्णिया एसपी के प्रति विश्वास जगने लगा है। मगर विगत एक माह से उनके तबादले के षडयंत्र रचे जाने लगे है। कई सफेदपोश इस तैयारी में है कि कोई झूठा आरोप लगाए ताकि तुरंत उच्चाधिकारियों से लेकर सीएम पीएम तक शिकायत किया जा सके। मगर बाबू यह पूर्णिया है...पब्लिक मूर्ख नहीं है, सब देख रही है,सब जान रही है। ●

टॉप टेन यूनिवर्सिटी में होगा डॉ0 राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

बीते 15 नवम्बर को को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन एवं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा प्रांगण में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह का विधिवत शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया तथा दीक्षांत समारोह में छात्र–छात्राओं को विभिन्न संकायों में स्वर्ण पदक, पी0एच0डी0 डिग्री, मास्टर डिग्री एवं बी0एस0सी0 डिग्री की उपाधि प्रदान की गई।

बताते चले कि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, जिसकी स्थापना राज्य सरकार ने की थी। पहले दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन बहुत ही उपयुक्त है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी बिहार के महामहिम राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने, यह हमारे लिए गौरव की बात है और इससे हमलोगों को संतोष की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला एग्रीकल्चर रिसर्च केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था जो पहले फिलिप्स ऑफ यू0एस0ए0 के नाम पर था। भयंकर भूकंप के बाद यह संस्था दिल्ली चली गयी और 1970 में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार ने की। इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परिणत करने के लिए हम लगे रहे और अंततोगत्वा 2016 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इसके लिए हमने हर शर्त स्वीकार किया। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में यह एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय था। 1908 में भागलपुर में स्थापित सबौर कृषि महाविद्यालय को वर्ष 2010 में हमलोगों ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट किया। केंद्र में जब यू0पी0ए0 की सरकार थी और डॉ0 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कृषि के मसले पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में एक एक्सपर्ट ने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा कि देश के अंदर बिहार में उत्पादन और उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। हमने उस मीटिंग में कहा था कि बिहार में उत्पादन और उत्पादकता दोनों जल्द ही बढ़ेंगे और वर्ष 2008–2012 के लिए हमने पहला कृषि रोड मैप तैयार करवाया। इसके बाद बीज विस्थापन दर के मामले में धान में 11 फीसदी से 42 फीसदी, गेहूं में 10 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी और मक्का में 60 से बढ़कर 86 फीसदी की बढोत्तरी हुई। 2012–2017 के दूसरे कृषि रोड मैप की लॉन्चिंग तात्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने की थी और अब तीसरा कृषि रोड मैप भी राष्ट्रपति के द्वारा लांच किया जा चुका है। मीटिंग में जब एक्सपर्ट बोल रहे थे, उस समय धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 12.5 क्विंटल थी जो बढ़कर 25.25 पर पहुंच गयी, गेहूं की उत्पादकता 14 से बढ़कर 28.5 जबकि मक्का की उत्पादकता 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 40 क्विंटल पर पहुंच गयी। बिहार को वर्ष 2012 में चावल के लिए, वर्ष 2013 में गेहूं के लिए और वर्ष 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला। इसके लिए मैं किसानों, कृषि विशेषज्ञों एवं सभी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए चुनौती है। पहले बिहार में 1200 से 1500 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ करता था, जो अब घटकर 800 मिलीमीटर से भी कम पर पहुंच गया है। इस वर्ष बिहार के 23 जिलों के 275 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुनिया भर में प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्याएं उपजी हैं, इसके लिए बिहार के लोग कसूरवार नहीं है लेकिन बिहार के लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया के किसी भी इलाके में कुदरत के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका दुष्प्रभाव दूसरी जगहों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सबौर कृषि विश्वविद्यालय और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की जो यहां शाखा खुली है, इन सबको

मिलकर लोगों को अल्टरनेटिव सुझाव देना होगा ताकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए क्रॉप साइकिल का कॉन्सेप्ट डेवेलप किया जा सके। इसके लिए सिर्फ पूसा और सबौर में ही नहीं बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से अगर एसेस नहीं किया गया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आज भी बिहार में 76 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। इसके साथ–साथ इस साल के अंत तक हर घर को बिजली कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य था, जिसे 25 अक्टूबर 2018 को ही पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब अगले साल तक अलग एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की गई थी और अब हमलोगों ने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ इतने अधिक संस्थान स्थापित हो गये हैं, अब उसे सुदृढ़ करने की दिशा में सोचिये। दिगर बात है कि कृषि की पढ़ाई करने के लिए अधिकांश विद्यार्थी एडमिशन लेते थे, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, जिसे देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से ऐसे विद्यार्थियों को किताब खरीदने के लिए 6 हजार रुपये के साथ ही प्रतिमाह 2 हजार रुपये देने का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर ध्यान दें। मुझे पूरा भरोसा है कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूरी मजबूती के साथ काम करेगा और टॉप टेन केंद्रीय यूनिवर्सिटी में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी शुमार होगा। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मैं दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक एवं उपाधि हासिल करने वाले छात्र–छात्राओं को बधाई देता हूँ।

गौरतलब है कि कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि वे कम जमीन तथा कम पानी के साथ ज्यादा कृषि उत्पादकता वाली कृषि प्रणाली विकसित करें। उन्होंने अपने कृषि वैज्ञानिकों पर गर्व करते हुए कहा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अब खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर सबी को जरूरी पौष्टिकता उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने बीज से बाजार तक किसानों को सहायता पहुंचाने की जरूरत का उल्लेख भी किया। राष्ट्रपति ने कृषि विकास के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि मंडियों ई–नाम

की स्थापना, नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मुद्रा योजना, किसान संपदा योजना, फसल बीमा विस्तार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने आशा जताई कि इनसे कृषि और किसानों की स्थिति बेहतर हो सकेगी। बिहार राज्य में कृषि के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति पर प्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालन भी कृषि का एक अंग है और बिहार को वर्ष 2018 में पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी रहने का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने कृषि एवं कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योंगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया और इस क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाओं से अधिकाधिक अवसर मुहैया कराने के लिए काम करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि आज अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने अपने को कृषि कार्यों से जोड़ना शुरू कर दिया है और परंपरागत तरीकों से उपर उठकर जैविक खेती कर रहे हैं। उनके उत्पादों की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में ही अच्छी मांग है। इस अवसर पर उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को आज की एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इससे सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि सब कुछ प्रभावित हो रहा है। इसके दुष्प्रभावों से खेती–बाड़ी को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, संस्थानों और शोधकर्ताओं को आगे आने को कहा। दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल 33 विद्यार्थियों में 25 छात्राओं के होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपनी बेटियों पर नाज है। उन्होंने दीक्षांत समारोह के आयोजन के समय को भी खास बताते हुए कहा कि त्योहारों के उल्लासमय वातावरण में यह प्रथम दीक्षांत समारोह सुखकारी है। खासकर सूर्योपासना के छठ पर्व का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि इस अवसर पर स्वच्छता और सौहार्द का जो दृश्य दिखता है, ये पूरे देश के लिए मिसाल है।

बताते चले कि इस दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के साथ–साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह, राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर देश की प्रथम लेडी श्रीमती सविता कोविंद, कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार, भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी, पर्यटन मंत्री श्री प्रमोद कुमार, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा, सांसद श्री रामनाथ ठाकुर, सांसद श्री अजय निषाद, राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ0 प्रफुल्ल कुमार मिश्र, कुलसचिव डॉ0 रवि नंदन, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड एवं विद्वतजन के सदस्यगण, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री के0एस0 द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राएं मौजूद थे। ●

फस्ट एंड फास्ट की आपाधापी में बनाये जाते हैं फेक ब्रेकिंग न्यूज

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

बीते 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना भवन स्थित ''संवाद'' कक्ष में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा **''डिजिटल युग में पत्रकारिता आचारनीति और चुनौतियां''** विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर अपने–अपने विचारों से श्री दिनेश कुमार निदेशक पी0आई0बी0 पटना, श्रीमती रजनी शंकर स्टेट हेड हिन्दुस्तान समाचार पटना, श्री प्रशान्त झा स्पेशल क्रॉसपौंडेंट इंडिया टीवी पटना, श्री मणिकांत ठाकुर स्वतंत्र पत्रकार पटना तथा श्री रवि अटल वरिष्ठ पत्रकार पटना ने अवगत कराया। उक्त संगोष्ठी में डिजिटल युग के ताकत पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि इसे समझना, मैनेज करना तथा समाचारों की तथ्यपरकता से रू–ब–रू कराना आवश्यक है। आज डिजिटल युग एक शक्ति बन चुकी है परन्तु चुनौतियां कहीं न कहीं दर्द भी दे रही हैं। इसी दर्द की वजह को समझने की जरूरत है।

गौरतलब है कि पत्रकारिता जगत में डिजिटल युग एक अच्छी शुरूआत है, जिससे पत्रकारिता त्वरित और आसान हुई है, लेकिन फेक न्यूज से बचने के लिए सजग होना होगा ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बची रहे। इस युग में यह आवश्यक है कि पंच इन्द्रियों को इस प्रकार इस्तेमाल किया जाये कि चुनौतियों का सामना आसानी से और निष्पक्ष रूप से, गति के साथ हो और उससे उत्पन्न होने वाले दर्द से कैसे बचा जाये, इस पर फोकस होना चाहिए। कहा जाता है कि एक ही चाकू दो दर्द देता है, क्योंकि चाकू का इस्तेमाल एक सर्जन भी करता है और एक कसाई भी करता है, अतः हम जिस डिजिटल शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वह सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज की नीयत से नहीं बल्कि समाचार की सत्यता की पुष्टि के साथ प्रयास हो। डिजिटल युग में विदेशों में रोबोट का इस्तेमाल बखूबी शुरू हो गया है, रोबोट एंकरिंग का भी कार्य अब करेगा। यहां यह देखना होगा कि आर्टिफिशियल रोबोट जो भर्चुअल इमेज है वह बेहतर ढ़ंग से समाज से जुड़ेगा या एक एक्चुअल एंकर बेटर होगा। रोबोट जैसे डिजिटलाईजेशन की प्रयोगात्मकता से पत्रकारिता जगत में नौकरी में कमी आने की भी संभावना है। दूसरी तरफ डिजिटल युग में इलेक्ट्रोनिक मीडिया की खबरें देश–विदेश में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है जबकि पहले ऐसा संभव नहीं था। इस प्रकार की प्रारम्भिक शुरूआत वर्ष 2004 में हुई थी जो अब अपनी गति पर है। इसमें दिक्कत यह होती है कि फस्ट एंड फास्ट की आपाधापी में मीडिया तथ्यों की सत्यता को नजरअंदाज करते हुए जो भी उल्टा–सीधा संग्रह करता है उसे ब्रेकिंग के रूप में डाल देता है। इस तरह से जो समाचार प्रसारित होता है वह फेक न्यूज हो जाता है, इससे बचने की जरूरत है और तथ्यपूर्ण समाचार को ही प्रसारित करने की आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता को महत्त्व देना होगा। सनद् रहे कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया की चुनौतियां सबसे अधिक है, क्योंकि अल्प समय में ही सोशल मीडिया अपने समाचारों को प्रसारित कर देता है, जिससे फेक न्यूज की संख्या बढ़ी है। सोशल मीडिया में सचेत रहकर तथ्यपरक समाचार से ही अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि त्वरित और व्यापक के हिसाब से सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, वशर्ते मीडिया समाचार की विश्वसनीयता हेतु आत्म नियंत्रण की आवश्यकता को बखूबी समझें।

बताते चले कि उक्त अवसर पर उप निदेशक श्री रवि भूषण सहाय ने सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के उप सचिव श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री अशोक कुमार, पी0आई0बी0 निदेशक श्री दिनेश कुमार, इंडिया टीवी के स्पेशल क्रॉसपौंडेंट श्री प्रशान्त झा एवं स्वतंत्र पत्रकार श्री मणिकांत ठाकुर को पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। इस संगोष्ठी को दीप प्रज्वलित कर प्रारम्भ करने के पूर्व सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सहायक निदेशक डॉ0 नीना झा ने हिन्दुस्तान समाचार के स्टेट हेड श्रीमती रजनी शंकर को तथा प्रेस सहायक श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने उप निदेशक श्री रवि भूषण सहाय को पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर स्वागत किया। वही सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के उप निदेशक श्री रवि भूषण सहाय ने उक्त विषय पर अपने विचारों से अवगत कराते हुए संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा सहायक निदेशक डॉ0 नीना झा ने संगोष्ठी के प्रारम्भ में सभी का स्वागत करते हुए तथा संगोष्ठी के विषय पर प्रकाश डालते हुए सभा संचालन कार्य सम्पन्न किया। ●

ओडीएफ निर्माण में चरपोखरी प्रखण्ड ने मारी बाजी

● मणिभूषण तिवारी

जीविकाकर्मी चरपोखरी प्रखण्ड ने जिले के 14 प्रखण्डों में सबसे पहले बाजी जीत गये। ये प्रखण्ड 02 अक्टूबर 2018 को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया था। जहाँ प्रधानमंत्री का नजर था और टारगेट था। गाँधी जयंती इस पर चरपोखरी प्रखण्ड के कर्मचारी, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने 100 प्रतिशत खरा उतरने का प्रयास किया और सफल भी हुए। इनका मानना था कि स्वच्छता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान को हम किसी भी सुरत में हारने नहीं देंगे और ऐसा ही हुआ। इस पुनीत कार्य को समय पर पूरा करने के लिए बी.पी.एम. को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रखण्ड के बी.डी.ओ. तथा प्रखण्ड प्रमुख भी सम्मानीत हुए। जीविका दीदी ने ये साबित कर दिखाया कि हम किसी से कम नहीं और इस कार्य के माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से हमारे देश का नाम ऊँचा हुआ और पूरे विश्व के लिए यह अभियान एक संदेश के रूप में उभर कर सामने आएगा। वह दिन दूर नहीं जब विश्व के बड़े-बड़े देश को भारत के आदर्शों पर चलना होगा। लोहिया स्वच्छता अभियान के बैनर तले सम्पन्न कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के प्रयासों को पंख देने में लोगों में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसमें जनता की भी भुमिका अत्यन्त सराहनीय रही। वी.पी.एम. चरपोखरी दीपक कुमार ने केवल सच प्रतिनिधि को बताया कि मैंने भी अपने जीवन काल में पहली बार इस नेक कार्य को लोगों के सहयोग से करके खुद को गौरवान्वित महसुस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है हमारा देश अन्य देशों के लिए आइडियल होगा। ऐसा कार्य मैंने सोचा भी नहीं था जो कि मोदी जी के निर्णय और साहस ने कर दिखाया। इससे महिलाओं में कंफिडेंस बढ़ा है। उन्हें शौचालय का सौगात मिला वो खुद को गौरवान्वित एवं सम्मानित महसूस कर रही है। अब आगे हमारा टीम उन जिलों में कार्य करने जा रही है, जहाँ ओ.डी.एफ. में देर हो रही है। ●

पंचायत को मिला प्रथम ओ.डी.एफ. का सौगात : पुनम देवी

15 सितम्बर 2018 को प्रखण्ड चरपोखरी के सियाडिह पंचायत को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया। इस आशय की जानकारी पंचायत मुखिया पुनम देवी ने दी। इससे सम्बन्धित एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रखण्ड के बी.डी.ओ. तथा थाना प्रभारी,जिला स्वच्छता कार्यक्रम से विजय कुमार, मुखिया पुनम देवी, सांख्यिकी पदाधिकारी विशेष प्रेरक एवं सभी प्रेरक जीविका के सी.एम. तथा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं सदस्या ने ने भाग लिया। जीविका दीदी जी उपस्थित रही तथा पंचायत के जनता का भी भरपुर सहयोग मिला। सभी लोगों को उनका उचित सम्मान मोमेन्टो, गमछा एवं पगड़ी देकर किया गया। महिला कर्मचारियों एवं महिला पदाधिकारियों को सॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। ये कार्य जीविका एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से सम्भव हो सका। स्वच्छ भारत मिशन का एक अनुठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तथा जिलाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त, भोजपुर के अथक प्रयास से संभव हो सका। उन्होंने आगे बताया कि उनके एवं हम सभी के जीवन में ये पहला मौका था जब हमलोग घर-घर शौचालय बनवा कर खुद को गौरवान्वित महसुस कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे नेक कार्य के लिए हमारी मातायें-बहनें कितनी खुश है। उक्त शौचालय की सौगात पा कर मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और पुरूष वर्ग भी काफी खुश हैं इस नेक कार्य से उन्हें भी बाहर नहीं जाना पड़ता। ऐसे में उनका जो समय बर्बाद हो जाता था, बाहर जाने में आज फ्रेश होकर काम पर निकलते हैं। सचमुच हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा सौगात दिया है, भारतवर्ष को। वे कोटि-कोटि धन्यवाद के पात्र हैं।

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। बेरोजगारी के अभिशाप को मिटायें। देश के सभी प्रदेश की राजधानी और देश के सभी प्रदेश के शहरों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें।

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308/9308727077

दबी जुबां की दबंग कहानी

● बिन्ध्याचल सिंह

बक्सर जिला अन्तर्गत दो कोषागार पदाधिकारी अपनी सेवा पूर्णत सेवा शुल्क के साथ दे रहे है। जिसमें प्रथम–कोषागार पदाधिकारी 'डुमरॉव' और दुसरा–कोषागार पदाधिकारी 'बक्सर' है। दोनो पदाधिकारीयो का अलग–अलग कार्य पद्धति हैं। जैसे–कोषागार पदाधिकारी 'डुमरॉव' के कार्यालय में ग्रामीण कार्य से आनेवाले प्रत्येक एक लाख रू0 के चेक पर 200/रू0 सेवा शुल्क लिया जाता है। यानि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्गत एक करोड के चेक पर कोषागार पदाधिकारी 20000/रू0 सेवा शुल्क लेते हैं। जबकि कर्मचारियो के वेतन के चेक कोषागार कार्यालय में आता है तो प्रत्येक चेक पर एक हजार रूपया लिया जाता है। चेक चाहे कितनी भी राशि की क्यो न हो। उपरोक्त बात की जानकारी शिक्षा विभाग ब्रहम्मपुर के एक अनुसेवक ने मार्च–2018 में दी। अनुसेवक ने बिहार सरकार की नीति और कोषागार पदाधिकारी की नियम पर अफसोस भरा शब्दो में कहा की एक तो वेतन छः–छः माह पर मिलता है उसपर भी कोशागार पदाधिकारी कार्यालय में एक हजार देना मजबुरी बनी रहती है। जबकि कोषागार पदाधिकारी कार्यालय 'बक्सर' के कार्यालय में पथ निर्माण विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा निर्गत चेक पर ठीकेदार स्वय कोशागार कार्यालय आकर अपनी सेवा शुल्क अदा करते है। सेवा शुल्क ठीकेदार कितना अदा करते है इस बात की जानकारी केवल सच प्रतिनिधी को नही है। लेकिन किसी भी विभाग से सेवा निवृत कर्मचारी से कुल राशि का दस प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जाता है। निम्न बात की जानकारी प्रतिनिधि को उत्पाद विभाग से सेवा निवृत कर्मचारी अक्टूबर–2017 में दी थी। जो भोजपूर जिला के जगदीशपुर प्रखण्ड के हेतमपुर गॉव के रहने वाले थे। प्रिय पाठकगण आपलोगो को बताते चले कि बक्सर जिला में अगर आप वाहन चलाने के लिये लाईसेंस बनवाना चाहते है तो आपको गाडी चलाने का परीक्षा नही देना पडेगा। उसके एवज में दो हजार रू0 मोटरयान निरिक्षक को देना पडेगा और आपको लाईसेंस प्राप्त हो जाएगा डी0 टी0 ओ0 कार्यालय की जानकारी धीरज कुमार प्रखण्ड ब्रहम्मपुर व राजु कुमार राजपुर ने दी। साथ ही आपलोगो को अवगत कराना चाहता हुं कि जिला के उच्च पदाधिकारी से मिलने की इच्छा न किजीएगा वरना आपको पुरे दिन इन्तजार करना पडेगा। साथ ही अगर जिला के उच्च पदाधिकारी के आदेशपाल आपके सम्बन्धी है तो आप सपने में भी मिलने की इच्छा न करेगे क्योकि आदेशपाल चाहेगे कि सम्बन्धी को अधिकारी से मिलावा दूं। और आदेशपाल जब पदाधिकारी महोदय से आपकी बात बतायेगे तो पदाधिकारी मिलने का जवाब न देकर आदेशपाल को बहुत डाटेगे। ●

प्रदुषण नियंत्रण एवं जल संरक्षण सरकार के बस की बात नहीं

● मणिभूषण तिवारी

आज लोग दिल्ली और एन.सी.आर. से भागने लगे हैं। कल सभी बड़े शहरों से पलायन होगा लोगों का। क्योंकि सरकार के पास इसके लिए ना तो कोई ठोस एजेन्डा है और ना ही कोई जागरूकता कार्यक्रम है। सिर्फ खुले में शौच मुक्त करवने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाता। इसके लिए सरकार को चाहिए कि अनेक सामाजिक संगठनों के साथ मीटिंग को और सर्वाधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जरूरी कदम उठाये। सिर्फ ऑड इन इवेन तथा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने से काम नहीं चलने वाला है। क्या ये सरकार को पता नहीं है कि क्रॉप कटिंग के बाद फरारी का जलायेंगे या नहीं। सरकार को चाहिए कि उसके फराली को खरीद कर उससे कोई काम लें। प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेवार ठहराने के जगह सरकार को पहले ही व्यवस्था करवाना चाहिए। बहुत दिनों से कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात हो रही है। मगर सरकार तो चाहती ही नहीं कि किसानों का कल्याण हो। बहुत लम्बे समय से दिल्ली के लोग प्रदूषण और डेंगु जैसे समस्याओं से जुझ रहे हैं। नेताओं का क्या है वे तो ए.सी. के आदी हो चुके हैं उनका जीवन तो आर्टिफिशियल हो चुका है, मगर जरा सोचिये 125 करोड़ से ज्यादा जनता क्या प्रकृति से दूर रह सकती है। रही बात जल संरक्षण की तो सरकार का तो इस बात की खबर है ही कि आने वाले समय में कितना बड़ा जल संकट करने ` लिए

सरकार तो कार्य कर रही रही है। जैसे कि बिहार सरकार की सात निश्चय योजना के अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना हर घर नल-जल योजना आज अपने चरम सीमा पर है। मगर खराब रख-रखाव के कारण प्रतिदिन कितना पानी बेकार बह कर बर्बाद हो रहा है। सरकार को इसका अंदाजा बिल्कुल ही नहीं है। नदियों के सफाई का कार्य कई वर्षो से चल रहा है, परन्तु आप अपने दिल से पुछिये कि एक भी नदी साफ हुई है क्या? नदियों के सुखने का कारण क्या है क्या कभी सोचा है किसी सरकार ने। धरती पर भगवान है, धरती पर जीवन है परन्तु इसको छोड़कर चाँद और मंगल पर घर बनाने की बात हो रही है। नदियों का जलधारण क्षमता कम हो रही है, नदी के किनारे पेड़ पौधे नहीं रहने से एवं बाढ़ की विविषिका को भी झेलना पड़ रहा है। जरा सोचिये हम कहाँ जा रहे हैं। आने वाले समय में धरती पर जीवन कितना कष्टकारी होगा। पानी की कमी कही ऐसा ना हो कि तृतीय विश्व युद्ध का कारण बने। इससे पहले सभी सरकार और सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। इसके लिए विकास शब्द बेमानी होगी। ●

बक्सर की सुरक्षा व्यवस्था एक नजर में

● बिन्ध्याचल सिंह

विश्वामित्र की नगरी बक्सर अपने आपको बहुत ही सुरक्षित महसुस कर रही है। जिसका श्रेय नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा की अथक प्रयास की देन है। 2013 बैच के पदाधिकारी श्री वर्मा जी का इतिहास रहा है कि जिस जिला में अपनी कर्तव्यनिष्ठता व ईमानदारी के साथ सेवा दे चुके है वहा की जनता आज भी सुरक्षा–व्यवस्था के लिये श्री वर्मा को याद करती है जिसका प्रमाण नवादा व मुजफ्फरपुर जिला से प्राप्त कर सकते है। अक्टुबर–2018 से बक्सर की सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर सम्भालने का पहला असर शहर के चौक चौराहे पर देखा गया जहॉ जाम नाम की चीज नही है।शहर के सबसे व्यस्त चौराहा ज्योति चौक वीर कुॅवर सिह चौक मुनीम चौक यमुना चौक सेन्डीगेट गोलम्बर पर आम जनता को जाम से निजात नही मिल रही थी।जबकि वर्तमान में जाम नाम की चीज नही है। दुर्गा पुजा के शुभ अवसर पर जिस प्रकार सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सचमुच

काबिले ए तारीफ है। हालांकि शहर की सुरक्षा व्यवस्था में आर्दश नगर थानाध्यक्ष श्री दयानन्द सिह की अहम भुमिका रहती है। विश्वामित्र की नगरी बक्सर में लगभग सालोभर तीर्थ यात्रियो का आना–जाना रहता है। जिसको ध्यान में रखकर बक्सर पुलिस स्टेशन से रामरेखा घाट तक पुलिस चौबीस घंटे दिखाई देती है। कर्तव्यनिष्ठता से समझौता न करने वाली बक्सर पुलिस की कार्य पद्धति सराहनीय है। आपको बताते चले कि बक्सर जिला अन्तर्गत डुमरॉव अनुमण्डल में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह पदस्थापित है जिंन्होने अनुमडण्ल की शांन्ति–व्यवस्था मे सफलता से एक कदम है जिसका प्रमाण दियारांचल क्षेत्र के आम जनता से प्राप्त कर सकते है। जो शराब कारोबारियो के आतंक से ग्रसित थे। गंगा नदी के रास्ते उतर प्रदेश के बलिया जिला से अवैध शराब की खेप लाने वाले के उपर माने ''दुःख का पहाड'' टुट पडा है। बक्सर जिला में सबसे ज्यादा अवैध शराब पकडने में राजपुर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार व कोरान सराय थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का है। परन्तु देखना यह है कि क्या सुरक्षा रूपी चमकता सूर्य पुरे दिन चमकता रहता है या अपराध लूट के बादल से घिर जाता है या भरी दोपहर में सूर्यास्त होता है।●

लूटेरा है पी.डी.एस. दुकानदार सिकरयॉ में?

● बिन्ध्याचल सिंह

सुपवा हॅसे चलनीया के जेकरा में सत्तहर गो छेद बा'' उपयुक्त भोजपुरी कहावत को चरितार्थ करते हुये जन–वितरण प्रणाली की दुकान संचालित हो रही है जिसके दुकानदार बहुत ही ईमानदार व गम्भीर विचार वाले है जिसमे प्रथम–शिवनाथ साह अनुज्ञप्ति संख्या–72/07 और दुसरा–चन्द्रावती देवी अनुज्ञप्ति संख्या–34/07 है। प्रिय पाठकगण आपलोगो को अवगत कराना चाहता हुॅ कि पी0डी0एस0 दुकानदार शिवनाथ साह तियर पंचायत में संचालित हो रही पी0डी0एस0 दुकानदारो में सबसे ईमानदार दुकानदार है; यही कारण है कि सभी दुकानदारो से सबसे कम यानि मात्र माह में नौ क्विंटल गेहूॅ बाजार में प्रत्येक माह बेचने को ले जाते है जबकि सबसे ज्यादा गेहुॅ चन्द्रावती देवी के पति श्री रजिन्द्र साह प्रत्येक माह पन्द्रह क्विंटल बेचते है। जिसका प्रमाण दुकानदार द्वारा प्रखण्ड से राशन प्राप्त करने के आठ दिन के अन्दर देखा जा सकता है। शिवनाथ साह की ईमानदारी की राशन टेम्पो पर बाजार जाती है जबकि चन्द्रावती देवी का राशन पिकअप से बिहिया बाजार में ले जाई जाती है। जो तियर– बिहिया पथ पर देखा जा सकता है। हांलाकि चन्द्रावती देवी के पति श्री रजिन्द्र साह से जानकारी लेने के लिये केवल सच प्रतिनिधि ने तीन बार अपने पत्रिका में उपलब्ध मोबाईल नम्बर से बात करने की कोशिश कर चुके है। लोकाचार के अनुसार–समुद्र मंथन के समय देवो के देव महादेव ने सश्टि बचाने के लिये स्वयं विश पी चुके थे। ठीक उसी प्रकार शिव नाथ साह और चन्द्रावती देवी के पति सरकार की अनाज बर्बाद न हो इसीलिये बाजार में बेचते आ रहे है। एक अनुमान के अनुसार अनुज्ञप्ति संख्या–72/07 के दुकानदार 2007 से अक्टुबर–2018 तक लगभग 1633500/रूपये की राशन बेच चुके है। उपरोक्त अनुमान सिकरिया गॉव के ग्रमीण और समाजसेवी के द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। नगर पंचायत बिहिया के वार्ड संख्या–05 के पी0डी0एस0 दुकानदार भी मिला–जुलाकर कुछ ऐसे ही लेकिन–परन्तु में शामिल है जिनकी जानकारी मिलते ही सूचीबद्ध किया जायेगा। ●

जिले का सबसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष डुमरॉव थाना में : भरत मिश्रा

● बिन्ध्याचल सिंह

राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भरत मिश्रा ने केवल सच प्रतिनिधि को अपने आवास पर डुमरॉव थानाध्यक्ष के काले करनामे कि जानकारी देते हुये अपने पैड पर लिखित प्रेस विज्ञप्ति दिये। जिसमें सुचीबद्ध शब्द इस प्रकार है–डुमरॉव थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक शिवनारायण राम का कारनामा एक मारपीट में हुए मुकदमा को लेकर सामने आया। डुमरॉव नगर लाला टोली रोड में ऋषी कुमार अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहे थे, कि एक बनावटी विपक्षी रीता देवी अपने गॉव बडका राजपुर से लाव–लश्कर के साथ पहले थाना में गयी। थाना प्रभारी ने पुलिस बल को भेजने की बात कह कर कहा कि आपलोग आगे जाकर काम रोकियें, पुलिस जा रही है। उक्त स्थल रीता देवी 10–12 व्यक्तियो के साथ जाकर स्व हथियार लाठी–डंडा के साथ पहुँचकर दीवार को तोडने लगी। इसी पर ऋशि कुमार एवं उनके परिजनो के द्वारा मना किया गया तो वे लोग नही माने और काफी तोड–फोड व लुट–पाट करने लेंगे इसी बीच मारपीट शुरू हो गया तब तक पुलिस पहुॅची और पहुचते ही दोनो पक्षो को पकड कर थाना ले गई। और दोनो पक्षो से लिखित ली। रीता देवी का डुमरॉव थाना में–377/18 एफ आई आर दर्ज हो गया और ऋशि कुमार द्वारा भी आवेदन दिया गया लेकिन एफ आई आर दर्ज न कर रात में ऋशि कुमार को थाना प्रभारी द्वारा काफी पिटाई कर गाली गलैज कर एफ आई आर को बदलने के लिये दबाव बना कर पहले के आवेदन को हटाकर और उनके विपक्षी से 25 हजार रूपया लेकर बदल दिया गया और सुबह में 378/18 डुमरॉव थाना में एफ आई आर दर्ज की गई। साथ ही दोनो पक्षो को 26/08/2018 को शाम चार बजे चलान किया गया। मामला इतना ही नही हुआ ऋशि कुमार हमारे यहॉ विगत 7 वर्षो से मेरा चार पहिया वाहन के चालक के रूप में सेवा करते आ रहा है। इन सभी घटनाओ को सुनकर जब मै थाना में गया; ऋशि कुमार का आवेदन एफ आई आर स्वयं मै उनसे पुछ–पुछ कर लिखा था और सुबह जब मै मिलने गया तो ऋशि कुमार रो–रो कर बताया कि बडा बाबु रात 11 बजे हमारी बुरी तरह पिटाई कर आवेदन बदलवा दिये है। साथ ही बोले है कि अगर मुँह खोला तो जिदंगी भर जेल में पडे रहोगे। पुलिस की औकात तेरे सात पीढी तक याद रखेगीं। जब ऋशि कुमार की बात सुनकर मै थानाध्यक्ष से पुछा तो कुछ न कहने से और बताने से नकर गये और ऋशि कुमार के विरोधी पक्ष से मिलकर हमारा नाम भी 377/18 में डाल दिये। उपरोक्त सभी मामला भूमि से है। विपक्षी रीता देवी ने एस0डी0ओ0 कोट में 144/18 किया गया। एस0डी0ओ0 डुमरॉव के द्वारा ऋशि कुमार के पिता–अशोक राय के काजगातो को सही पाकर 144/18 को खारीज कर दिया गया। तब जाकर ऋशि कुमार अपने मकान का निर्माण करने लगे। बिना कुछ कागजात और सच्चाई को देखते हुये विरोधी पक्ष से 25 हजार रूपया लेकर काफी पक्षपात किया गया। जो अब तक के डुमरॉव थाना के इतिहास में सबसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष है। इन सभी मामला को जॉच कराने एवं थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने के लिये जोनरल आईजी नैय्यर हसनैन खान को आवेदन पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार ऋशि कुमार ने किया है। ●

मेथोडिस्ट : बढ़ते कदम के सुनहरे पल!

● बिन्ध्याचल सिंह

बक्सर जिला अन्तर्गत डुमरॉव प्रखण्ड के चिलहरी पंचायत के प्रताप सागर में स्थित मेथाडिस्ट बिहार ही नही, अपितु पुरे भारत में यक्ष्मा निवारण में विगत कई दशक से सेवा में देने में चर्चित है। मेथाडिस्ट की स्थापना 1957 ई0 में हुई थी। परन्तु रोगो का निवारण 1958 ई0 से हो रहा है जो डुमरॉव के महाराजा श्री कमल सिंह द्वारा आम लोगो की सुख –सुविधा को ध्यान में रखते हुए,1957 में मेथाडिस्ट के लिए भुमि दान में देकर कृतिमान स्थापित किये। मेथोडिस्ट हॉस्टिल में कुल सात चिकित्सक की सेवा जारी रहती है।जो निम्नवत् है :– प्रथम–डॉक्टर सुबास इमानुएल एमडी, दुसरा–डॉक्टर प्रीता इमानुएल एमडी, तीसरा–डॉक्टर डी एन प्रसाद एम ओ, चौथा–डॉक्टर वी बी सिंह एम ओ,पॉचवा–डॉक्टर सत्यम दॉत, छठवा–डॉक्टर गौतम एम एस आई सातवॉ– डॉक्टर समरेन्द्र आई फिजिसियन पदस्थापित है। हॉस्पिटल मे रोगियो को बैठने के लिये उचित व्यवस्था; रात में ठहरने के लिये व्यवस्था दवा व सूई; पेय जल शुद्ध वातावरण सुरक्षा की पुरी व्यवस्था है। साथ ही रोगी के इलाज के लिये समुचित व्यवस्था है। मेथोडिस्ट हॉस्पिटल 'प्रताप सागर' बक्सर की जिम्मेवारी डॉक्टर आर0 के0 सिंह को सौपी गई है जिसका वे बखुबी से निर्वाह करते आ रहें है। डॉ0 सिह के रोजमर्रा में शामिल, भरती हुई रोगीयो से सुबह–शाम जरूर मिलते है। हॉस्पिटल परिसर की साफ–सफाई, दूर–दराज से आये रोगीयो की सुविधा मुहैया कराना, हॉस्पिटल परिवार अपना परम कर्तव्य समझतें है। अर्थात दुसरे शब्द मे–अतिथि देवो भव्। हॉस्पिटल का क्षेत्रफल 23 एकड है जिसमें पार्क सहित विशालकाय तालाब, आवासीय कमरा सहित हॉस्पिटल का परिसर स्थित है। हॉस्पिटल में मिलने वाली दवाईयॉ व सूई की व्यवस्था हॉस्पिटल मुस्तैदी से रखते है ताकि दुसरे राज्य से आनेवाले रोगीयो को दवा व सूई के लिए भटकना न पडे।इतना ही नही बिहार सहित अन्य राज्यो से आने वाले रोगी और उनके सहायक को हॉपिस्टल द्वारा रेलवे पास दिया जाता है; जिसमें रोगी और उनके सहायक को कुल टिकट के मुल्य का एक चौथाई ही देना पडता है। जो भारत सरकार से पंजीकृत है। मेथाडिस्ट–यक्ष्मा और सर्पदश पर पूर्णतःसफलता प्राप्त कर चुका है जो डॉक्टर आर0 के0 सिंह के अथक प्रयास की उपलब्धि है। स्थानीय लोग व दुर से आये रोगीयो के अनुसार–हॉस्पिटल परिवार की सहानुभूति पूर्ण व्यवहार व डॉक्टर आर0 के0 सिंह के अथक प्रयास को शत्–शत् नमन्।●

समतामूलक समाज के उत्थान में 'सखि रे' के बढ़ते कदम

● आनन्द प्रकाश पाण्डेय

समता मूलक समाज में किसी भी महिला के साथ घर की चहारदिवारी के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, महिला को ताने देना, गाली देना, अपमान करना, जबरन शादी के लिए बाध्य करना, पत्नी का नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना जैसे मामले घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। नारी का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुरानी संस्कृति है। यह एक विडम्बना ही है कि भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त विराधाभासी रही है। एक तरफ तो उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है तो दूसरी ओर उसे 'बेचारी अबला' भी कहा जाता है। इन दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतंत्र विकास में बाधा से ही नारी को इंसान के रूप में देखने के प्रयास कम ही हुए है। पुरूष के बराबर स्थान एवं अधिकारों की मांग ने भी उसे अत्यधिक छला है। अत: वह आज तक 'मानवी' को स्थान प्राप्त करने से भी वंचित रही है। नारी के भिन्न-भिन्न रूपों में समाज को सही मार्ग दिखाती रही है चाहे वो सीता हो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी, इन्दिरा गाँधी हों या सरोजिनी नायडू हों। सदियों से समय की धार पर चलती हुई नारी अनेक विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही है। पूज्जा, योग्या, सहचरी, सहधर्मिणी, माँ, बहन एवं अर्धांगिनी, इन सभी रूपों में उसका शोषित और दमित स्वरूप। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे नारी के कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज वह देवी नहीं बनना चाहती, वह सही और सच्चे अर्थों में अच्छा इंसान बनना चाहती है। नैतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों को नकारा नहीं जासकता। हमारे पारंपरिक चरित्र, नैतिक मूल्यों की धरोहर है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को अधिकार देने तथा उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा अन्य खामियों पर भी विचार किया जाए। इस बात को समझा जाना चाहिए कि केवल साधनों की उपलब्धि तथा महिलाओं की उन तक पहुँच से ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी बल्कि इन सबके लिए जरूरी है कि लोगों में जन-जागरूकता आवश्यक है।

समाज में भागीदारी हेतु पुरूषों को आगे करना होगा। अगर हम सहजता से उठेंगी, कोमलता के साथ आगे बढ़ेगी। केवल घरेलू हिंसा पर कानून बनाने भर से कुछ नहीं होगा। जबतक हमारी ओछी सोंच नहीं बदलेगी। जब महिला सशक्त होगी तो समाज स्वत: सशक्त हो जायेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना व उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही हमारे 'सखि री' का उद्देश्य है।

उर्मिला, ट्रस्टी
'सखि री' महिला विकास संस्थान

इन सबके इतर 'सखि री' महिला विकास संस्थान वसंतपुर की मैनेजमेंट ट्रस्टी उर्मिला ने अपने अदम्य साहस व का परिचय देते हुए कई झंझावातों से दो-चार करती हुई वर्षो से अनवरत महिलाओं के विकास व उत्थान में महती भूमिका निभा रही है। वैसे इन्हें कई संकटों का भी सामना करना पड़ा है लेकिन अपने धुन में मस्त उर्मिला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चल पड़ी तो बस चल पड़ी, उसका नतीजा यह हुआ है कि जागृति की मिशाल बन चुकी है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, जेन्डर, महिलाओं को आत्म निर्भर, कानूनी सलाह व उन्हें समाज में कैसे जीवन निर्वाह करना है? इस क्षेत्र में 'सखि री' के विकासात्मक कार्यो की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। उर्मिला के सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि 500 से अधिक परिवारों को टूटने से बचाया है। अब वह दहेज मुक्त शादी व बाल विवाद के खिलाफ अभियान युद्ध स्तर पर चला रही है। इस अभियान की पहुँच लगभग 20 गाँवों तक सकुशल जन मानस में व्याप्त है। वैसे भी ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'' को ध्येय वाक्य मानने वाली उर्मिला की प्रेरणा स्रोत उनकी माता रही है। आज की तारीख में घरेलू हिंसा बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आज महिलाओं का विकास हो रहा है। आज वो खुलकर सामने आना चाह रही है। वे पुरूषों के समान कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। ●

बहरौली पंचायत को स्वच्छ बनाना है : अजीत कुमार सिंह

● आनन्द प्रकाश पाण्डेय/अशोक कुमार तिवारी

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया, राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अघोसरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश की गुलामी से मुक्त कराया, परन्तु, 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआँ गाँधी जी ने अपने आस-पास के लोगों को स्वच्छता बनाये रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन लैट्रिन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह मंत्र को स्थापित करने की भी एक पहल करेगा। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगाँठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत (ओ.डी.एफ.; को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

भारत देश जो कभी किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कि अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो कि अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो कि अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था उस समय भारत में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और उस समय भारत में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और उस समय हमारा देश बिहार विकसित देशों की श्रेणी में आता था। गंदगी हमारे देश के लिए एक महामारी का मा कर रही है, जिस कारण आये दिन लोग बीमार पड़ रहा है और लोगों को बड़ी बीमारियाँ जैसे डेंगू अस्थमा, दिल से जुड़ी बीमारियाँ आदि हो रही है जिसके कारण हमारे देश के अस्पताल बीमार मरीजों से भरे पड़े हैं और उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पता है। हमें इस गंदगी को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि यह हमारे जीवन को ही नहीं हमारी पृथ्वी को भी तबाह कर रही है, जिसके कारण आने वाले पिढ़ी को जीने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाये और हमारा जीवन काल भी छोटा हो जायेगा, ऐसा कहना है सारण प्रमंडल में अपने विकास कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मशरक प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बहरौली के मुखिया अजीत कुमार सिंह का। आगे मुखिया अजीत सिंह ने कहा कि मोदी जी को जो स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश को विकास चाहिए तो सबसे पहले देश को साफ-सुथरा होना आवश्यक है। सारण प्रमंडल में उम्दा शौचालय, बेहतरीन संपर्क सड़कें बनाने का श्रेय बहरौली मुखिया अजित सिंह को जाता है। मुखिया ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने व जनमानस तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मोदी जी ने 9 प्रभारी लोगों को चुना है वे क्रमशः सचिन तेंदुलकर प्रियंका चोपड़ा, महेन्द्र सिंह धोनी, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, सलमान खान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम, कमल हसन, शशि थरूर आदि। मुखिया अजीत कुमार सिंह ने अपने पंचायत में जो स्वच्छता अभियान चलाया है वह सिर्फ कबिले तारीफ है, वरन, अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरनीय भी है। वार्ड वार क्रमशः मुखिया ने बारी-बारी से खुछ झाड़ू उठाकर पूरे पंचाय में सफाई अभियान चलाया। लोगों ने भी मुखिया के इस काम में पूरा सहयोग किया। अजीत सिंह ने अपने नेतृत्व में पूरे ग्रामीण जनता के साथ खुद झाड़ू लेकर आस-पास की सफाई का कमान संभाल रखा है। ●

महात्मा गाँधी जिन्होंने भारत को एक निर्मल और स्वच्छ देश बनाने का सपना देखा था वे चाहते थे कि विदेशों की तरह हमारा देश भी साफ-सुथरा दिखे, इसके लिए उन्होंने बेहतर प्रयास भी किए। उन्हीं के अधुरे सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। मोदी जी ने पूरे पंचायत में समूह में लोग जाकर श्रमदान करके हर गली-मुहल्ले की रोज सफाई रखेंगे, जिससे कि हमारा पूरा पंचायत स्वच्छ व साफ दिखाई दें।

अजीत सिंह
मुखिया, बहरौली

विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा : संजय सिंह

● आनन्द प्रकाश पाण्डेय

जिस ग्राम-स्वराज के रास्ते गाँधी हिन्द स्वराज का सपना साकार होते देखना चाहते थे, उससे हमारे गाँव कोसों दूर होते जा रहे हैं। विकास के नाम पर शहरीकरण, मशीनीकरण दैत्याकार रूप में फैलते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाँवों की रौनक कूच करती जा रही है। गाँवों में युवा शक्ति का पलायन रोकना आज एक बड़ी चुनौती है। महात्मा गाँधी अपनी ग्राम सुराज संबंधी अवधारणा को जीव पर्यन्त परिभाषितकरते रहे। उनकी दृष्टि में गाँवों की संपन्नता में ही देश की संपन्नता तथा गाँवों की स्वायत पंचायती व्यवस्था में ही देश की सच्ची प्रजातांत्रिक छवि अभिव्यक्ति पा सकती थी। उनका मानना था कि भारत चंद शहरों में

नहीं, बल्कि सात लाख गाँवों में बसा हुआ है। यही कारण था कि उन्होंने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ ग्रामोद्योग, ग्राम-स्वराज जैसी योजनाओं की परिकलपना का भी आपके रचनात्मक कार्यो में समावेश किया। यही बात गाँधी जी भी 1909 से लेकर जीवन की आखिरी साँस तक कहते रहे। स्पष्टत: गाँवों में बसने वाले

✯ ग्राम पंचायत राज बिठुना में कराये गए कार्यों पर एक नजर :-

☞ राजस्व ग्राम बिठुना के जुनेदपुर वार्ड नं. 4 में रवौली मोड़ से लेकर विद्या सिंह के घर तक पी.सी.सी. 125 फीट।

☞ बिठुना सुदामा माँणी के घर से उदय सिंह के घर तक पी.सी.सी. 1150 फीट।

☞ बिठुना वार्ड नं.-7 में काशी सिंह के बथान से लेकर शिवजी ठाकुर के बथान के आगे तक पी.सी.सी. 900 फीट।

☞ योगेन्द्र सिंह के घर से बड़का गाँव सीमा तक मिट्टीकरण व ईटकरण 600 फीट।

☞ बिठुना राजीव गाँधी सेवाश्रम से नंद किशोर पाण्डेय के खेत तक मिट्टीकरण व ईटकरण 2300 फीट।

☞ सिघौली मध्य विद्यालय से सरहरी सीमा तक मिट्टीकरण व ईटकरण 2200 फीट।

☞ द्वारका राउत के घर से रेखा सिंह के खेत तक पी.सी.सी. 700 फीट।

☞ रतौली लुकमाता के स्थान से लेकर शिव प्रसाद के घर तक पी.सी.सी. 400 फीट।

☞ बलराम पाण्डेय के घर से मस्जिद तक 125 फीट पी.सी.सी.।

☞ बबन प्रसाद के घर से नथुनी प्रसाद के घर तक पी.सी.सी. 100 फीट।

☞ बिठुन देवी माई के मंदिर का जीर्णोद्धार।

☞ बिठुन देवी मंदिर के पास सौर पानी टंकी

का निर्माण विशेष प्रयास से संपन्न।

☞ पूर्व से अबतक इंदिरा आवास लगभग 300

☞ वृद्धा पेंशन लाभुक लगभग 400

☞ जल नल योजनान्तर्गत वार्ड संख्या-4, 7, 8 में कार्य संपन्न।

☞ वृक्षारोपण 2 यूनिट।

☞ बिठुना 7 नं. वार्ड में तथा 2 में (हरिजन टोली) आंगनबाड़ी।

पंचायत की जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। पंचायत की सभी समस्याओं से निजात दिलाने का मैं सदैव तत्पर रहूँगा। जिस उम्मीद से सम्मानित जनता ने मुझे चुना है, उसके लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। 24 घंटों आम जनता के लिए मैं मौजूद हूँ। उनके हर सुख-दु:ख में साथ हूँ।

संजय सिंह
मुखिया, ग्राम पंचायत राज बिठुना

भारत की समस्याओं का समाधान गाँधी परिकल्पित ''ग्राम सुराज को मूर्त करके ही हो सकता है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत राज बिठुना के मुखिया संजय सिंह का यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि मैं अपने वादे के अनुसार 24 घंटे जनता की सेवा में प्रस्तुत है। हर बुनियादी सुविधाएँ हर उचित हकदार तक पहुँचे तब जाकर पंचायत विकसित होगा।

सड़कें, वृक्षारोपण, तालाब, पी.सी.सी., मिट्टीकरण, ईटकरण, वृद्धापेंशन, कबीर अत्येष्टि सहित कई योजनाओं का लाभ आम जनता को मयस्सर हो रहा है। जब गाँव आत्मनिर्भर हो जायेगा तब ग्राम स्वराज का सपना पूरा हो पायेगा। पंचायत का चहुँमुखी विकास करना ही हमारा लक्ष्य है। जिस विश्वास के साथ मुझे जनता ने चुना है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। चाहे कोई भी पर्व हो या त्योहार मुखिया बिठुना उन्हें आर्थिक मदद व वस्त्र मुहैया कराते हैं। किसी के धार में शादी हो तो आर्थिक मदद और राशन का भी इंतजाम करते है। कहते हैं कि गरीबों की मदद करने से मेरे आत्मा को शुकुन मिलता है। ●

खजूरा पंचायत का विकास हमारी प्राथमिकता : मृदुला

● आनन्द प्रकाश पाण्डेय/अशोक कुमारी तिवारी

'नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य? प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल गुदड़ी में रखती चुन-चुन कर बड़े कीमती लाल।'' उपरोक्त पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, मुखिया ग्राम पंचायत राज खजूरी मृदुला देवी पर। पंचायत में विकास की गंगा बहाने का उद्त दीख रही है। यह श्रेय पंचायत की मुखिया जनता जनार्दन दोनों को जाता है, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उचित व्यक्तियों तक पहुँचाया जा रहा है।

अपने व्यक्तिगत विवेक से पंचायत में समता मूलक और समानता मूलक समाज के मद्देनजर सरकारी योजनाओं का वितरण करती है, जिसमें पंचायत में न केवल उनकी ईमानदारी झलकती है, बल्कि पंचायत की हर योजनाओं में पारदर्शिता रहती है, जिससे पंचायत की जनता खुश रहतीहै। मुखिया कुमुद देवी का यह कब्जा अतिशयाक्ति न होगी कि मैं अपने वादे के अनुसार 24 घंटे जनता की सेवा में प्रस्तुत हूँ। हर बुनियादी सुविधाएँ हर उचित हकदार तक पहुँचे तब जाकर पंचायत का विकास अग्रेतर होगा। चुनांचे, दूसरी ओर मुखिया प्रतिनिधि सुनील राय काखजूरी पंचायत के विकास में सराहनीय प्रयास के लिए पंचायतवासी उनके कायल है। किसी की बेटी की शादी हो या बिमारी आ अन्य परेशानियों में प्रतिनिधि सुनील राय निजी रूप से उनकी हर संभव मदद को प्रयत्नशील दीखते हैं। मुखिया खजरूी अपने पंचायत में विकास की नयी सोंच रखती है। विकास उनका मुख्य मुद्दा होता है। ●

मेरा सदैव यह प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को मान-सम्मान मिले। सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिले इसके लिए प्रयत्नशील रहती हूँ।

मृदुला देवी, मुखिया
ग्राम पंचायत राज खजूरी

खजुरी पंचायत के चहुंमुखी विकास हेतु हम सभी तत्पर हैं। पंचायत में विकास हो इसके हर संभव प्रयास जारी है। आम जनता के सहयोग से पूरे पंचायत को विकसित बनाने हेतु तत्पर है।

सुनील, मुखिया प्रतिनिधि

☆ ग्राम पंचायत राज खजूरी, मशरक में कराये गए कार्यो पर एक नजर :

☞ विशुनपुरा में 'शुकन महतो के घर से महावीर स्थान तक 2100 फीट पी.सी.सी.।
☞ सरदार गंज में भुटेली महतो के घर से नेमी राय के घर तक 1000 फीट पी.सी.सी.।
☞ शंकर राय के घर से लालबाबू राय के घर तक 1000 फीट पी.सी.सी.।
☞ मदन महतो के बथान से तीन मुहानी तक पी.सी.सी. 500 फीट।
☞ विशुनपुरा प्रा. वि. सरदारगंज प्रांगण में मिट्टीकरण व ईटकरण।
☞ नया प्राथमिक विद्यालय में मिट्टीकरण व ईटकरण।
☞ विशुनपुरा सहित पूरे पंचायत में लगभग 22000 फीट मिट्टीकरण।
☞ शेरू कहाँ महावीर स्थान में मिट्टीकरण।
☞ विशुनपुरा, शेरूकहां व पकड़ी श्मशान में मिट्टीकरण
☞ पकड़ी सामुदायिक भवन परिसर में मरम्मती, ईटकरण वे चबूतरा निर्माण
☞ विशुनपुरा में दो पुलिया निर्माण, मिट्टीकरण 3000 फीट खजूरी गाँव से नहर तक
☞ वृक्षारोपण लगभग 30 यूनिट व वृक्षारोपण लाभुक 250
☞ कबीर अन्त्येष्ठि लाभुक 50 व आवास योजना के लाभुक लगभग 26
☞ नल जल योजनान्तर्गत वार्ड नं. 6, 10, 14, 1, 2 में कार्य संपन्न
☞ शौचालय निर्माण कार्य जारी

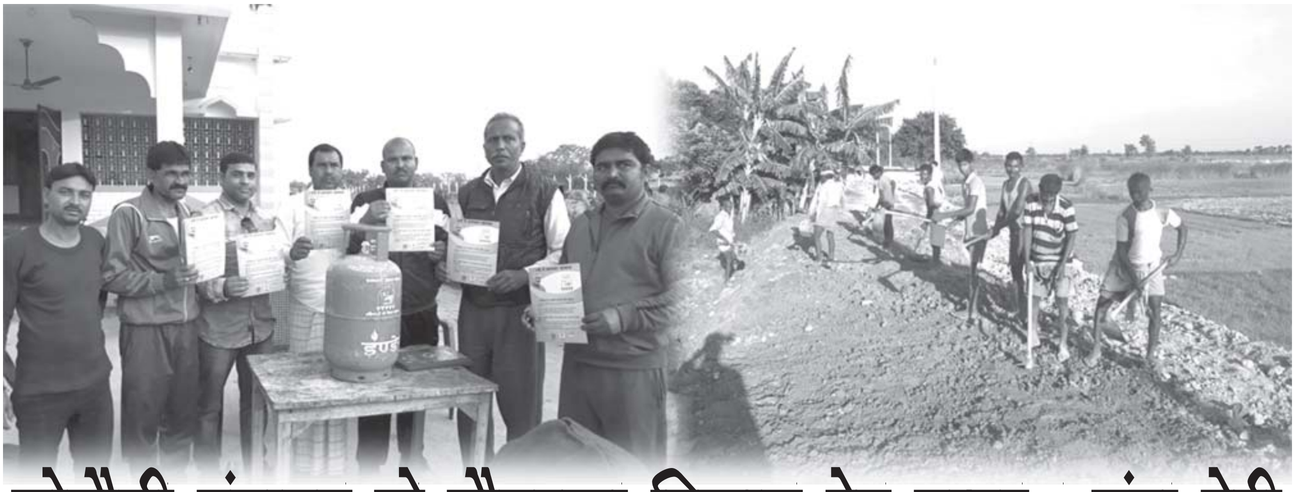

सोनौली पंचायत के चौतरफा विकास हेतु तत्पर : चंपा देवी

● आनन्द प्रकाश पाण्डेय/अशोक कुमारी तिवारी

कई ऐसे गाँव है, जो डिजिटल इंडिया के दौर में विकास में पिछड़े हुए थे। पंचायती राज लागू होने के बाद उन गाँवों में विकास की रोशनी पहुँचनी शुरू हो गई है। कई पंचायत में जनप्रतिनिधियों की मेहनत व जनता के लिए कुछ करने की लगन से बदलाव की बयार दिखनी शुरू हो गई है। इन्हीं में से शुमार है सोनौली पंचायत का। पंचायत राज व्यवस्थान्तर्गत कई

अभी तक जो भी काम हुआ है नाकामी है। अभी बहुत सा कार्य होना बाकी है। लोगों के जागरूक होने के कारण पंचायत में विकास की बयार बह रही है। आम सहयोग से पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदलना ही हमारा उद्देश्य है।

चंपा देवी, मुखिया

गरीब-गुरबों के चाहे वे हिन्दू या मुस्लिम छठ होली व ईद के अवसर दो बार वस्त्र व अन्य वस्तुएँ दी जा रही है। किसी के भी मृत्यु पर (गरीबों को) नगदी व अनाज दिया जाता है। गरीब बेटियों की शादियों में सहयोग राशि व अनाज की भी व्यवस्था दी जाती है। सोनौली पंचायत का चहुँमुखी विकास हो इसके लिए चौबीसों घंटों प्रयासरत हैं। हर लाभुक तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले ऐसा प्रयास हम सभी का रहता है।

संतोष परमार, मुखिया प्रतिनिधि

✯ सोनौली पंचायत में कराये गये कार्यों पर एक नजर :-

- ☞ मंगुरहां सीमा से विजेन्द्र तिवारी के घर तक ईंटकरण व पी.सी.सी. लगभग 2 किमी.।
- ☞ गोढ़ना तुरहा टोली ईंटकरण लगभग 1600 फीट।
- ☞ चैनपुर चमरियां मधुसुदन कुंवर के घर से रमेश शुक्ल के घर तक ईंटकरण 2200 फीट।
- ☞ प्रो. राजेश्वर सिंह के घर से सोनौली खार तक ईंटकरण लगभग 22 फीट।
- ☞ अंसारी गाछी से बलुआ तक मिट्टीकरण व ईंटकरण लगभग 1300 फीट।
- ☞ पंचरूखवा में नंदकिशोर सिंह के घर से शिव मंदिर तक मिट्टीकरण व ईंटकरण लगभग 400 फीट।
- ☞ नरेश सिंह के घर से सिरसा जलालपुर सीमा तक ईंटकरण लगभग 2400 फीट।
- ☞ इंदिरा आवास के लाभुक पूर्व में 250 वर्तमान में 100 ।
- ☞ कबीर अन्त्येष्ठि के लाभुक 100 व वृद्धा पेंशन लगभग 800 ।
- ☞ नवसृजित विद्यालय पचरूखवा व सिकटी भीखम में मिट्टीकरण।
- ☞ चौदहवें वित्त योजनान्तर्गत लगभग 350 चापाकल।
- ☞ सात श्मशानों में मिट्टीकरण व सार्वजनिक स्थलों पर चबूतरा निर्माण।
- ☞ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनौली के प्रांगण में मिट्टीकरण।
- ☞ खाद्य सुरक्षा के लाभुकों की संख्या लगभग 2686 ।
- ☞ स्वच्छ जल योजनान्तर्गत क्रमशः वार्ड नं.-6, 11, 15 में कार्य संपन्न व वार्ड संख्या-1, 7, 8, 9, 13 में प्रगति पर।

समस्याः पूर्व में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र की जाँच करायी जाय व आम जनता की सुविधा के मद्देनजर अधूरा कार्य को पूर्ण किया जाये।

गाँवों में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुँची है। सोनौली पंचायत में आजादी के बाद सरकार की योजनान्तर्गत किसी भी योजनाओं से छिटपुट कार्य ही हो पाया था। चुनांचे आज सोनौली पंचायत में मिट्टीकरण व ईंटकरण के बाद कई आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है। सोनौली पंचायत लगभग सभी संपर्क मार्गो से जुड़ चुकी है। इस पंचायत में मिट्टीकरण व ईंटकरण के कई विकास कार्य हुए हैं। मुखिया कहती है कि जल्द ही पूरा पंचायत सड़क में बदला सा दिखेगा। पूर्व में यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जाँच करायी जाय जो वर्षो से अधूरा पड़ा है। विभागीय तुमाफेरी व भ्रष्टाचारियों के कारण यह निर्माण अधर में है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बयार बहे इस उद्देश्य से राज्य सरकार मूलभूत सुविधाएँ देने की बातें करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएँ कहाँ तक पहुँची है इसी को जानने केवल सच टीम कई माह से गाँवों का दौरा कर रही है। निश्चित तौर पर गाँवों में विकास की बयार बहती दिख रही है। दौरा कर रही है। निश्चित तौर पर गाँव में बदलाव की बयार दिख रही है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार भी मिल रहे है जिससे पलायन कम हुआ है। ●

छठ पूजा की महिमा का गुणगान अब 54 फ्रांसीसी भाषाई देशों में

● दीपनारायण सिंह दीपक/धर्मेन्द्र सिंह

बिहार के महापर्व छठ की महिमा ही निराली है। सदियों से बिहारवासियों के मन में अपनी मिट्टी और संस्कृति के प्रति लगाव और महान आस्था का संगम है ये त्यौहार। यह पर्व उन तमाम बिहारवासियों के लिए खास हो जाता है, जो इस वक्त बिहार की पावन धरा पर कार्यरत ना होकर देश-विदेश के किसी और छोर पर होते हैं। ऐसी ही कुछ निराली बात बिहार कैडर के आई.पी.एस. अधिकारी श्री कुमार आशीष के साथ सन् 2006-2007 में यहाँ के 9000 किलोमीटर दूर फ्रांस में हुई थी। बता दें कि श्री आशीष भारतीय पुलिस सेवा के 2012 बैच के अधिकारी है और अब तक मधेपुरा, नालंदा तथा वर्तमान में किशनगंज एस. पी. के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और अपने सामुदायिक पोलिसिंग के विभिन्न सफल प्रयोगों के लिए बिहार सहित पूरे देश में जाने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने फ्रेंच भाषा में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. भी किया है। पुलिससिंग के साथ पठन-पाठन और लेखन में भी उनकी व्यापक रूचि रही है और अबतक कई लेख विभिन्न जगहों से प्रकाशित हो चुके हैं। यो बताते हैं कि आज से 12 साल पूर्व जब वो फ्रांस में स्टडी टूर पर गए थे, तब वहाँ एक संगोष्ठी में कुछ फ्रेंच लोगों ने उनसे बिहार के बारे में कुछ रोचक और अनूठा बताने को कहा, तब उन्होंने बिहार के महापर्व छठ के बारे में विस्तार से उनलोगों को समझाया। फ्रेंच लोग काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इस विषय पर फ्रांस के साथ फ्रेंच बोलने-समझने वाले अन्य 54 देशों तक भी इस पर्व की महता और पावन सन्देश पहुँचाना चाहिए। उनकी प्रेरणा से कुमार आशीष ने वापस स्वदेश लौटकर इस पर्व के बारे में और गहन अध्ययन एवं बारीकी से शोध कर छठ पर्व को पूर्णत: परिभाषित करने वाला एक लेख ''Chhath Puja Faderation due Dieu Soleil'' लिखा जो कि भारत सरकार के अंग भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् दिल्ली के द्वारा फ्रेंच भाषा में ''Rencontreavec I'Inde'' नामक किताब में सन् 2013 में प्रकाशित हुई।

इस लेख में श्री आशीष ने छठ पर्व के सही पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण कर फ्रांसीसी भाषा के लोगों के लिए इस महापर्व की जटिलताओं को समझने का एक नया आयाम दिया है-शुरूआत में ये बताते है है कि छठ मूलत: सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक-व्यवहारिक कठोर शुद्धता रखी जाती है। छठ शब्द सिर्फ दिवाली के छठे दिन का ही द्योतक

नहीं है, बल्कि ये इंगित करता है कि भगवान सूर्य की प्रखर किरणों की सकारात्मक ऊर्जा को हठ योग के छ: अभ्यासों के माध्यम से एक आम आदमी कैसे आत्मसात कर सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकता है? इस पर्व के हर छोटे से छोटे विधान की यौगिक और वैज्ञानिक महता है। मसलन, साल में दो बार क्यों मनाया जाता है यह पर्व? सूर्य की उपासना के व्रत जल में खड़े रहने का आधार है? डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे का विचार है? सूप और दौरो का पूजा में क्या महत्व है? यह पूजा ऋग्वेद काल से शुरू हुई। महाभारत में धौम्य ऋषि के कहने पर द्रौपदी ने पाँचों पांडवों के साथ छठ पर्व कर सूर्य की कृपा से अपना खोया राज्य वापस प्राप्त किया था। बिहार में इसका प्रचलन सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण से शुरू होना माना जाता है। बिहार के तीनों बड़े प्रभागों यथा, मगध भोजपुर और मिथिला में बड़े धूम-धाम से यह पर्व मनाया जाता है। मिथिला के क्षेत्र में 'कोसी भरना' भी किया जाता है, जिससे मानव शरीर के पंचतत्व के प्रतीक रूप में पाँच गन्ने एक साथ लगाये जाते है और उन्हें ऊष्मा प्रदान करने के लिए चारो तरफ से मिट्टी के दिए लगाये जाते हैं। जिस घर में नयी शादी या नए बच्चे का आगमन होता है। वो लोग बड़ी निष्ठा से ये रीति निभाते हैं। बिहार के सिकंदरा प्रखंड जमुई जिले के रहने वाले आई.पी.एस. श्री आशीष को फ्रांस में हुई उसी मीटिंग में बिहार में रहकर बिहार के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा मिली थी, जब एक फ्रेंच यूद्धा मादाम निकोले ने उनसे बिहार के पिछड़ेपर का कारण पूछा था और तब तमाम तथ्यों में एक ये भी तथ्य उभर कर सामने आया था कि बिहार के प्रतिभाशाली लोग भारत सहित और अन्य विदेशी जगहों पर अपने-अपने क्षेत्रों में हमेशा आगे रहते हैं पर बिहार वापस लौटना पसंद नहीं करते, इस कारण बिहार से प्रतिभा का पलायन रूक नहीं रहा है और परिणामस्वरूप बिहार पिछड़ा राज्य बना रहता है। इस तथ्य को चुनौती के रूप में लेते हुए श्री आशीष फ्रांस से लौटकर वापस आये और UPSC की कठिन परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन कर अपने गृह राज्य में सेवा देने आये। मोतिहारी, दरभंगा, बलिया, बेगूसराय, मधेपुरा, नालंदा और अब किशनगंज, जहाँ भी उन्होंने कार्य किया है, अपने बिहार की मिट्टी के प्रति सच्ची आस्था और जरूरतमंदों को त्वरित न्याय प्रदान करने का कार्य कर लोगों को दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सामुदायिक-सांस्कृतिक कार्यो से ये लगातार क्रूर पुलिसिंग का चेहरा बदल कर पब्लिक-फ्रेंडली पुलिसंग कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ अपराध नियंत्रण में काफी सहायता मिली है। वरन पुलिस और सरकार में आम लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। अब समय आ गया है कि पूरे विश्व में जहाँ भी बिहारी डायस्पोरा के लोग है, इस अवसर पर अपने-अपने तरीके से आगे आये और बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि, विरासत और बुद्धत्व से पूरे विश्व को जागृत करे। ●

होमियोपैथी में आत्महत्या रोकने की दवा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार आत्महत्या करने का प्रमुख कारण जीवन के प्रति निराशा है। आत्महत्या के अधिकांश प्रकरण किशोरावस्था में अधिक सामने आते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि बचपन या युवावस्था में आत्महत्या की घटनाएं नहीं होती। हां वृद्धावस्था मे आत्महत्या के किस्से सुनने को कुछ कम ही मिलते है। चिकित्सा विज्ञान में आत्महत्या करना या आत्महत्या का विचार मन में उठना या दूसरों की हत्याएं कर देना या मन में ऐसे विचारों का पैदा होना भी रोग की श्रेणी में ही आता है। इस प्रवृत्ति को दूर करने व मानस बदल डालने की दृष्टि से होमियोपैथी बहुत कामयाब रही है। यहां इस दृष्टि से कुछ दवाओं का संकेत किया जा रहा है:-

☞ **औरम मेटालिकम**
(Aurum Metalicum) :- इस दवा में मानसिक अवसाद अधिक दिखलाई देता है। इसके रोगी में आत्महत्या कर लेने की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है वह अपने जीवन में निराश होकर ऐसा सोचा करता है कि इस प्रकार के जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जरा सी सुविधा मिलने पर ही आत्महत्या कर लेते है।

☞ **नाजा (Naja Tripudians) :-** यह दवा कोवरा सर्प के विष से बनाई जाती है। इसका रोगी भी आत्महत्या करना चाहता है पर मरने से डरता भी है। इस दवा के निर्वाचन के लिये हमें रोगी की अन्य बातों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। नाजा के रोगी पर रोगों का आक्रमण प्राय: बांयी ओर अधिक होता है और इसका मुख्य केन्द्र हृदशूल के साथ व्याकुलता व मृत्यु भय रहता है।

☞ **अर्जेन्टम नाइट्रिक्म**
(Argentum Nitricum) :- यह गरम प्रकृति की दवा है। इसका रोगी अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने का विचार करता है। इसके रोगी का मन किसी काम में नहीं लगता, अक्सर दिमाग का काम करने वालों के मन में जब वैराश्य भाव पैदा हो जाता है तो इस दवा से उनको विशेष लाभ मिलता है।

☞ **प्लैटिना (Platina) :-** इसका रोगी हमेशा दूसरों की हत्या करने की योजना बनाता रहता है और अन्य व्यक्तियों से अपने को सदा बहुत श्रेष्ठ समझता है। अपनी बड़ाई आप करता रहता है, दूसरों से घृणा इसके रोगी को भूत-प्रेत से भी बहुत डर लगता है। कभी-कभी इतना उदास हो जाता है कि मृत्यु को अपने समीप आते देखने लगता है।

☞ **आयोडम (Iodium) :-** यह भी गरम प्रकृति की दवा है। इसके रोगी व्यक्ति में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। महत्वपूर्ण लक्षण यही है- रोगी को भूख बहुत लगती है। फिर भी मांसक्षय होते जाना यक्ष्मा जनित दशा। रोगी का रंग सांवला, बाल काले होते है और इसके रोगी कण्ठमाला रोग से भी प्राय: ग्रसित रहते है। इसको भी उच्च शक्ति में प्रयोग करने से ज्यादा लाभ मिलता है।

☞ **एल्युमिना (Alumina) :-** इसका रोगी जब भी खून देखता है तो उसके मन में अपनी हत्या कर डालने का भाव पैदा हो जाता है। इसके रोगी को लगता है कि समय बहुत धीरे-धीरे बीत रहा है। इसके रोगी की रूधिर गति शिथिल होती है, सर्दी के दिनों में उसके हाथ-पैर बहुत ठण्डे हो जाते है। जैव ताप की कमी।

☞ **एक्टिया रेसिमोसा उर्फ सिमिसिफ्युगा (Actea Racemosa/Cimicifuga)** :-इस दवा के रोगी भी आत्महत्या की प्रवणता रहती है, पर यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह दवा महिलाओं के लिये ज्यादा लाभदायक है। इसकी रोगिणी हिस्टेरिया प्रधान होती है। उसका मासिक धर्म अनियमित रहता है।

☞ **नेट्रम सल्फ**
(Natrum Sulphuricum) :- रोगी अपने जीवन से बहुत उदास रहता है और अपने को गोली से मार डालने की प्रबल इच्छा उसके मन में उठती रहती है। इस भावना पर वह बड़ी मुश्किल से काबू में रख पाता है। दिमाग पर कभ लगे आघात का दुष्परिणाम।

☞ **एन्टिम क्रूड (Antim Crud) :-** इसके रोगी में भी अपने को गोली मार देने की इच्छा पैदा हो जाती है। सर्दी बहुत लगीत है। बहुत ज्यादा उदासी व उसके साथ रोते रहना घोर निराशा के कारण डूब कर मर जाना चाहती है। मुंह भारी किये पड़े रहना, बोलना नहीं चाहती, दूसरा उससे बात करे यह भी पसंद नहीं होता। अपने जीवन से घृणा।

☞ **पल्सेटिला (Pulsatila) :-** इसकी रोगिणी भी आत्महत्या को करना चाहती है पर मरने से डरती है। कायर, भूत, प्रेतों से डर, परिवर्तनशील रोग व मिजाज इसकी रोगिणी मोटी व मांसल होती है। सरलतापूर्वक रोने लग जाती है, बिना रोये अपने उपसर्ग नहीं बता पाती। नम्र, शरीर व डरपोक रोगिणी होती है। सहज ही हंस व रो देने वाली गर्म प्रकृति की रोगिणी।

✯ **विचित्र रोगों में लाभदायक है होमियोपैथी** :- विचित्र रोग शीर्षक पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि विचित्र रोग क्या है? विचित्र रोग ऐसा रोग है जिसके बारे में सामान्य: यह माना जाता

है कि यह कोई रोग नहीं है, व्यक्ति मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, यह मन का भ्रम है, ग्रसित व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं रहता है, ग्रसित व्यक्ति की फालतू की सोच की उपज है। होमियोपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी इस प्रकार के लक्षणों को रोग नहीं माना जाता है, इसके लिए मनोचिकित्सा करवाने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके शरीर के अंदर चीटियां या कीड़े चल रहे है, शरीर में गर्म या ठंडी सूई चुभाई जा रही है, मुंह पर मकड़ा का जाला लगा हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस प्रकार के रोगों के लिए होमियोपैथी में सफल इलाज है, आज है इन्हीं बीमारियों के इलाज पर चर्चा करूंगा। आगे विभिन्न प्रकार के विभिन्न रोगों के लिए होमियोपैथी दवाओं का वर्णन है, जिनके प्रयोग से फायदा उठाया जा सकता है।

☞ अगर कोई पुरूष या महिला मन में यह धारणा बना लेता/लेती है कि शादी करना गलत है, इसलिए शादी से इनकार करता/करती है, विपरीत लिंग से दूर रहता/रहती है तो- पल्सेटिला 30 फायदेमंद होता है।

☞ स्त्री या पुरूष द्वारा विपरीत लिंग को देखते या सोचते ही चूमने या आलिंगन की तीव्र इच्छा होने पर, इसे दूर करने के लिए- ऐगारिकस मस्केरियस 6, 30, 200 का प्रयोग फायदेमंद होता है।

☞ अगर गाना सुनने से किसी को कष्ट होता है या कोई तकलीफ उभर आती है, तो - एम्ब्रा ग्रीशिया 6 का सुबह में एक खुराक एक सप्ताह के अंतराल में मात्र चार बार उपयोग करना चाहिए।

☞ अगर कोई व्यक्ति बिना किसी बात के अनावश्यक रूप से हंसता है या हंसी की बात पर गंभीर हो जाता है, तो एनाकार्डियम 6, 30, 200 का प्रयोग फायदेमंद होता है।

☞ अगर कोई स्त्री या पुरूष बिना मतलब के बार-बार हाथ धोते रहते है या बहुत देर तक रगड़-रगड़ कर साबुन लगाते रहते है, तो-कैम्फर 30 सीफीलीनम C.M. के प्रयोग से यह आदत छूट जाती है, ठीक होने के बाद उन्हें स्वयं महसूस होने लगता है कि उनकी यह आदत बुरी थी। ऐसी स्त्री या पुरुष को यह महसूस होता है कि उनके हाथ या पैर धोने के बाद भी गंदे ही है, इसलिए वे बार-बार अपने हाथ या पैर को रगड़-रगड़ कर साफ करते रहते है।

☞ अगर बच्चा किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा अपनी ओर देखने या छूने से रोने लगता है या गुस्सा हो जाता है, तो एन्टिमोनियम क्रूडम 3, 6, 30,200 का प्रयोग फायदेमंद होता है।

☞ अगर स्त्री या पुरुष बच्चों की तरह बेमतलब की बातें बोलते रहते है या बिना मतलब बड़बड़ाते रहते है, तो एपिस मेलिफिका 30, 200 का प्रयोग लाभप्रद होता है।

☞ अगर समय धीरे बीतता मालूम हो, तो - एल्युमिना 30, 200 का प्रयोग लाभप्रद होता है।

☞ अगर ऐसा महसूस होता है कि समय जल्दी-जल्दी बीत रहा है, तो काकुलस इंडीकस 3, 6, 30 या थेरीडियन 30, 200 का प्रयोग लक्षणानुसार फायदेमंद होता है।

☞ अगर किसी को महसूस हो कि उसके शरीर के अंदर यथा पेट, हाथ या पैर में कहीं कोई कीड़ा घुसा हुआ है और हरकत कर रहा है या कुलबुला रहा है, तो क्रोकस सैटावक्स 200 फायदेमंद है।

☞ व्यक्ति जब चलता है तो ऐसा महसूस करता है, जैसे वह जमीन पर नहीं आसमान में चल रहा है और जब लेटता है तो ऐसा महसूस करता है कि वह बिछावन पर नहीं आसमान में लटक रहा है, ऐसी मनोस्थिति में-लैक कैनाइनम 30, 200 का प्रयोग लाभप्रद होता है।

☞ अगर किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चारों ओर पिन या आलपिन बिखरे पड़े है, उसे डर लगता है कि कही पिन उसे चुभ न जाए, इस भय से वह पिन या आलपिन ढूंढ़ा करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, पिन या आलपिन नहीं मिलने पर भी उसे विश्वास नहीं होता है कि पिन या आलपिन वहां नहीं बिखरा है। ऐसा काल्पनिक विचार या भ्रम-साइलीशिया 12 एक्स, 200 एक्स के प्रयोग से दूर हो जाता है, साथ ही इससे जुड़ी अन्य कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी समाप्त हो जाती है।

☞ अगर कोई बच्चा दिन में हंसता-खेलता रहे, लेकिन रात होते ही रोना-चिल्लाना आरंभ कर दे, तो-साइप्रिपेडियम प्यूबिसेन्स 6, 30 फायदेमंद होता है।

☞ अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर कांप रहा है, किन्तु बाहर से देखने पर शरीर का कांपना मालूम नहीं होता है, तो-सल्फ्यूरिक एसिड 30, 200 फायदेमंद होता है।

☞ अगर बहुत ठंड मालूम होती है, शरीर के किसी भी स्थान के मांसपेशी या हाथ-पैर थरथराता, सिर हमेशा कांपता है, थरथराहट या कंपन जागते समय होती है किन्तु सोते ही ही यह बंद हो जाती है, तो-एगारिकस मस्केरियस 3, 6, 30, 200 फायदेमंद होता है।

☞ जाग्रत अवस्था में बिछौने की चादर खुरचते रहने पर-बेलाडोना 30, 200 या हायोसायमस 200, 1 एम फायदेमंद होता है।

☞ अगर ऊपर की ओर देखने पर चक्कर आ जाता है, तो साइलीशिया 12 एक्स, 30 एक्स, 200 एक्स फायदेमंद होता है।

☞ जीभ के पिछले हिस्से पर एक बाल लगा होने का अनुभव होने पर, जबकि वास्तव में जीभ पर बाल नहीं होता है, तो नेट्रम म्यूर 6 एक्स, 12 एक्स फायदेमंद होता है।

☞ निगलते समय गला में मछली का कांटा या तिनका अटका हुआ महसूस होने पर-ऐलूमिना 30 या हिपर सल्फ 6ए 30 लक्षणानुसार प्रयोग फायदेमंद होता है।

☞ ऐसा महसूस होता है कि मुंह पर मकड़ी का जाला लिपटा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है तो-एलुमिना 30, 200, ग्रेफाइटिस 5, 30, 200 या बोरेक्स 6, 30, 200 का लक्ष्णानुसार प्रयोग लाभप्रद होता है।

☞ अगर किसी को कपड़ा यथा रूमाल, कॉलर इत्यादि चबाने की आदत है, तो-एल्युमिना 6, 30, 200 फायदेमंद होता है, इसके प्रयोग से यह आदत छूट जायेगी।

☞ अगर किसी व्यक्ति को खड़े रहने पर नीद आती है, किन्तु बिछावन परलेटते ही नींद गायब हो जाती है, तो-कोका 3, 6, 30 फायदेमंद होता है।

☞ अगर किसी की नींद प्रतिदिन रात में तीन बजे खुल जाती है, सोते-सोते चौक उठता है, स्वप्न की वजह से नीद खुल जाती है, तो-कॉफिया क्रूडा 200 की एक खुराक प्रत्येक तीसरे दिन गत को सोते समय लेने पर उपरोक्त समस्या दूर जो जाती है।

☞ अगर किसी को हमेशा जम्हाई आते रहती है, तो-एसिड साइट्रिकम मदर टिंचर का प्रयोग फायदेमंद होता है।

☞ अगर कोई स्वप्न में यह देखता है कि घर में चोर घुस गया है और जागने पर वह घर में उसे ढुंढ़ता है, तो-नेट्रम म्यूर 6 एक्स, 12 एक्स, 200 एक्स, 6, 30, 200 या सोरिनम 30, 200- लक्षणानुसार फायदेमंद होता है। लक्षणानुसार का अर्थ व्यक्ति में जिस दवा के ज्यादा लक्षण पाये जाएं।

☞ अगर किसी बालक/बालिका या युवक/युवती को अधिक पढ़ने के कारण, रात-रात भर जग कर पढ़ाई करने के कारण पागलपन या मानसिक उन्माद हो जाता है, तो-स्ट्रेमोनियम 6, 30, 200 के प्रयोग से दूर हो जाता है।

☞ आंख के सामने काली मक्खियां, काला दाग, कुहरा या मकड़ा का जाला दिखाई देता है, एक चीज का दो चीज दिखाई देता है, पढ़ने में परेशानी होती है, अक्षर मानों हटते जाते है, विभिन्न तरह के रंग और चेहरा दिखाई देता है, आंख की पुतली इधर-उधर घुमाता है, आंखे बार-बार खोलता और बंद करता है, तो-ऐगारिकस मस्केरियस 3, 6, 200-फायदेमंद होता है।

☞ अगर किसी का स्वर लोप हो जाए और उसे शब्दों का अर्थ ज्ञान न रहे, तो-काली ब्रोम 30-का प्रयोग फायदेमंद होता है।

होमियोपैथी दवाएं उपरोक्त बीमारियों में अचूक रूप से फायदा करती है, जरूरत है सिर्फ सही दवा का चुनाव कर प्रयोग करने की। सामान्यत: उपरोक्त बीमारियों को बीमारी नहीं माना जाता है।● **(साभार- होमियोगगन)**

कोचिंग संचालक को मिली धमकी

● हरि जी पाण्डेय

ये कोई नई बात नहीं है, जब आप शहर में किसी कोचिंग संचालक, व्यापारी या अन्य प्रतिष्ठित लोगों को धमकियाँ मिली हो उनमें मारपीट, गाली-गलौज की गई। दिन-प्रतिदिन असमाजिक तत्वों का बोल बाला शहर में बढ़ते जा रहा है, जिससे आम जनजीवन के साथ अच्छे शिक्षकों, व्यापारियों डॉक्टरों इत्यादि में भय का माहौल उत्पन्न हुआ है। बीते दिनों शहर के लगभग बीचो-बीच स्थित The Act English Classes के संचालक शहनवाज अख्तर सर को धमकी दी गई कि यहाँ से अपना कोचिंग बंद करें। जिस तरह से उनको धमकी दी गई, उससे लगता है, जैसे एक बार शहर में मानो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई हो। एक शिक्षक कभी किसी धर्म या जाति के बंधन में बंधकर शिक्षा नहीं प्रदान करता, सबको समान भाव से शिक्षा देते हैं एवं उनके व्यवस्थित समाज के निर्माण की कामना करते हैं, लेकिन जब उसी समाज निर्माण पर अगर जातिगत या धार्मिक हमले होने लगे तो वास्तव में यह चिंताजनक है। फिलहाल यही शहर अपने जिले का जिला मुख्यालय भी है, और यहाँ तमाम बड़े, अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न जगहों में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार की दृष्टि से भी आते हैं। लेकिन उनको यहाँ आने के बाद अव्यवस्था होने लगती है, असमाजिक तत्वों का प्रहार होने लगता है, इससे वो हमेशा घबराए हुए एवं तनाव महसुस करते हैं। लोगों से भय खत्म करने के लिए निश्चित ही जिला प्रशासन को अहम भुमिका निभानी होगी ताकि यहाँ के बच्चे-बच्चियाँ बिना भय के कोचिंग, स्कूल, कॉलेज जा सके। हर बार प्रशासन के नाकामी का खामियाजा आम जनजीवन को भुगतना पड़ता है, आज भी इन शहर के कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बाहर असमाजिक तत्व का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे छात्राएं खासे परेशान रहती है और इससे संचालक भी तनाम महसुस करते है। कई बार तो न सिर्फ यहाँ के कोचिंग चलाने वाले संस्थानों के निदेशक को धमकी मिली है, बल्कि उन्हें गोली भी मार दी गई है। इससे कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी साफ झलकती है। हद तो तब हो जाती है जब किसी पर धार्मिक हमले किये जाए, इससे जिला प्रशासन को हमेशा सचेत रहने की जरूरत है कि कहीं असमाजिक तत्वों द्वारा शहर की शांति भंग करने की कोशिश तो न की जा रही है। ●

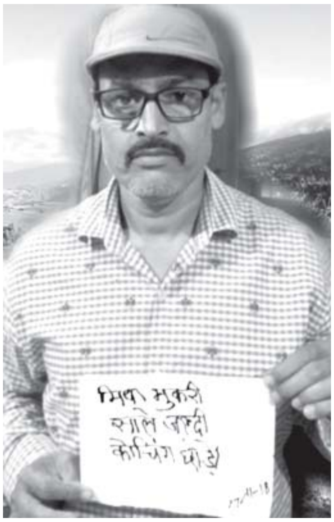

दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त दिग्घी चट्टी का माँ भगवती मंदिर

● प्रभात रंजन

हाजीपुर प्रखंड क्षेत्र के दिग्घी चट्टी स्थित माँ भगवती मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली है। मंदिर का महात्मय देश के कोने-कोने से भक्तों को खींच लाता है। यहाँ सालों भर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मान्तया है कि माँ अपने भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूरी करती हैं और हर संकट से उन्हें बचाती है। बहुत से परिवार यहाँ अपने बच्चों के मुंडन, जनेऊ संस्कार और शादी के लिए भी आते हैं। मंदिर में दोनों संध्या को दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ होता है। नवरात्रि के दिनों में विशेष विधि -विधान से पूजा-अर्चना की जाती है जिसे वाराणसी के आचार्य अनुरूद्ध द्विवेदी के देख-रेख में संपन्न किया जाता है। इस अवधि में भक्तों की भरी-भीड़ रहती है। इस अवसर पर सर्वोदय दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में मंदिर को आकर्षक ढंग से सजावट की जाती है। भजन कीर्तन किया जाता है और मंदिर के मुख प्रकोष्ठ में ऊंची वेदी पर प्रतिस्थापित पिंडी के आलावा भव्य प्रतिमा का निर्माण करवाया जाता है, जो पूरे शहर में आकर्षण का केन्द्र होता है। नवरात्र समाप्ति के बाद प्रतिमा का निर्माण करवाया जाता है, जो पूरे शहर में आकर्षण का केन्द्र होता है। नवरात्र समाप्ति के बाद प्रतिमा का विसर्जन कर भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर के संरक्षक अवध किशोर सिंह का कहना है कि इतना विशाल आयोजन माता की कृपा से ही हो पाता है। बिहार की राजधानी पटना से यह स्थान एन.एच. 77 पर 22 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना से मुजफ्फरपुर, पटना से समस्तीपुर जाने वाली सभी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। यात्री चाहें तो रामाशीष चौक पर उतरकर रिक्शा या ऑटो में मंदिर जा सकते हैं। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से माता के मंदिर की दूरी 29 किलोमीटर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन हाजीपुर है। यहाँ से उतरकर रिक्शा या ऑटो से पूर्व मध्य रेलवे कार्यालय होते हुए दिग्घी चट्टी वाली माँ भगवती मंदिर में अर्जी के लिए पहुंच सकते हैं।●

सुविधा के आभाव में चल रहा प्रखण्ड मुख्यालय कार्यालय

● सुमित राज यादव

ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय के करीब 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी घोर सुविधाओं के अभाव में प्रखंड कार्यालय का संचालन हो रहा है। नगर पंचायत के 12 वार्डो में करीब 22 हजार से अधिक आबादी और 22 पंचायत वाली प्रखंड मुख्यालय की स्थिति आज भी दयनीय है। कई अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। मुख्यालय का आकार और स्थल को निश्चित रूप से बदला। किन्तु, सुविधाओं के आभाव से प्रखंड मुख्यालय आज भी कराह रहा है। कई समस्याओं के कारण प्रखंड कार्यालय आने वाले लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जिसमें पीने के लिए पानी, बैठने के सुविधओं का अभाव, वाहनों के पार्किग का अव्यवस्थित होना भी बड़ा समस्या है। करीब तीन वर्षो से अधिक दिनों से नजारत का प्रभार पूर्ण रूप से ठाकुरगंज प्रखंड नाजिर को नहीं मिल पाया है। ठाकुरगंज में नाजिर पद पर पदस्थापित मतिउर रहमान वर्तमान में जिला पंचायती राज कार्यालय में कार्यरत है। कुछ 15 एकड़ की जमीन पर प्रखंड मुख्यालय कार्यालय का है। खाता संख्या 57 में कई खेसरा अंकित है। जिसमें खेसरा संख्या-2460, 2459, 2461, 2499, 2526, 2526, 2527, 2497, 2495, 2496, 2494, 2491, 2498, 2500 है। करीब पाँच वर्ष पूर्व इसकी चारदीवारी का निर्माण हुआ था। उस समय तत्कालीन सी. ओ. अनूप कुमार त्रिपाठी थे।

✯ **बैठने की नहीं है व्यवस्था :-** प्रखंड मुख्यालय पहुँचने वाले लोगों को कार्यालय में बैठने की उचित सुविधा न होने के कारण यत्र-तत्र मिट्टी पर बैठने को विवश है। कड़ी धूप में भी लोगों को आर.टी.पी.एस. काउंटर में कतार में अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। तो अन्य कार्य के लिए पहुँचे लोगों को भी मुख्यालय के गेट पर या कार्यालय के गेट पर ही खड़ा रहना पड़ता है। जिससे आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

✯ **महिलाओं की सुरक्षा कमी :-** कार्यालय के पास सुरक्षा गार्ड के नहीं रहने के कारण महिलाओं को लेकर शोरगुल होता रहता है। गार्ड न रहने की स्थिति में महिलाओं की लंबी कतारें कभी-कभी बड़ी होने से धूप, वर्षा में इंतजार करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी इस परेशानी से होकर गुजरना पड़ता है। प्रमाण-पत्र लेने के लिए प्रखंड कार्यालय में आने वाले बच्चों की भीड़ भी अनियंत्रित होती है।

✯ **नहीं है पार्किंग की सुविधा :-** 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रखंड मुख्यालय परिसर में अबतक पार्किंग की सुविधा नहीं हो पाई है। जिसके कारण वाहन जहाँ-तहाँ लगाई जाती है। कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर वाहनों के बनाए जाने से काफी दिक्कतें होती है। गार्ड न रहने से अंचलाधिकारी और बी.डी.ओ. के वाहन छत के नीचे खड़ी की जाती है। जबकि करीब 15 एकड़ के खुले मैदान में प्रखंड कार्यालय है।

✯ **वृक्षारोपण से मिल सकती है परेशानी से निजात :-** प्रखंड मुख्यालय परिसर में खुले जमीन में छायादार वृक्षों के वृक्षारोपण हो जाने से लोगों को पेड़ की छाव से राहत मिल सकेगी। वन विभाग के कर्मी बबलू से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा भी कही गई थी। किंतु पौधा का चयन प्रखंड मुख्यालय को लेकर सही होना चाहिए। इसलिए अबतक नहीं मिल पाई थी। किन्तु, वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा भी जानकारी दी गई है। जल्द पौधा उपलब्ध होते ही मुख्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

✯ **पीने का पानी की समस्या :-** प्रखण्ड मुख्यालय परिसर में दूर से आप लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए लोगों को खरीदकर पीना पड़ता है। साथ ही सरकारी योजना से बने चापाकल भी अपनी बदहाली पर आँसू बहाने को विवश है।

✯ **कई विभागों के एकसाथ है कार्यालय :-** प्रखंड मुख्यालय परिसर अन्तर्गत सभी विभागों के कार्यालय एक साथ है। जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, अंचलाधिकारी का कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, मनरेगा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, आई.सी.डी.एस. कार्यालय, व्यापार मंडल भवन, कौशल विकास योजना भवन के साथ आवासीय भवन क्वार्टर भी शामिल है। ●

✯ चारदीवारी निर्माण को लेकर बात हुई है। वृक्षारोपण के साथ मुख्यालय परिसर को जल्द पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा।

श्रीराम पासवान,
प्रखंड विकास पदाधिकारी

✯ व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही कार्य आरम्भ किया जाएगा। अंचल कार्यालय में आर.टी.पी.एस. काउंटर में भी बदलाव जल्द देखने को मिलेगा।

उदय कृष्ण यादव,
अंचलाधिकारी

काले हीरे का बेहतरीन खजाना झारखण्ड

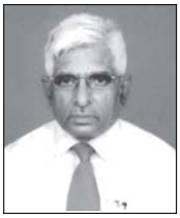

● ललन कुमार प्रसाद

हमारे देश में करीब 190 थर्मल पॉवर स्टेशन हैं, जो कोयला से चलाये जाते हैं। कोयला जलाकर बॉयलर में स्टीम जेनरेट की जाती है और स्टीम से टरबाइन चलायी जाती है और तब बिजली का उत्पादन होता है। इन्ही थर्मल पॉवर स्टेशनों की बदौलत सारा देश रौशन रहता है तथा देश के सारे उद्योग चलाये जाते हैं। दरअसल कोयले से बिजली पैदा की जाती है, जिससे देश के सारे उद्योग चलते हैं। जिससे न केवल देश रौशन होता है, बल्कि अस्पतालों में जांच हेतु सभी उपकरणों को चलाया जाता है। लेबोरेटरिज के ढ़ेर सारे उपकरण बिजली से ही चलाये जाते हैं। अखबार, किताब, पत्रिका को छापने के लिए छपाई मशीन और लिखित मैटर को प्रकाशनार्थ कम्पोज करने के लिए कम्प्यूटर भी बिजली से चलाये जाते हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय आदि बिजली के बदौलत ही रौशन रहते हैं। बैंक, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सिनेमाघर, मॉल, बाजार, सड़के आदि सब के सब बिजली से रौशन रहते हैं, जो कोयला जलाकर पैदा की जाती है। और कितना बखान करूं, बिजली की उपयोगिता की कोई सीमा नहीं है, जो कोयला जलाकर पैदा की जाती है। अब तो आप समझ ही गये होंगे कि घर, दफ्तर, बाजार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, मॉल, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी केन्द्र, रेलवे स्टेशन, रेल के डब्बे, बस अड्डा, हवाई अड्डा, बंदरगाह, म्यूजियम, अभिलेखागार आदि सब के सब कोयले के बदौलत ही रौशन है।

कोयले के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से देश का झारखण्ड राज्य, देश में सर्वोत्तम है। ऐसा इसलिए की कोयले के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से पूरी दुनियां में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान भारत है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखण्ड में है। इसलिए झारखण्ड को कोयलांचल भी कहा जाता है।

☆ देश का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक कोयला उत्पाादक प्रदेश है झारखण्ड :- दरअसल पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाले पदार्थों में कोयला एक प्रकार का अनोखा खनिज है, जो स्वयं जलकर लोगों को खाने के लिए भोजन पकाता है। दुनियां का अंधेरा दूर करने के लिए रौशनी पैदा करता है और हर तरह का सहुलियत पैदा करके उद्योगों को चलाता है। चिरकाल से कोयला का उपयोग खाना पकाने और ताप पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है। मानव सभ्यता के आरंभिक दौर से ईंधन का स्थान सर्वोच्च रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को पकाने, आसपास की जगहों को रौशन करने तथा जाड़ा के दिनों में आग

तापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। वैसे प्रकृति में अनेक प्रकार के ठोस ईंधन पाये जाते हैं, जैसे-कोयला, लकड़ी, छाल, झाड़ी, आदि। लेकिन सर्वाधिक उपयोगी कोयला है। इसलिए कोयले को काला हीरा कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत होने के कारण आज के आधुनिक युग में भी कोयले की उपयोगिता उत्तरोत्तर

बढ़ती चली जा रही है। दरअसल, यह ऊर्जा का सरल, सस्ता और प्रचूर मात्रा में उपलब्ध एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसकी उपयोगिता जर्बदस्त है। भाप के इंजन के अविष्कार के साथ इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाने लगा। भाप इंजन को चलाना दुनियां को रौशन करने तथा इंड्रस्ट्रीज में मशिनों को चलाने के लिए थर्मल पॉवर स्टेशनों में बिजली का उत्पादन करना हो, ईंट पकाना हो, धमन भट्टियां चलानी हो, लोहे और इस्पात उद्योग के लिए धातुकर्मी कोक बनाना हो, भाप से पकाकर प्लाईवूड तैयार करना हो, सीमेंट, चूना, चीनी, एलुमिना, मैग्नेशिया आदि का उत्पादन करना हो, जीवन रक्षक दवाईयां बनानी हो और न जाने किन-किन पदार्थों का उत्पादन करना हो, इन सब के लिए कोयला चाहिए। फलस्वरूप जिस देश में जितने अधिक कोयले का भंडार उपलब्ध है, वह देश औद्योगिक रूप से उतना ही विकसित और अर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध है। अमेरिका, रूस और चीन इन तीन देशों में कुल मिलाकर विश्वभर के कुल कोयला उत्पादन का 65 फिसदी हिस्सा प्राप्त होता है। इसलिए ये तीनों देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। कोयले के भंडार और उसके उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व में चौथा स्थान भारत का है। लेकिन, भारत विकसित देश नहीं है और जो आज की हालात है, उससे तो यही लगता है कि भारत शायद ही विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा। ईश्वर करे की मेरा अनुमान 100 फिसदी गलत साबित हो।

बांग्लादेश, नेपाल, म्यामार और न्यूजीलैंड को भारत कोयले का निर्यात करता है। कोयले के उत्पादन में लगातार बिगड़ती स्थिति के चलते भारत अपने ही देश में कोयले की मांग पूरी करने में अक्षम होता जा रहा है। नतीजा भारतीय कोयले के निर्यात में लगातार कमी होती जा रही है। दुख की बात है कि दुनियां का सर्वश्रेष्ठ और चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और निदरलैंड से भारत न कोयले का आयात कर रहा है, आयात करने की मात्रा भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। अमेरिका, रूस और चीन हमारे देश से काफी आगे निकल गये हैं और भारत लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। लगातार कई दशकों तक झारखण्ड में कोयला उत्पादन में निरंतर कमी होते जा रही है। नतीजा, हमें कोयले के आयात में लगातार बढ़ोत्तरी करनी पड़ रही है। फलस्वरूप हमारे देश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण है, कोयले के खनन के दौरान कोयले की भारी बर्बादी। क्योंकि झारखण्ड में तीन हजार से अधिक अवैध कोयला खद्दाने हैं। जिसको जहां इच्छा होती है, अवैध रूप से कोयले का खनन शुरू कर देता है। कोई रोक-टोक नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है। प्रतिदिन करोड़ रूपये मूल्य के कोयले की चोरी, जिससे भंडारण और ट्रांसर्पोटेशन के दौरान कोयला भारी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। इन दोनों कृत्य कोयले की बर्बादी के सबसे बड़े कारणों की जड़ में है, जो कोयला उद्योग में व्याप्त जर्बदस्त भ्रष्टाचार का नतीजा है।

भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया के 1 अप्रैल 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले का भंडार 293497.15 मिलियन टन है और अकेले झारखण्ड में 80356.20 मिलियन टन, यानि देश में कोयले के कुल भंडार का 27.35 फिसदी। लेकिन, भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया का यह आंकलन गलत है, क्योंकि हाल ही में झारखण्ड में छः जगहों पर उत्तम कोयले के बड़े भंडार पाये गये हैं। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान का कहना है कि झारखण्ड में उत्तम कोयले का इतना बड़ा भंडार है कि अकेले यह राज्य पूरे देश के सभी थर्मल पॉवर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति कर सकता है, जिससे

की पूरा देश रौशन हो सकता है और देश के सभी उद्योगों को संचालित किया जा सकता है। वैसे तो देश के कई राज्यों में कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोयला क्षेत्र अवस्थित राज्य हैं-झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडू, पांडीचेरी, गुजरात और राजस्थान। लेकिन देश के प्रमुख पांच कोयला क्षेत्र हैं-दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, हजारीबाग कोयला क्षेत्र, उत्तर कोयल घाटी कोयला क्षेत्र, देवघर कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र। इन पांच कोयला क्षेत्रों में से चार पूर्णत: और एक आंशिक रूप से झारखण्ड में अवस्थित है। यही कारण है कि देश में कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखण्ड में है और सबसे अधिक उत्पादन भी इसी राज्य से होता है। सिर्फ दामोदर घार्टी कोयला क्षेत्र के रानीगंज उप कोयला क्षेत्र का अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस कोयला उपक्षेत्र का कुछ भाग झारखण्ड के संथाल परगना और वीरभूम क्षेत्र में पड़ता है। अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल में पड़ने के कारण इस उप कोयला क्षेत्र में कोयले का खनन का कार्य पश्चिम बंगाल द्वारा संचालित किया जाता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में रानीगंज उप कोयला क्षेत्र के अलावा अन्य उप कोयला क्षेत्र हैं-झरिया उप कोयला क्षेत्र, बोकारो उप कोयला क्षेत्र और चन्द्रपूरा उप कोयला क्षेत्र। हजारीबाग कोयला क्षेत्र के उपकोयला क्षेत्र हैं-रामगढ़ उप कोयला क्षेत्र, कनकपुरा उप कोयला क्षेत्र, ईंटखोरी उप कोयला क्षेत्र, चोप उप कोयला क्षेत्र और गिरिडीय उप कोयला क्षेत्र। उत्तर कोयल घाटी कोयला क्षेत्र के उप कोयला क्षे हैं-हतार उप कोयला क्षेत्र, औरंग उप कोयला क्षेत्र और डाल्टेनगंज उप कोयला क्षेत्र। देवघर कोयला क्षेत्र के उपकोयला क्षेत्र हैं-जयंति उप कोयला क्षेत्र, शाहजूरी उप कोयला क्षेत्र और कुण्डित करैया उप कोयला क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र के उप कोयला क्षेत्र हैं-ब्राह्मणी उप कोयला क्षेत्र, पचवाड़ा उप कोयला क्षेत्र, चुपरविता उप कोयला क्षेत्र, डूनरा या महुआगिरी या जिलकारी उप कोयला क्षेत्र और हुरा उप कोयला क्षेत्र।

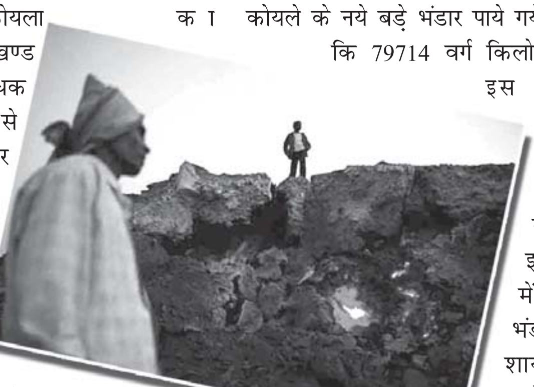

रानीगंज उप कोयला उत्पादक क्षेत्र के बाद देश का सबसे बड़ा उप कोयला उत्पादक क्षेत्र है झरिया उप कोयला उत्पादक क्षेत्र। हासिय की आकृति का उप कोयला उत्पादक क्षेत्र औसतन 38 किलोमीटर लंबा और 19 किलोमीटर चौड़ा है। यह उप कोयला क्षेत्र कुल मिलाकर 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उप कोयला क्षेत्र झारखण्ड के धनबाद जिला में अवस्थित है। देश के कुल कोयला उत्पादन का दस फिसदी कोयला यही से प्राप्त होता है। दुनियां का सर्वोत्तम कोयला यही से प्राप्त होता है। यही कारण है कि धनबाद को ''काले हीरे की नगर'' कहा जाता है। झारखण्ड में लातेहार जिला के जगलेदंगा गांव में चार स्थानों पर और दुमका पछवाड़ा क्षेत्र में दो स्थानों पर उत्तम श्रेणी के कोयले के नये बड़े भंडार पाये गये हैं। लगता है कि 79714 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य में चप्पे-चप्पे पर जमीन के नीचे कोयले का भंडार है। इतने बड़े क्षेत्र में कोयले का भंडार विश्व में शायद ही कही देखने-सुनने को मिले। वास्तव में हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत दुनियां भर में चौथा होने के बावजूद कोयला का आयात करत है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

कोयले की बर्बादी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है झरिया कोइलरी में जमीन के नीचे कोयला खाद्यान्न के अंदर कई वर्ग किलोमीटर में फैली भीषण आग। इस आगजनी की शुरूआत आज से लगभग 120 वर्ष पहले हुई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। फलस्वरूप प्रतिदिन न जाने कितने करोड़ रूपये मूल्य का दुनियां का सर्वोत्तम कोयला राख में तब्दील होता जा रहा है। सर्वोत्तम कोयला इसलिए की झरिया कोईलरी से दुनियां का सर्वोत्तम कोयला प्राप्त होता है। इस आगजनी के चलते झरिया कोइलरी क्षेत्र के 35 किलोमीटर की दूरी तक रेल का परिचालन बंद कर दिया गया, जिससे भारतीय रेलवे को न केवल अरबों-खरबों का नुकसान उठाना पड़ा बल्कि उसके आसपास बसे लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं जमीन में लगी इस अंदरूनी आग के चलते पर्यावरण बुरी तरह से दिन-रात चौबिसों घंटे प्रदुषित होता रहता है। इस लगातार होती आ रही भारी क्षति के लिए सबसे अधिक वे गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट सरकारी मुलाजिम हैं, जो भारत की आजादी के पहले से लेकर आज तक विभिन्न काल खंडों में कार्यरत्त थें और आज भी कार्यरत्त हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब से न जाने कितनी राज्य और केन्द्र सरकारें आयी और गई। लेकिन, इन सरकारों के नेताओं ने झरिया कोइलरी में लगी भीषण आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखते आ रहे हैं भारत की बर्बादी। आजादी के पहले 200 वर्षों तक तो अंग्रेजों का शाषण था। उनका लक्ष्य ही था भारत को लूटना। लेकिन, जब देश आजाद हो गया तो देश के अधिकतर राजनेताओं और सरकारी मुलाजिम भी वही कर रहे हैं। यानि अपने ही देश को लूट कर भरपूर निजी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि मुगल काल से अंग्रेजों के शासनकाल तक इस देश को जितना लूटा गया, उससे कई गुणा अधिक आजादी के बाद से देश के ढ़ेर सारे नेताओं और सरकारी मुलाजिमों ने लूटा है तथा लूट के पैसे से भारी मात्रा में संपत्ति खरीद रखा है। वैज्ञानिक शोध संस्थान और बी.सी.सी. एल. द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपगग्रहों के द्वारा ली गई धनबाद कोल फिल्ड की तस्वीरों से पता चला है कि 1976 से 1988 तक आग का दायरा 17.32 वर्ग किलोमीटर था, जो 1990 में सिमटकर 15.87 वर्ग किलोमीटर और 1994 में 13.67 वर्ग किलोमीटर रह गया। उसके बाद अमेरिका-कनाडा की संयुक्त एजेंसी ''मेटकम गाइ'' द्वारा 1996 में विशेष तौरपर उपग्रह सर्वे में 8.9 वर्गकिलोमीटर तक सिमटा देखा गया। अर्थात् 1976 से 1996 के बीच झरिया कोइलरी की आग सिमटकर 8. 9 वर्ग किलोमीटर रह गई। अर्थात् झरिया कोइलरी की आग के दायरे में 8.32 वर्ग किलोमीटर की

कमी हो गई। उस समय झारखण्ड सरकारी और झारखण्ड के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत्त सरकारी मुलाजिम गफलत में जीने लगे की झरिया कोइलरी की आग स्वत: बुझ जायेगी। लेकिन वह बहुत अच्छा मौका था आग पर काबू पाने का। यदि उसी समय सरकार झरिया कोइलरी की आग को बुझाने का प्रयास करती तो 1999 पूरा होते होते झरिया कोइलरी की आग बुझ सकती थी। लेकिन सरकार की निष्क्रियता और सरकारी मुलाजिमों के निकम्मापन के चलते आग पुन: फैलने लगी। पिछले चार वर्षों में आग के दायरे में 1.10 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। इस बात का पता अंतरिक्ष में 700 से 1000 किलोमीटी की ऊँचाई पर चक्कर लगा रहे नाशा के टेरा नामक उपग्रह में धरती की सतह की उष्मा मापने के लिए लगे आधुनिकत्तम सेंसर एस्टर (एडवांस्ट स्पेसबोर्न थर्मल इमिशन एण्ड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर) द्वारा ली गई तस्वीर से पता चला है। दरअसल यह अमेरिकी उपग्रह विश्व का ऐसा अकेला उपग्रह है, जिसमें हर तरह के सेंसर लगे हैं। वर्तमान में झरिया कोइलरी में लगी आग की स्थिति कैसी है, इसका पता लगाने के लिए कोकिंग कोल लिमिटेड, झारखण्ड ने नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद से सम्पर्क किया था। उसके बाद नासा, अमेरिका से मदद ली गई, तब जाकर सच्चाई सामने आयी।

आजादी के बाद से ही कई दशकों तक डबल इंजन सरकारें रही। यानि, कांग्रेस की ही सरकार रही। फिर भी आग नहीं बुझाई जा सकी, जबकि उस समय झरिया कोइलरी में जमीन के अंदर लगी आग का दायरा काफी छोटा था। अब पुन: डबल इंजन सरकारें हैं, यानि केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन अब आग का दायरा काफी बड़ा है। अब तो सरकार को इस मामले को लेकर बहुत अधिक सक्रिय अविलंब हो जाना चाहिए, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इतना ही नहीं कोयले के अवैध खनन और चोरी रोकने में सौ फिसदी असफल है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सरकारे क्या कर रही है। अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभ रही है। सरकार अपनी उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के प्रति इतना लाचार क्यों है।

जब कोयले का खनन किया जाता है तो जमीन के अंदर निकले कोयले की वजह से बनी खाली जगह को बालू से भरने के बाद पानी से तर कर दिया जाता है, जिससे की कोयले की खनने के बाद एक्सपोज्ड सतह से जो थोड़-थोड़ी मात्रा में मिथेन गैस रिसती रहती है, उसको

बिल्कुल बंद कर दिया जाये। जिससे की आग लगने की कोई संभावना ही न रह जाये। लेकिन इस कार्य को करने के लिए खाली बनी जगह में जितना बालू भरना चाहिए था, उससे बहुत ही कम मात्रा में भरा गया। यह भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। परिणाम आज झरिया कोइलरी की जमीन के अंदर भयंकर आग की चपेट में है। इसे लेकर सारी दुनियां चिंतित है, लेकिन झारखण्ड सरकार कुंभकर्णी नींद में सोयी हुई है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या झरिया कोइलरी में लगी आग को बुझाना संभव है? क्या आग का दायरा लगातार बढ़ता ही चला जायेगा? और इससे पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान तथा पर्यावरण प्रदुषण में इजाफा ही होता चला जायेगा? अगर आग को नहीं बुझाया गया तो कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। झरिया कोइलरी में लगी इस प्रचंड आग को बुझाना असंभव नहीं है, मुमकिन है। इसके लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा की जरूरत है। यदि आगजनी वाले क्षेत्र की सीमा से दस मीटर हटकर चारो तरफ से बीस इंच मोटी इंट की दीवार खड़ी करते चले और दीवार खड़ी करने के लिए उसके दोनो ओर बनी खाली जमीन को बालू से भरकर पानी से तर करते चले। ऐसे करने से झरिया कोइलरी में लगी आग को जैसे-जैसे जलने के लिए कोयला मिलना बंद होता चला जायेगा, वैसे-वैसे आग बुझती चली जायेगी। इस तरह आग का दायरा लगातार सिमटता चला जायेगा और अंतत: आग बुझ जायेगी। यह काम बहुत कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।

☆ **कोयला क्या है :-** यह एक प्रकार का काला ठोस खनीज है, जो भू-गर्भ से निकला है। भू-गर्भ में जिवाश्म पदार्थों (पेड़-पौधों) के लाखों वर्षों तक दबे रहने पर नमी, दबाव और समय के साथ भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों

के आधार पर अनेक प्रकार के कायेले बनते हैं, जो खानों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के यह कोयले उम्दा किस्म के ईंधन हैं, क्योंकि इनका उष्मीय मान बहुत अधिक होता है। इनका उष्मीय मान 4000 से 11000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तक होता है। उष्मीय मान क्या है? किसी ईंधन की ईकाइ मात्रा के पूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली उष्मा की कुल मात्रा को उस ईंधन विशेष का उष्मीय मान कहा जाता है। इसकी ईकाइ कैलोरी प्रतिग्राम या किलो कैलोरी प्रतिग्राम है।

कोयला एक पेचीदा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का काले रंग का रासायनिक जटिल मिश्रण है। जिन्हें साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से कोयले के चार अवयव होते हैं-विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजेन। इन्ही विभिन्न चार अवयवों के चलते कोयले भिन्न-भिन्न दिखते हैं।

☞ **विट्रेन :-** विट्रेन प्रधान कोयला पतली धारियों वाले चमकीले काले रंग का होता है।

☞ **क्लेरेन :-** क्लेरेन प्रधान कोयला विट्रेन प्रधान कोयले की अपेक्षा कम पतले धारियों वाला काले रंग का कम चमकीला होता है।

☞ **ड्यूरेन :-** ड्यूरेन प्रधान कोयला मोटी धारियों वाला काले मटमैले रंग का होता है।

☞ **फ्यूजेन :-** फ्यूजेन प्रधान कोयला कम कठोर, रेशेदार और काले रंग का होता है।

✯ **कोयले का वर्गीकरण :-** पृथ्वी के अंदर खानों में भिन्न-भिन्न गहराई से कोयले निकाले जाते हैं। एक ही खान से निकले भिन्न-भिन्न गहराई के कोयले भिन्न-भिन्न होते हैं। हर एक किस्म का कोयला अपनी रचना में दूसरे किस्म के कोयले से भिन्न होता है, क्योंकि पेड़-पौधे से कोयला बनाने वाली परिस्थितियां अलग-अलग गहराई में अलग-अलग रहती है।

कोयले कई किस्म के होते है। इन किस्मों के साथ इनके गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैं। वैसे कोयले का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है-इनके गुणों के आधार पर, संरचना के आधार पर, बाहरी स्वरूप के आधार पर, उष्मा प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति स्थल की परिस्थिति के आधार पर, इत्यादि। लेकिन, किस प्रकार के पौधों से कोयला बना है, इस दृष्टि से कोयला दो प्रकार के होते हैं-धरणिक (ह्यूमी) कोयला और अधणिक (सेप्रोपेली) कोयला। जो बड़े-बड़े वृक्षों और उनके वल्कों से बने होते हैं, उन्हें ह्यूमिक कोयला कहते हैं। जो कोयला छोटे-छोटे पेड़-पौधों से बने होते हैं, उन्हें सेप्रोपेली कोयला कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से सेप्रोपेली कोयले का महत्व ह्यूमिक कोयले की अपेक्षा बहुत कम होता है। भारत में सेप्रोपेली कोयला बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है।

✯ **ह्यूमिक कोयले की किस्में :-**

☞ **पीट कोयला :-** यह कोयले में परिवर्तित होने वाली सबसे पहली अवस्था है। इसमें वनस्पति के अवशेष भी पाये जाते हैं। यह कोयले का सबसे नरम रूप है। इसका रंग हल्के भूरे रंग से लेकर गहरे भूरे रंग का होता है। इसके जलने पर काफी धूंआ निकलता है। सूखने पर यह कठोर और भंगूर हो जाता है। इस कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर चूर-चूर हो जाता है। जिससे इसका बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इसका इस्तेमाल जलावन के रूप में किया जाता है। यह सभी प्रकार के कोयलों में सबसे घटिया किस्म का कोयला है, क्योंकि इसका उष्मीय मान सभी प्रकार के कोयले में सबसे कम होता है। इसका उष्मीय मान 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है।

☞ **लिग्नाइट कोयला :-** यह गहरे बादामी रंग का होता है। पीट कोयले की तरह तोड़कर देखने पर इसकी रचना भी लकड़ी जैसी दिखती है। यह पीट कोयला से कठोर होता है। यह कोयला भी उम्दा जलावन नहीं है, क्योंकि इसका उष्मीय मान भी बहुत कम होता है। इसका उष्मीय मान 4000 से 5000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। पीट कोयले की तरह यह कोयला भी सूखने पर कठोर और भंगुर हो जाता है। इस कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर चूर-चूर हो जाता है, जिससे इसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। पीट कोयले की तरह इस कोयले को खुली हवा में भंडारित नहीं किया जाता और ना ही दूर तक ढ़ोकर ले जाया जाता है, क्योंकि यह हवा से ऑक्सिजन का अवशोषण करता है, जिससे इसमें स्वत: आग लगने का भय बना रहता है। मुख्य रूप से इस कोयले का उपयोग प्रोड्यूसर गैस तैयार करने के लिए किया जाता है।

☞ **बिटुमिनी कोयला :-** बिटुमिनी कोयले का उष्मीय मान 6850 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से लेकर 8350 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तक होता है। अर्ध-बिटुमिनी कोयला के पूर्ण दहन के बाद चार फिसदी राख बचता है और सब-बिटुमिनी कोयला को जलाने पर तीन फिसदी राख बचता है। यह कोयला काले से धूसर रंग का होता है। इसे छूने पर उंगली में काला दाग पड़ जाता है। मध्यम और निम्न बिटुमिनी कोयले का उपयोग कोक और गैस बनाने में होता है। यह सरलता से जलता है और ज्यादा धूंआ नहीं देता है। यह कोयला टूटता है पर चूर्ण नहीं होता, पटिया (स्लेट) में टूटता है। स्पष्ट है कि इस कोयले का प्रज्वलन गुण उत्तम है और ट्रांसपोर्टेशन में इस कोयले की बर्बादी नहीं होती है। इसलिए बिटुमिनी कोयला सर्वोत्तम कोयला है। अत: संसार में ईंधन के रूप में सबसे अधिक इसी कोयले का उपयोग किया जाता है।

कठोरता के आधार पर बिटुमिनी कोयला मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं- अर्ध-बिटुमिनी कोयला और सब-बिटुमिनी कोयला। लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी बिटुमिनी कोयला होता है। जिसे सुपर बिटुमिनी कोयला कहते हैं। इसका उष्मीय मान 7500 से 8500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है।

☞ **एन्थ्रासाइट कोयेला :-** यह कोयला भारत में कश्मीर और आसाम के क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाणा क्षेत्रों में भी कही-कही यह कोयला मिलता है। यह कोयले का सबसे कठोर रूप है। इसलिए इसे कठोर कोयला के नाम से भी जाना

Anthracite

Bituminous

Subbituminous

Lignite

जाता है। यह काला होता है लेकिन इसको छूने से हांथ में दाग नहीं पड़ती है। इसमें अध-धात्विक चमक होती है। यह कठिनाई से और धीमे जलता है। इसलिए इसे लकड़ी से नहीं जलाया जाता। इसे गैस या बिटुमिनी कोयला से जलाया जाता है। जलने पर यह छोटी मगर हल्के नीले रंग की चमक के साथ पीला ज्वाला देता है। इसका उष्मीय मान 7800 से 8800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है।

☞ **अर्ध-एन्थ्रासाइट कोयला :-** एन्थ्रासाइट और निम्न वाष्पशील बिटुमिनी कोयले के बीच के कोयला को अर्ध-एन्थ्रासाइट कोयला कहते हैं। यह अर्ध-बिटुमिनी कोयला से अधिक कठोर पर एन्थ्रासाइट कोयला से कम कठोर होता है। यह एन्थ्रासाइट के अपेक्षा सरलता से जलता है।

☞ **मेटा-एन्थ्रासाइट कोयला :-** यह कोयला एन्थ्रासाइट श्रेणी में सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला है। इसमें स्थायी कार्बन अधिक होता है, इसलिए इसको छूने से हांथ में दाग नहीं लगता है।

☞ **स्टीम कोयला :-** यह बिटुमिनी परिवार का ही कोयला है, जिसमें केकिंग कोयले की प्रधानता रहती है। इसमें उड़नशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। यह पीली लव के साथ जलता है और धूंआ अधिक देता है। यह कोयला अधिकत्तर भाप बनाने वाले वॉयलरों की भट्टियों में प्रयुक्त होता है।

☞ **कुकिंग कोयला :-** जलने पर यह पीले और नीले रंग की ज्वाला देता है तथा धूंआ बहुत कम देता है। जलने पर आग पकड़ते-पकड़ते इसका सारा धूंआ निकल जाता है, जिससे बाद में यह कालिख नहीं देता। आमतौर पर इसे घरेलू कार्यो जैसे खाना पकाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तथा हल्की भट्टियों में जलाया जाता है।

☞ **केनिल कोयला :-** यह बिटुमिनी और सब-बिटुमिनी कोयले के मध्य की श्रेणी का कोयला है। इसमें उड़नशील पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। यह कोयला दीप्त ज्वाल यानि प्रकाश विखेड़ने वाली मोमबत्ती की ज्वाला की तरह जलता है। इसलिए इसका नाम केनिल कोयला पड़ा। गर्म होने पर यह कोयला बहुत अधिक मात्रा में गैस प्रदान करता है। यही कारण है कि गैस के उत्पादन में बहुत अधिक काम आता है और मूल्यवान होता है।

☞ **ग्रेफाइट कोयला :-** यह कोयले में सबसे ऊँची और शुद्ध श्रेणी का काले रंग का कोयला है। इसका प्रज्वलन तापमान बहुत ऊँचा है। इसलिए अकेले नहीं जलाया जाता। इसको तेल के साथ मिलाकर जलाया जाता है, जिससे की इसे जलाने हेतु यानि आग पकड़ने हेतु उच्च तापमान प्राप्त हो सके। सभी प्रकार के कोयलों की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 98 फिसदी होती है। इसमें नमी और उड़नशील पदार्थ अन्य सभी कोयले की तुलना में सबसे कम होता है। इसे शुद्धत्तम कोयला कहा जाता है। इसलिए इस कोयले को उच्च ताप वाली भट्टियों में जलाना ज्यादा हितकर होता है। अधिकतर इसे अन्य कोयले के साथ मिलाकर जलाया जाता है।

✯ **कैसे बचेगी कोयला कामगारों की जान :-** उद्योगों के विकास पर ही किसी देश की प्रगति निर्भर है, लेकिन औद्योगिक विकास के साथ-साथ उन उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा औद्योगिक स्थानों के आस-पास के पर्यावरण की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। उद्योगों में लगे कामगारों के विमार होने से औद्योगिक समृद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी उपकरण अपने से नहीं चलते हैं, उसे आदमी ही चलाता है। इसलिए उद्योग-धंधों में लगे कामगारों के स्वास्थ्य की देखभाल जरूरी है, उद्योगों में उत्पन्न होने वाले बिमारियों से कामगारों की सुरक्षा जरूरी है। यही बात कोयला उद्योग पर भी लागू होती है। कोयला उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। इसमें लाखों कामगार प्रतिदिन काम करते हैं। पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने पर वर्षों तक काम करने वाले कामगारों को आंथ्रकोसिस नामक सांस की खतरनाक बिमारी हो जाती है। यह एक लाइलाज बिमारी है।

इसलिए कोयला उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। आंथ्रकोसिस से पीड़ित कामगार को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति वायुमंडल से सांस के द्वारा जितनी हवा लेनी चाहिए, उतना नहीं ले पाता है। चूकि हवा कम लेते हैं, इसलिए ऑक्सिजन भी कम मिलता है। नतीजा उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति एक के बाद एक अलग-अलग बिमारी से ग्रसित होता चला जाता है और अंतत: उसकी मृत्यु हो जाती है।

इसलिए कोयला के खनन, भंडारण तथा लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान कामगारों को उचित प्रकार के डस्ट रेसपाइरेटर को पहनकर ही काम करना चाहिए। लेकिन, हमारे आदिवासी कामगार अनपढ़ हैं। इसलिए वे नहीं समझते हैं कि कार्य के दौरान कोयले के धूलकण सांस के द्वारा उनके फेफड़ों में घूंसकर उसकी टिसुज को क्षतिग्रस्त कर वहां पर अपना स्थान बना लेते हैं। जिसके चलते उनके सांस लेने की क्षमता लगातार कमजोर पड़ती जाती है। फलस्वरूप समय के पहले ही उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोयला कंपनियों के सेफ्टी ऑफिसर द्वारा डस्ट रेसपाइरेटर को पहनकर ही काम करने को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।

✮ कोयला आयात करने हेतु सरकारी बहानेबाजी :- अर्ध-बिटुमिनी कोयला और सब-बिटुमिनी कोयला पूर्ण दहन के बाद क्रमश: चार फिसदी और तीन फिसदी राख बचता है। लेकिन, अर्ध-एन्थ्रासाइट कोयला और मेटा-एन्थ्रासाइट कोयला के पूर्ण दहन के बाद क्रमश: दस फिसदी और सात फिसदी राख बचता है। इसलिए कोयला विशेषज्ञों द्वारा यह कहकर नकार देना की एन्थ्रासाइट कोयले के दहन से कम मात्रा में राख बनता है और इसलिए इस किस्म के कोयले को आयात करने की सिफारिश करना हास्यास्पद लगता है। जहां तक मेरा अनुमान है, एन्थ्रासाइट कोयले के उत्पादन हेतु खनन नहीं कराया या बहुत ही कम कराया जाना इसका बहुत उच्च प्रजलन तापमान है। जिसके चलते घरेलू इस्तेमाल हेतु इसे नकार दिया जाता है। जब हमारे देश में ही एन्थ्रासाइट कोयला का पर्याप्त भंडार है तो इस किस्म के कोयले को आयात करने की क्या जरूरत।

✮ कैसे रूकेगी कोयले की बर्बादी? :- झारखण्ड में 3 हजार से अधिक अवैध कोयला खाद्याने हैं। जिससे खनन के दौरान कोयले की बेतहाशा बर्बादी होती है। जब तक कोयले का खनन बगैर उचित तकनीक को अपनाये चोरी-छिपे, लेकिन बेरोक-टोक खनन होता रहेगा, तब तक प्रतिदिन खनन के दौरान भारी मात्रा में होती रहने वाली कोयले की बर्बादी को रोकना असंभव है। इसके लिए जरूरी है कि अवैध खनन पर अविलंब रोक लगा दी जाये और कोयले का खनन वैज्ञानिक तरीके से की जाये तथा कोयले का भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन उचित तरीके से कराया जाये, वरना हमारे देश को भारी आर्थिक क्षति लगातार उठानी पड़ सकती है। हमारे देश में कोयले के उत्पादन में लगातार कमी होती चली जायेगी। फलस्वरूप देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के आयात में लगातार बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार में अनवरत अधिक से अधिक कमी होती चली जायेगी।

भारत सेंट्रल कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है, जो झारखण्ड की राजधानी रांची में अवस्थित है। बीसीसीएल का काम ही कोयले का खनन इस प्रकार से कराया जाये की खनन के दौरान कोयले की बर्बाद न के बराबर हो। एक कोयला खान से अलग-अलग गहराई से अलग-अलग किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस किस्म के कोयले का कितनी गहराई से उत्खनन करने से किस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे की आसानी के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी सर्वाधिक उपयुक्त साबित हो तथा कम समय में बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया जा सके। लेकिन आज के हालात में यह संभव नहीं है। क्योंकि बीसीसीएल कंपनी बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही कारण है कि हर दिन हजारों जगहों पर कोयले का अवैध खनन बेरोक-टोक होता रहता है और वह भी जैसे-तैसे बगैर कोई वैज्ञानिक तकनीक अपनाये। ऐसे में कोयले की बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगा? अवैध कोयला खनन का कार्य सरकारी कोल कंपनियों के भरपूर समर्थन से कोल माफिया के लोग स्थानीय आदिवासियों के साथ मिलकर करते हैं।

✮ झारखण्ड के प्रमुख कोयला संस्थान :-

☞ भारत सेंट्रल कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), रांची।

☞ खनिज ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम और युरेनियम) पर अनुसंधान करने वाला शिक्षण संस्थान ''इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स'' (डीम्ड विश्वविद्यालय)। जिसकी स्थापना 1926 में धनबाद में हुई थी।

☞ माइनिंग एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1965 में रांची में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कोयला तथा अन्य खनिजों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाली मशिनों का निर्माण करना।

☞ सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट की स्थापना 1947 में जादूगोडा में हुई।

☞ सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची।

☞ सिंगरेली, जमादोवा, पश्चिमी बोकारो, लोदना, कर्णपूरा, आदि स्थानों पर कोयला शोधन कारखाने लगाये गये हैं। जहां कोयले से राख, अग्निसह मिट्टी, जिप्सम, फैल्सपार, शेल, आदि अलग किये जाते हैं।

✮ आखिर कब मिलेगा कोयला खादानों के असली मालिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार :- इतना तो सच है कि धूर्त लोग राजनेताओं तथा सरकारी मुलाजिमों से मिलकर जमीन के कागजात में हेरा-फेरी कराकर अनपढ़, सीधे-साधे, ईमानदार और मेहनती आदिवासियों

के जमीन को कौड़ियों में खरीदकर संपत्तिशाली बन बैठै हैं। इन धूर्त लोगों में राजनेता, सरकारी मुलाजिम, कोयला माफिया और ठग लोगों का बराबर का योगदान है, क्योंकि इन सबों ने मिलकर आदिवासियों को लूटा है, बर्बाद किया है। झारखण्ड में अधिकांश आबादी आदिवासियों का है, लेकिन झारखण्ड के अधिकांश भू-भाग पर गैर आदिवासी, सरकारी मुलाजिमों और गैर आदिवासी राजनेताओं ने आदिवासियों के आंखों में धूल झोंककर कब्जा कर लिया है। फिर ज्यादातर कोयला खादाने पहाड़ी इलाकों में स्थित है। यूं तो जंगल के विनाश से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे अधिक आदिवासी प्रभावित होते हैं। ऐसा इसलिए की आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। इनके दैनिक जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं जंगलों से पूरी होती है। वन्य प्राणियों का आखेट और जंगल में उपलब्ध फल तथा कंदमूल इनका भोजन होता है। इनके आवास वृक्षों की शाखाओं की टहनियों से तैयार किये जाते हैं। लेकिन ये आदिवासी राजनेताओं, सरकारी मुलाजिमों और धोखाबाजों के काली करतूतों के चलते अपने ही जमीन से बेदखल कर दिए गये हैं। ये लोग प्रताड़ित होकर भीतर से टूट गये हैं। पेट भरने के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। आखिर सरकार गरीब, अनपढ़, सीधे-साधे, ईमानदार और मेहनती आदिवासियों को जीवन यापन के साधन कब उपलब्ध करायेगी, जिसके वे असली हकदार हैं। आखिर कब मिलेगा कोयला खादानों के असली मालिकों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार?

✮ स्थिति बद्द से बद्दतर होती जा रही है, फिर भी केन्द्र और राज्य सरकारें सुधरने को तैयार नहीं :- कोयले की किल्लत के चलते बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और दिल्ली सहित देश के बड़े हिस्से को ब्लैक आउट का सामना करना पड़ सकता है, यानि बत्ती गुल हो सकती है। कोल इंडिया के एक्जीक्यूटिव के मुताबिक राजमहल कोलमाइंस में मौजूद कोयले का भंडार लगभग खाली होने को है। खादान के विस्तार की अविलंब शख्त जरूरत है। राजमहल कोल माइंस से सटे दो गांव बंसबीहा और तालझारी में भूमि विवाद के चलते भूमि अधिग्रहन की प्रक्रिया लंबे समय से लटकी पड़ी है। है। 160 हेक्टेयर में फैले इन दो गांवों के इलाकों में सघन आबादी है, जहां जमीन के एक-एक प्लॉट के लिए 40-50 लोग अपना हक जता रहे हैं। ऐसा इसलिए की, या तो राजस्व विभाग के सरकारी मुलाजिमों ने जमीन के मूल कागजातों को गायब कर दिया है या जमीन के मूल कागजातों में भ्रष्ट लोगों से नजराना लेकर हेरा-फेरी कर दी गई है, या तो दोनो ही भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। भ्रष्ट लोगों के साथ ढ़ेर सारे भ्रष्ट मुलाजिमों ने मिलकर ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी है कि जमीन के मूल कागजात के आभाव में सरकार किमकर्तव्य विमूढ़ हो गई है। सच तो यह है, दो सौ वर्षो के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत को जितना लूटा है, उससे बहुत ज्यादा आजादी के बाद 71 वर्षो में देश के भ्रष्ट लोगों ने देश को लूटा है।

स्थिति इतनी भयावह है कि एनटीपीसी के फरक्का थर्मल पॉवर प्लांट में कोयले का स्टॉक घटकर चार हजार टन पहुंच गया है, जो दो महीने पहले ढ़ाई लाख टन था। कहलगांव थर्मल पॉवर स्टेशन में भी कोयले का स्टॉक घटकर 45 हजार टन रह गया है, जो दो महीने पहले पांच लाख टन था। कोयले के स्टॉक की कमी के चलते फरक्का और कहलगांव पॉवर प्लांट के पॉवर जेनरेशन लेबल को घटाकर क्रमशः 60 फिसदी और 80 फिसदी करना पड़ गया है, जो पहले 90 फिसदी था। एनटीपीसी के मुताबिक कोल इंडिया की तरफ से कोयले की आपूर्ति में और कमी आयी तो फरक्का तथा कहलगांव पावर प्लांट्स के पॉवर जेनरेशन लेबल को और कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन कोयले की आपूर्ति में जिस तरह से लगातार कमी होते जा रही है, उससे लगता है कि एनटीपीसी को अपने पॉवर प्लांट्स को बंद भी करना पड़ सकता है। स्थिति बहुत भयावह है।

यह कैसी विबडम्बना है कि देश में कोयले का अकूत भंडार होने के बावजूद देश को भारी मात्रा में कोयले का आयात करना पड़ रहा है। सच्चाई तो यह है कि अकेले झारखण्ड

राज्य में कोयले का इतना बड़ा भंडार है कि वह पूरे देश को रौशन कर सकता है, पूरे देश के कल-कारखाने को चलाने के लिए बिजली दे सकता है। देश में कोयले के भंडार को लेकर भू-गर्भ शास्त्रीयों ने जो आंकलन किया है, वह सही नहीं है। झारखण्ड में लगातार उत्तम कोयले के भंडार नया क्षेत्र मिलता जा रहा है। फिर भी कोल माइंस के विस्तार में स्थानीय भूमि अधिग्रहन मुद्दे आड़े आ रहे हैं। मसलन राजमहल कोल माइंस के विस्तार को ही ले लिजिए। जहां देश के कई हिस्सों में थर्मल पॉवर स्टेशनों के लिए कोयले की आपूर्ति की जाती है। आज हमारे आदिवासी भाई जमीन के मालिकाना हक को लेकर बुरी तरह से पीड़ित हैं। जमीन का हक प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे हैं। ऐसे में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर इस समस्या को सुलझाने हेतु कारगर प्रयास करना चाहिए। अलग से ईमानदार और काबिल सरकारी मुलाजिमों की एक टीम बनाकर आदिवासियों के जमीन के प्लॉटों का कागजात ठीक करा देना चाहिए। सरकार का इस बात का ध्यान रखना चाहिए की आदिवासी लोग सिर्फ झारखण्ड या भारत के ही अति उत्तम मानव नहीं है बल्कि सारी दुनियां के अति उत्तम मानव हैं। ये सरल, ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। इनके जीवन में छल-कपट का कोई स्थान नहीं है। इसलिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आदिवासी लोग व्यवस्थित तथा सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सके, फिलहाल तो देश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

सफाइकर्मियों की मौते होती रहेगी तो सफाई का कार्य कौन करेगा?

● ललन कुमार प्रसाद

10 अगस्त 2018 को बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले मे बनकटवा प्रखण्ड के जीतपुर पंचायत के बेला गांव में सैप्टिक टंकी की सेटरिंग खोलकर अंदर जाने से दम घुटने के कारण छः लोगों की मौत हो गई-दिनेश महतो (45), बच्ची देवी (42), बसंत महतो (15), मोहन महतो (22), सचिन कुमार (19) और सरोज (20)। इनमें से चार मौके पर ही दम तोड़ दिये, जबकि दो की मौत छौड़ादानो सदर अस्पताल में डॉक्टर गैरमौजूदगी और ऑक्सिजन उपलब्ध न होने से हो गई। अस्पताल की लापरवाही को लेकर जब लोगों ने हंगामा किया तो स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। सदर अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी की मौत सेप्टिंग टैंक में जहरीली गैसों की वजह से दम घूंटने की वजह से हुई है।

25 अगस्त 2018 को बिहार के नवगछिया जिला के बिहपुर थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव में शौचालय की टंकी से सटे पानी के सोख्ता से मरी हुई बकरी निकालने के दौरान जहरीली गैसों की चपेट में आने से दम घूटने के चलते तीन लोगों की मौत हो गई-राजा कुमार (20), नीरज महतो (29) और फोटीन मंडल (32)।

25 सितम्बर 2018 को बिहार के सीतामढ़ी जिला के सहियारा थाना के बेलाही खूर्द गांव के बीन टोले में तीन माह से बंद पड़ी अर्धनिर्मित टंकी की सेटरिंग खोलकर सफाई करने के लिए अंदर जाने पर दम घूटने के चलते एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई-मुकेश दास (35), संतोष दास (18), लक्ष्मण दास (40) और रमाशंकर दास (35)।

29 सितम्बर 2018 को बिहार के सारण जिला के पानापुर प्रखण्ड के

धनौती गांव में नवनिर्मित शौचालय की टंकी के अंदर काम कर रहे तीन मजदूरों की मौत दम घूटने से होग गई-हसापीर गांव निवासी भोला राय (30), धनौती गांव निवासी टिंकू साह (26) और रसौली तख्त गांव निवासी अमित पासवान (30)। तीनों मजदूरों को बेहोशी की अवस्था में मशरक सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

✯ प्राणधाती है सैप्टिक टैंक, मैनहोल और सीवर लाइन की सफाई का कार्य, क्यों? :- बंद पड़े सैप्टिक टैंक, मैनहोल और सीवर लाइन में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉसजीन, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जहरीली गैसों का निर्माण बहुत भारी मात्रा में होता है। जिन्हें सैप्टिक टैंक या मैनहोल के बंद होने के कारण बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन, सैप्टिक टैंक या मैनहोल के अंदर इन गैसों के निर्माण की प्रक्रिया बगैर किसी रोकटोक के अनवरत चलती रहती है। इस कारण ये गैसें सिमित जगह में दबती चली जाती है। इसलिए बहुत ही कम जगह में बहुत अधिक मात्रा में जहरीली गैसे संग्रहित हो जाती है। फलस्वरूप सफाई करने के लिए जब सैप्टिक टैंक और मैनहोल खोला जाता है तो उसमें दबी हुई जहरीली गैसे चलाई गई बंदूक की गोली के वेग से बाहर निकलती है। सफाइकर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। उन्हें एकाएक बहुत ज्यादा ऑक्सिजन की कमी का सामना करना पड़ जाता है। उन्हें ऑक्सिजन का मिलना एकाएक बंद हो जाता है। जिसके चलते उनका मस्तिष्क एकाएक लगभग काम करना बंद कर देता है। इसलिए सहायता के लिए मुंह से आवाज निकालने तक

का भी होश नहीं रह जाता, जिससे की आपात स्थिति में बगैर किसी विलंब के सफाइकर्मी को मदद पहुंचाई जा सके। नतीजा पांच से दस मिनट के अंदर सफाइकर्मी की मौत हो जाती है। इतनी जल्दी सफाइकर्मी की मौत क्यों हो जाती है? दरअसल, एक व्यस्क आदमी 24 घंटे में 21600 बार सांस लेता है और छोड़ता है। एक दिन में 15700 लीटर हवा लेता है और छोड़ता है। यदि उसे तीन मिनट तक हवा न मिले तो उसकी मौत हो जाती है।

पटना नगर निगम कर्मचारी युनियन के अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश सिंह का कहना है कि सुप्रिम कोर्ट ने अंडर ग्राउंड सफाई के मैनुअल तरीके पर रोक लगा दी है। फिर भी नगर पालिका, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड या कोई अन्य संस्था अथवा कोई व्यक्ति इस तरह की सफाई कराता है तो उसके लिए वकायदा गाइड लाइन जारी किया गया है। इस गाइड लाइन का फॉलो करने पर ही किसी कर्मचारी को अंडर ग्राउण्ड सफाई के लिए सैप्टिक टैंक, मैनहोल और सीवर लाइन के अंदर भेजा जा सकता है। आगे चन्द्र प्रकाश सिंह कहते हैं कि सिर्फ मशीनों से ही इन जगहों की सफाई करायी जानी चाहिए। परन्तु देश के इक्का-दुक्का बहुत ही बड़े शहर में ऐसी मशीने हैं और वह भी नाम मात्र की संख्या में। इसलिए हमें मजबूरी में मैनुअल तरीका ही अपनाना पड़ता है। लेकिन बहुत ही दु:ख की बात है कि आज भी बगैर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने ही नंगे बदन सफाइकर्मी को गटर में उतार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वेजवाड़ा विलसन बताते हैं कि वर्ष 2000 से 2017 तक सैप्टिक टैंक, मैनहोल, सीवर लाइन और गटर की सफाई करने के दौरान 1760 लोगों की मौत हो चुकी है। अर्थात् देश भर में औसतन सलाना 104 सफाइकर्मी की मौत उपरोक्त जगहों की सफाई करने के दौरान हो जाती है। अर्थात् एक साल में जितने जवान कश्मीर में देश की सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं, उतने ही सफाइकर्मी समाज को स्वच्छ रखने में मौत के ग्रास बन जाते हैं। लेकिन बहुत ही दु:ख की बात है कि ऐसे मामलों में आज तक एक भी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई सजा नहीं सुनाई गई है।

किसी व्यक्ति को गहरे सीवर, सैप्टिक टैंक, नाले, सीवर लाइन आदि की सफाई के लिए लगाना गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मौत होने पर सफाई कराने के लिए भेजने वाले पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जायेगा। इसके लिए किसी बिल्डिंग के मालिक, ठेकेदार और संबंधित एजेंसियां जैसे नगर पालिका, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड सामुहिक रूप से जिम्मेदार होंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपातकालिन स्थिति में अगर सीवर लाइन में कार्य करना आवश्यक हो गया है तो इसके लिए संबधित एजेंसी से लिखित स्वीकृति लेनी होगी और यह लिखित देना होगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का समुचित इस्तेमाल कराया जायेगा तथा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सावधानियों का सख्ती से पालन किया जायेगा। इतना ही नहीं सफाई कराने वाले संस्था के द्वारा सुरक्षाकर्मियों के नाम से प्रमाणित लिखित वर्क परमिट काम शुरू करने के पहले देना होगा।

☆ क्या है वर्क परमिट? :- वर्क परमिट यानि काम करने के लिए प्रमाणित लिखित अनुमति पत्र है। यह एक तरह का प्रमाणित दस्तावेज है, जो काम करने वाली संस्था के द्वारा काम करने वाले कामगार को सावधानी बरतने हेतु, काम शुरू करने के पहले दिया जाता है। यह एक तरह का कानूनी और प्रमाणित दस्तावेज है, जो काम करने के लिए राजी हो गए कामगार को अधिकृत करता है कि वह सौंपे गये कार्य को बताये गये स्थान पर दी गई अवधि में पूरा करे।

☆ वर्क परमिट में क्या रहता है :- वर्क परमिट में सौंपे गये काम से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में जरूरी जानकारियां दी गई रहती है और उन खतरों से बचने के लिए कार्य स्थल पर कौन-कौन से सुरक्षात्मक कदम उठाये गये हैं, इसकी भी जानकारी दी गयी होती है। फिर सौंपे गये काम को सुरक्षित रूप से संपन्न करने के लिए कौन-कौन से समान्य तथा कौन-कौन से विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई होती है।

☆ वर्क परमिट सिस्टम का उद्देश्य :- वर्क परमिट सिस्टम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि काम करने के दरम्यान जोखिम का स्तर व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने योग्य रहे और हमेशा नियंत्रण में रहे।

☆ सफाइकर्मियों को सुरक्षा उपकरण हो उपलब्ध :- दरअसल सफाइकर्मियों को सैप्टिक टैंक, मैनहोल और सीवरलाइन की सफाई हेतू उपकरण के नाम पर फावड़ा, कुदाल, बाल्टी और बांस की फट्टी के अलावा कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के नाम पर

बिरले ही किसी-किसी सफाइकर्मी को सेफ्टी हेलमेट मात्र दिया जाता है। जबकि सफाइकर्मियों को पीवीसी ग्लब्स, सेफ्टी हेलमेट, कलरलेस सेफ्टी गुगल्स, सेफ्टी बेल्ट, फेश मास्क और जरूरत के मुताबिक सेफ्टी सूज नामक व्यक्तिगत् सुरक्षा उपकरण अवश्य ही मुहैया कराया जाना चाहिए, जिन्हें पहनकर ही सफाइकर्मियों को सैप्टिक टैंक अथवा मैनहोल में उतारा जा सके। एक किलोग्राम क्षमता वाले ऑक्सिजन सिलेंडर के साथ ऑक्सिजन मास्क भी कार्य स्थल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल कर आपात स्थिति में बगैर किसी विलंब के बेहोश हो गये सफाइकर्मी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित एक कीट की कीमत लगभग 20-25 हजार रूपये है। हर नगर पालिक और नगर निगम को उपरोक्त व्यक्तिगत् सुरक्षा कीट पर्याप्त संख्या में अवश्य रखनी चाहिए।

✯ मैनहोल, सैप्टिक टैंक, सीवर लाइन आदि कार्यों से जुड़ी सावधानियां :-

☞ सैप्टिक टैंक, मैनहोल, सीवरलाइन, पुराना कुआं आदि की सफाई का कार्य जहां भी चल रहा हो, वहां पर एक एम्बुलेंस अवश्य तैनात होना चाहिए। एम्बुलेंस जीवन रक्षक दवाइयों और जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए। विशेषकरण ऑक्सिजन मास्क (ऑक्सिजन सप्लाई उपकरण) अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल द्वारा बेहोश गये सफाइकर्मी की जान बचायी जा सके। साथ में दो प्राथमिक चिकित्सक अवश्य होनी चाहिए, जिससे की जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा के कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सके।

☞ एक तीन पैर वाला ऐसा स्टैंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसके शिखर से एक मजबूत नाइलन की रस्सी लटकाने की सुविधा दी गई है तथा जिसकी सहायता से का करने वाले व्यक्ति को मैनहोल या सैप्टिक टैंक के अंदर उतारने और अंदर से बाहर निकालने में सहुलियत हो। रस्सी से बंधा बेल्ट लगाकर ही सफाईकर्मी को मैनहोल या सैप्टिक टैंक में उतारना चाहिए, जिससे की आवश्यकता पड़ने पर सफाइकर्मी को खिंचकर मैनहोल या सैप्टिक टैंक से बाहर निकाला जा सके।

☞ मैनहोल या सैप्टिक टैंक के पास एक आदमी को सेफ्टी अटेंडेंट के रूप में हमेशा मौजूद रहना चाहिए और उस सेफ्टी अटेंडेंट को संचार उपकरण से सुसजिज्त होना चाहिए।

☞ सेफ्टी अटेंडेंट के पास एक लालटेन, जिसमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल भरा हो, एक दिया सलाई और एक केमिकली ट्रीटेड यानि फायरप्रूफ पतली डोरी होनी चाहिए, जिसकी सहायता से काम शुरू करने से पहले यह जांचा जा सके की सेप्टिक टैंक, मैनहोल और कुंआ के भीतर की हवा में ऑक्सिजन है या नहीं या सिर्फ जहरीली गैसे हैं। पतली डोरी की सहायता से जलता हुआ लालटेन मैनहोल, सैप्टिक टैंक और कुंआ के अंदर पहुंचाने पर यदि लालटेन बुझ जाये तो समझीय की इस वक्त किसी भी व्यक्ति को इन जगहों के अंदर उतारना खतरनाक है। ऐसे में पेडेस्टेटल फैन की सहायता से सेप्टिक टैंक या मैनहोल या कुंआ के अंदर तेजी से हवा भेंजे। ऐसे करने पर इन जगहों के अंदर की जहरीली गैसे बाहर निकल जायेगी, जिससे की इन जगहों के अंदर सफाई का काम करना सुरक्षित हो जायेगा। फिर भी दोबारा जलता हुआ लालटेन इन जगहों के अंदर पहुंचाकर अवश्य जांच ले। यदि इन जगहों के अंदर पहुंचाने के बाद भी लालटेन ज्यों का त्यों जलता रहे तो समझीय की इन जगहों के अंदर किसी भी सफाइकर्मी को उतारने में कोई खतरा नहीं है।

☞ सैप्टिक टैंक या मैनहोल में काम शुरू करने से पहले कम से कम छः घंटे के लिए खोलकर छोड़ देना चाहिए, जिससे की डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा सैप्टिक टैंक या मैनहोल में मौजूद जहरीली गैसें स्वतः सैप्टिक टैंक या मैनहोल बाहर निकल जाये और सैप्टिक या मैनहोल के अंदर किसी व्यक्ति को उतारना खतरनाक न रह जाये।

☞ जरूरत के मुताबिक किसी भी सफाइकर्मी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर ही मैनहोल या सैप्टिक टैंक या कुंआ के अंदर उतरना चाहिए।

✯ जरूरी है अंडरग्राउंड का मशीनीकरण :- सबसे पहले सैप्टिक टैंक और मैनहोल की सफाई के लिए बड़े-बड़े शहरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों तक संक्शन मशील वाले टैंक उपलब्ध कराने चाहिए। बड़े शहरों में गहरे नालों की सफाई के लिए बड़ी डिसेल्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मशीन में लगा हाई प्रेशरयुक्त पाइप

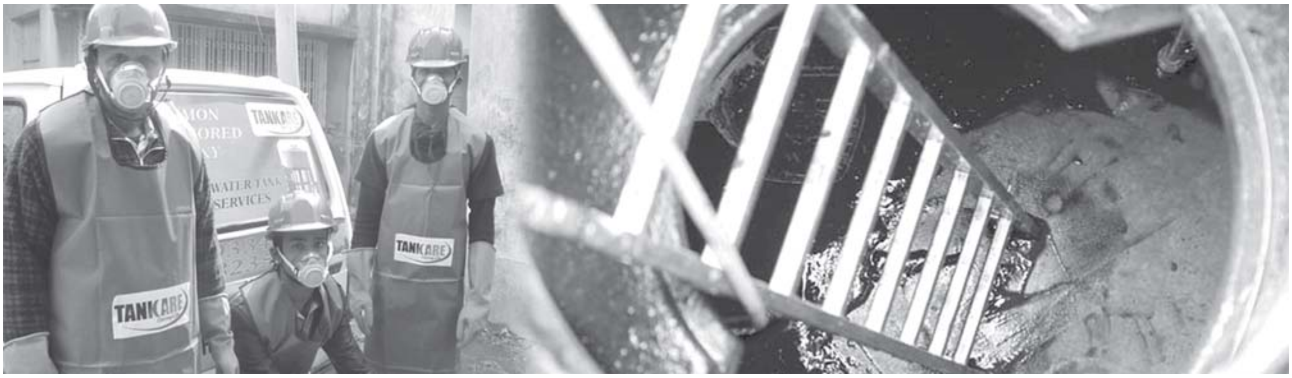

को नाले या मैनहोल के अंदर डालकर सिल्ट यानि जमे हुए कीचड़ को खींचकर बाहर निकालने में बड़ी सहुलियत होती है। लेकिन, फिलहाल ऐसी मशीनों की उपलब्धता देश की कुछ ही बड़े शहरों में है और कम संख्या में है। जो कि नगर पालिका और नगर निगम के पदाधिकारियों की अक्रमण्यता का नतीजा है। मैनहोल की सफाई करने वाले इन दोनो तरह के रोबोटों का निर्माण भारतीय युवा इंजिनीयरों की बहुत बड़ी उपलब्धी है। अंडरग्राउंड सफाई का कार्य बहुत अधिक दुष्कर हो गया है, हर साल लगभग सौ कर्मियों की मौत हो जाती है, इसलिए उपरोक्त दोनो तरह का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर युद्धस्तर पर कराया जाना चाहिए।

आजाद भारत में आरंभ से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आयी हैं, उनमें से किसी को भी देश की स्वच्छता को लेकर किसी ने भी कोई तवज्जों नहीं दिया, सिर्फ मोदी सरकार को छोड़कर। मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में स्वच्छता को लेकर जो काम कर दिखाया है, वह सचमुच उल्लेखनीय व सराहनीय है, क्योंकि परिणाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। मसलन सरकारी आर्थिक मदद से पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनवाये गये हैं, जो मोदी सरकार द्वारा चलाये गये स्वच्छता मिशन का प्रमाण है। पिछले साढ़े चार साल में देश के करीब साढ़े पांच करोड़ गरीब परिवारों को सिलेंडर और रेगुलेटर के साथ मुफ्त चुल्हा मुहैया कराया गया है। फलस्वरूप रसोई घर धूंआमुक्त तथा स्वच्छ हो गया है। गरीब महिलाओं का जो समय ईंधन को चुन-चुनकर एकत्र करने में बर्बाद हो जाता था, अब बचने लगा है। फलस्वरूप गरीब महिलाएं इस बचे हुए समय का सदुपयोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में करने लगी हैं।

लेकिन अफसोस आज भी नगर पालिक, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड अपनी वचनबद्धता को जरा भी नहीं निभा रहे हैं। सफाइकर्मियों के प्रति उपरोक्त संस्थान इतना गैर जिम्मेदार और इतना असंवेदनशील क्यों हैं? क्या इसलिए की ये सफाइकर्मी बहुत ही गरीब, अनपढ़ और दलित हैं, और इसलिए बार-बार नरक में उतरने को मजबूर हैं। हमें इंसानियत का ख्याल क्यों नहीं आता? महात्मा गांधी ने कहा था ''जो समाज गंदगी को साफ करता है, उसका स्थान माँ के बराबर होता है''। लेकिन, हकीकत यह है कि इन सफाइकर्मियों को समाज इंसान भी नहीं समझता। यही कारण है कि आज भी देश के कई मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है। समाज के तथाकथित सभ्य लोग इन दलितों को समाज की मुख्यधारा से अलग रखते हैं। क्या गांधी जयंती के अवसर पर बापू की प्रतीमा पर फूल-माला चढ़ाने भर से ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? क्या हांथ में झाड़ू थामे हुए फोटो खिंचवाकर हम स्वच्छता अभियान के अंग बन जाते हैं? यह सब नौटंकी नहीं तो और क्या है। इनकी उपेक्षा कब तक जारी रहेगी? क्या इन्हें सम्मानपूर्वक जिने का अधिकार नहीं है? इंसानी गरीमा भी तो कोई चीज होती है। हालात बदलने की जिम्मेदारी सबकी है-सरकार की भी और समाज की भी। जब तक समाज इस बात को नहीं समझेगा, हल निकालना संभव नहीं है। पहले ही बहुत ज्यादा विलंब हो चुका है। इसलिए इस बात को हम सभी को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। फिर जो दलित हैं, उन्हें अपनी ओर से भी निराशा भरा जीवन जीने से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। गंदगी के साथ जीने की पूरी आदतों को नकारना होगा। गरीब होते हुए भी रहन-सहन के हर स्तर पर स्वच्छता को अपनानी होगी, जिससे समाज के तथाकथित सभ्य लोग दलितों के साथ रहने में सहज महसूस करने लगे। याद रहे ताली दोनो हांथों से बजती है, इसलिए समाज के कथित सभ्य लोगों और दलितों, दोनों ओर से समान रूप से सार्थक प्रयास करने होगे। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :-
www.psfsm.in

युवा कलाकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत बने मुंगेरीलाल राजन कुमार

● के.एम. राज

एक दशक पूर्व मशहूर टीवी सीरियल मुंगेरीलाल के हसीन सपने जिसमें इस वाक्य को असफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन मुंगेर टेटियाबम्बर के रहने वाले राजन कुमार ने मुंगेरीलाल के हसीन सपने को सफलता का प्रतीक में बदल दिया। उन्होंने बचपन में जो सपना देखा था वह आज हकीकत में बदल गए। राजन कुमार ने अभिनय से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि जिले का नाम भी विश्व पटल पर अंकित कर दिया। इन्हें 2004 में चार्ली चैपलिन द्वितीयक के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एवं 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चार्ली चैपलिन टू के नाम से दर्ज कर लिया गया इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कार मिले। हीरो राजन कुमार के लिए 2018 बेहद खास रहा। उन्हें इस साल कई अहम पुरस्कारों से नवाज़ा गया बल्कि उनकी फिल्म 'नमस्ते बिहार' ने भी दर्शको का दिल जीत लिया। इन्हें 18 नवम्बर 2018 का अभिनय के क्षेत्र में आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मभूषण परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के हाथों सम्मानित किया।

✭ स्वामी जी ने भी सीसी–2 नाम से किया अलंकृत

:– आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पद्मभूषण परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने हीरो राजन कुमार को एक नए नाम से अलंकृत किया। उन्होंने राजन को 'सीसी–2' का नया नाम दिया। आपको बता दें कि राजन कुमार चार्ली चैप्लिन 2 के नाम से भी विख्यात हैं उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मुंगेर से ही सम्बन्ध रखने वाले हीरो राजन कुमार ने इस सम्बन्ध में कहा कि अवार्ड को मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि, पद्मभूषण परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के हाथों अपनी माता जी के साथ आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, यह मेरे लिए कोई सपना पूरे होने जैसा एहसास है। अपने अभिनय के दम पर उन्होंने भारत ही नहीं दुनिया भर में अपने लोहा मनवा लिया हैं। चार्ली चैपलिन के भूमिका में वह देश विदेश में अब तक दस हजार से ज्यादा शो कर चुके हैं। वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा छऊ नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2004 में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा बेस्ट युवा अभिनेता का पुरस्कार, 2004 में ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2005 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2013 कृष्णा आर्ट मुंबई द्वारा स्वर्ण पदक। 2018 ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा एक लाख बीस हजार वोट लेकर शूरवीर अवॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने 12 वर्षीय अनुष्का अरोरा को पानी में डूबते देख शो के दौरान चार्ली चैपलिन कॉस्टयूम में ही कूदकर उनकी जान बचाई थी। उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। 2018 में ही स्वलिखित हंसता बचपन के लिए मगही अकादमी बिहार सरकार द्वारा डॉ राम प्रसाद सिंह साहित्य पुरस्कार मिला। हंसता बचपन ने अपने लोकार्पण में ही वर्ल्ड रिकार्ड बना लिया। 1 मिनट में एक साथ 300 पाठकों के साथ लोकार्पण कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 2018 में ही छात्र शांति दूत मिशन द्वारा इसे ब्रांड अम्बेसडर बनाकर बिहार इकाई का अध्यक्ष भी बनाया है।

किसी मुंगेरिया के द्वारा पहली फिल्म शहर मसीहा नहीं जो मुंगेर के ही डॉक्टर अरुणेंद्र भारती के उपन्यास पर आधारित थी। उसे बनाने का कीर्तिमान इनके नाम है। शहर मसीहा नहीं को दर्शकों ने खूब सराहा। इनकी दूसरी हिंदी फिल्म नमस्ते बिहार ने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। 8 नवंबर को रिलीज हुई मुंबई के मल्टीप्लेक्स यह फिल्म के सभी शो

हाउसफुल हुए। बकौल राजन ने कहा उन्हें डर था कि नमस्ते बिहार सिरसा होने के कारण कहीं केवल बिहार के लोग इसे पसंद करेंगे। लेकिन बिहार के अलावा गुजरातए पंजाब और महाराष्ट्र के लोगों ने भी सिनेमा घर जाकर फिल्म को सुपरहिट करवाया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का मुहूर्त सुबह 4:00 बजे कर शूटिंग भी प्रारंभ करने के कारण नमस्ते बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने भी सुबह 4:00 बजे फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं किया। हमारा नमस्ते बिहार सुबह 4:00 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इसका मुहूर्त किया गया या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव अपने जिले में कराने का इच्छा पाले राजन ने कहा कि 2019 में इस जिले में दर्जनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को लेकर अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव करवाना है। इसके लिए वह मुंबई सहित अन्य राज्यों के अलावा विदेश का भी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने भी 2019 में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में हर संभव मदद करने की बात कही। ●

बिहारी-बंगाली परंपरा का अद्भुत दृश्य दिखता है जगधात्री पूजा में

● के.एम. राज

रेल कॉलोनी पानी टंकी मैदान जमालपुर में 1961 से मनाते आ रहे मां धात्री पूजा महोत्सव का शुभारंभ पूजा पाठ से लेकर भक्ति जागरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। चार दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्य कारखाना प्रबंधक अरविंद कुमार पांडे ने किया तो समापन मुंगेर पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं पुलिस अधीक्षक अभियान राणा नवीन ने संयुक्त रूप से मां की आराधना कर किया। चार दिवसीय इस महोत्सव में जहां पूजा समिति की ओर से महिलाओं एवं कन्याओं के लिए शंख ध्वनि एवं मोमबत्ती जलाना प्रतियोगिता का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सफल प्रतिभागियों को जहां बड़ी दुर्गा के महंत डॉक्टर मनोहर दास ने उपहार भेंट कर सम्मानित किया। वहीं महोत्सव में आए मुख्य कारखाना प्रबंधक एके पांडे एवं पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से कहा पूजा. पाठ तो आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस तरह के आयोजन से समाज में भाईचारा ही स्थापित नहीं होता है बल्कि धार्मिक माहौल बनता है और पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था नियंत्रण करने में भी सहायता मिलती है वैसे प्रत्येक मनुष्य को किसी ना किसी के प्रति आस्था रखना चाहिए यह अच्छी बात है कि देवी देवता के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है उससे समाज में एक धार्मिक माहौल बनता है उससे नकारात्मक शक्तियों दूर होती है और मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चलने का रास्ता भी प्रशस्त करती है इसलिए। ऐसे आयोजन कर्ता धन्यवाद के पात्र है।

इसके पहले पूजा समिति के संयोजक रिंकू सिंहए अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा, सचिव एसके आर्य, पंकज श्रीवास्तव संयुक्त रूप से तमाम अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया। इधर मां जगधात्री पूजा के मंच पर जब मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों की टोली ने जब भगवान कृष्ण सुदामा के अद्भुत झांकी की प्रस्तुति मंच से साझा किया तो उपस्थित श्रोताओं के आंखों को गीली कर कर दिया। देर रात तक चले भक्ति जागरण के इस कार्यक्रम में मथुरा एवं बिंद्रावन से आए कलाकार महेश चंद्र व्यास, ईश्वर चंद्र, राम जी वैद्य, तिवारी जी, केशव, बंटी, कन्हैया, मुंशी आदि कलाकारों ने जब बारी बारी जग धात्री पूजा के मंच से फूलों की होली, मयूर नृत्य सहित कई भक्ति भजनों की प्रस्तुति पर श्रोता एवं धर्म प्रेमी आनंदित होकर झूम उठे। कार्यक्रम का संचालन महेश अंजाना ने किया। इधर महोत्सव के समापन के बाद मां जगधात्री प्रतिमा का विसर्जन रेल कॉलोनी की महिलाओं ने काफी उत्सुकता के साथ कराया। इधर इस पूजा महोत्सव को संपन्न करवाने में थानाध्यक्ष सुनील कुमार, एसआई गोपाल कुमार सिंह, प्रोफेसर राजीव नयन, मोहम्मद जुम्मन आलम, लायंस क्लब के अध्यक्ष रंजीत प्रसाद, पुष्पेंद्र कुमार सिंह, पंकु पासवान, पवन श्रीवास्तव, चंदन कुमार, मनोज कुमार, शुक्ला बाबा, सतीश चंद्र, जग्गू दादा, मुरारी कुमार, चंद्रचूर साक्षी सहित क्षेत्रवासियों का सहयोग सराहनीय रूप से मिला इसके लिए पूजा समिति के संयोजक रिंकू सिंह ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। ●

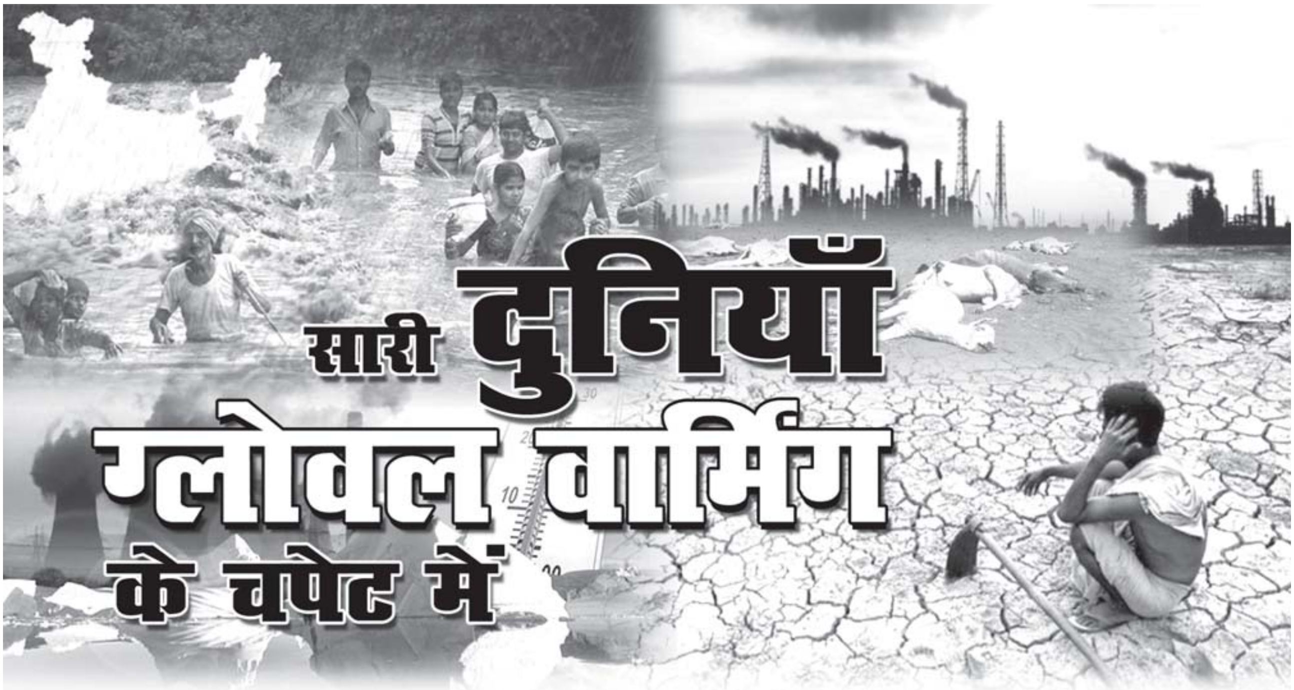

● ललन कुमार प्रसाद

ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, धरती का गर्म होना यानि धरती का तापमान बढ़ना। यानि धरती से कार्बन का उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होना, जो सिर्फ और सिर्फ मानव गतिविधियों के कारण पैदा होता है। वैश्विक तापमान का इस्तेमाल धरती के वातावरण और समुद्र के औसत तामपान में होने वाली क्रमिक वृद्धि के संबंध में किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि धरती के तापमान में होने वाल बदलाव स्थायी तौरपर धरती के जलवायु (क्लाईमेट) को बदल रहा है। जो धीरे-धीरे हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर तापमान का लेखा-जोखा रखने की शुरूआत वर्ष 1880 में शुरू हुई थी। नासा के अनुसार पिछले दस वर्षों में 2.08 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है धरती का तापमान। जिसे आंकड़ों में देखा जा सकता है। ब्रिटेन की संस्था 'कार्बन ब्रीफ के अनुसार पिछले 150 वर्षों में दिल्ली का तापमान 1.0 डि०से०, मुम्बई का 0.7 डि०से०, चेन्नई का 0.6 डि०से० और कोलकाता का 1.2 डि०से० बढ़ा है।

✯ ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारक :-

☞ ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक है आबादी में बेतहाशा वृद्धि। 1990 में विश्व की आबादी 1 अरब 60 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 7 अरब को भी पार कर गई है। लगातार बेतहाशा बढ़ती आबादी की

बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधा-धूंध दोहन किया जा रहा है। जब आबादी बढ़ती है तो बढ़ी हुई आबादी को एकोमोडेट करने तथा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी संख्या में मकान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पीटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री, मॉल, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन, पुल, फ्लाई ओवर, सड़क, डाकघर, सचिवालय, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बंदरगांह, स्टेडीयम, होटल आदि ढ़ेर सारे कंस्ट्रक्शन के कार्य करने पड़ते हैं, जिसके चलते भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए ढ़ेर सारे ईंट की चिमनिया और सिमेंट के कारखाने स्थापित कर चलाने पड़ते हैं। घरों को रौशन करने के लिए तथा बढ़े हुए विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए थर्मल पॉवर स्टेशनों को स्थापित कर बिजली पैदा करनी पड़ती है, जो कार्बन उत्सर्जन की बहुत बड़ी वजह है। ढ़ेर सारे उद्योगों की चिमनियों से भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता रहता है। बढ़ी हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे खाना पकाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन जैसे-बाईक, कार, ऑटो, ट्रक, बस आदि वाहनों को जलाने में भारी मात्रा में ईंधन जलाया जाता है जो कार्बन उत्सर्जन का बहुत बड़ा स्त्रोत है। बढ़ी हुई आबादी को खाने-पीने, रहने, पढ़ने- लिखने, खेलने-कूदने, घूमने-फिरने,

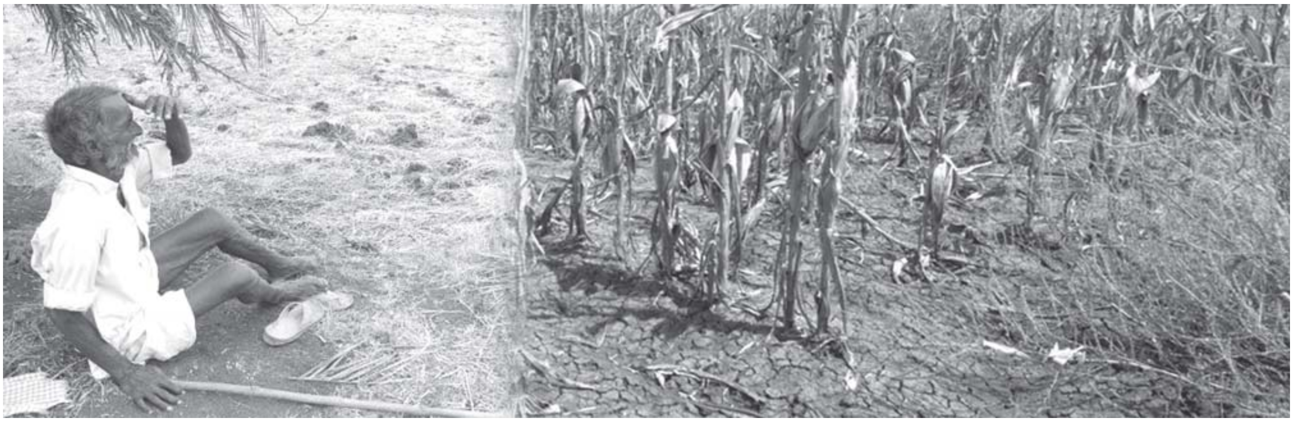

चिकित्सा आदि के ढ़ेर सारे कार्यो को अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए वायुमंडल में बहुत ही भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करना पड़ता है। इस तरह हम पाते हैं कि दुनियां भर में कार्बन उत्सर्जन की सबसे बड़ी वजह है, बेतहाशा बढ़ती आबादी, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक है।

☞ सघन वनों के रकवा में आयी कमी के चलते कार्बन के अवशोषण में भारी कमी है।

☞ वाहनों की संख्या में हर दिन हो रही बेतहाशा वृद्धि के चलते हर रोज कार्बन के उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है। वाहनों के रख-रखाव की कमी तथा ट्रैफिक जाम के चलते भी कॉर्बन के उत्सर्जन में अनवरत वृद्धि हो रही है।

☞ जहां देखिए वही तथा कूड़ा डम्पिंग यार्ड में भारी पैमाने पर हर रोज कूड़े को जलाये जाने पर भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। मसलन बिहार की राजधानी पटना को ही ले लिजिए। यहां विस्कोमान कॉलोनी के पास ही अगमकुंआ सेकेंड्री कूड़ा केन्द्र है। जहां आये दिन कूड़ा में आग लगाकर जलाया जाता है। कूड़ा में लगायी गयी आग से भारी मात्रा में धूंआ उठता है यानि कॉर्बन सहित अन्य विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं। मोहल्ले में रहने वाले कई लोगों को सांस की बीमारी हो गई है। कई दुकानदार नाक पर रूमाल बांधकर दुकानदारी करने को मजबूर होते हैं। मौर्य बिहार कॉलोनी से आगे पाटलीपुत्र अपार्टमेंट के सामने हर रोज कूड़ा जलाया जाता है। बुद्धमार्ग स्थित पटना नगर निगम के पुराने कार्यालय के पीछे हर दिन प्रातःकाल बिजली के तार से तांबा निकलने के लिए कचड़ा चुनने वाले बिजली के तार में आग लगा देते हैं, जिससे बेहद जहरीला धूंआ निकलता है। यही कार्य आये दिन कदमकुंआ स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के सामने स्थित बुद्धमुर्ति के पास कचड़ा चुनने वाले करते हैं। पटना नगर निगम की चेतावनी के बाद कूड़ा-कचड़ा डम्पिंग केन्द्र, न्यू बाईपास के किनारे और पटना के ढ़ेर सारे मुहल्लों के कूड़ा केन्द्रों में कूड़ा-कचड़ा जलाने की घटनाएं जारी है। यह हाल सिर्फ पटना शहर की नहीं है। पूरे बिहार के छोटे-बड़े सभी शहरों का है। मसलन भागलपुर के चंपा नगर में नगर निगम द्वारा डंप किए गये कूडा-कचड़ा जलाने का है। हर दिन यहां शहर से 220 मीट्रिक टन कचड़ा फेका जाता है, जिसे आये दिन आग लगाकर जला दिया जाता है। फलस्वरूप इस कूड़ा डम्पिंग यार्ड में कूड़ा-कचड़ा जमा करने हेतु पर्याप्त जगह बन जाती है।

नासा के अनुसार पिछले दस वर्षों में धरती का तापमान :-		
वर्ष	-	तापमान में वृद्धि (डि०से० में)
2008	-	0.62
2009	-	0.63
2010	-	0.70
2011	-	0.57
2012	-	0.61
2013	-	0.64
2014	-	0.73
2015	-	0.86
2016	-	0.88
2017	-	0.90
वृद्धि	=	0.92-0.62=0.28 डि०से०

यह हाल सिर्फ बिहार का ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की हालत तो और गई-गुजरी है। बनारस में सड़कों तथा गलियों में हर दिन थोड़ी-थोड़ी दूर पर कूड़ा-कचड़ा जलते हुए देखने को मिलता है, अब पूरे देश की कल्पना कीजिए। हमारे देश में अरबो टन कूड़ा-कचड़ा हर रोज जलाया जाता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ कूड़ा-कचड़ा जलाने से कितनी भारी मात्रा में कॉर्बन का उत्सर्जन होता है।

5. झारखण्ड के झरिया कोइलरी में लगी आग जो आज कई वर्ग किलोमीटर में फैल गई है और जो पिछले 120 वर्षों से जल रही है। इसके चलते हर रोज कई करोड़ का सर्वोत्तम कोयला बगैर किसी उपयोग के राख में तब्दील होता जा रहा है, और कम हवा में जलने के कारण दिन-रात, चौबिसो घंटे बगैर रूके भारी मात्रा में कॉर्बन उत्सर्जित कर रहा है, जिससे ग्लोबन वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। झरिया कोलियरी में लगी आग को बुझाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारे कुछ किया हो या नहीं, लेकिन रघुवर सरकार ने भी चार वर्षों में रत्तीभर भी कोई काम नहीं किया। जबकि रघुवर सरकार को मोदी सरकार का भरपूर समर्थन प्राप्त है और मोदी सरकार चाहती है कि रघुवर सरकार झरिया कोलियरी की आग को बुझाने का पुरजोर प्रयास करे। परन्तु रघुवर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि झरिया कोलियरी की आग शर्तिया बुझाई जा सकती है। इससे बड़ी रघुवर सरकार की नासमझी और अकर्मण्यता क्या होगी? झरिया कोलियरी की आग बुझाने को लेकर झारखण्ड सरकार, मोदी सरकार बगैर किसी उपयोग के इतनी भारी मात्रा में श्रेष्ठत्तम कोयले की बर्बादी, पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने वाली और पूरी दुनियां को भारी नुकसान पहुंचाने वाली इस विकराल समस्या से अपने आप को कैसे अलग-थलग रखे हुए है। केवल सत्ता का सुख भोगने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

✯ ग्लोबल वार्मिंग का असर :-

☞ **अकाल पड़ने का खतरा :-** संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्तमान में एशिया में 7 करोड़ 90 लाख पांच साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 48 करोड़ 60 लाख की आबादी भूख से जुझ रही है। इंटर गर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीपीसी), जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी अंतर सरकारी समिति

है, जिसमें दुनियां भर के 40 देशों के ख्याति प्राप्त पर्यावरण वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है, ने पिछले दिनों दक्षिण कोरिया के इचियॉन में एक रिपोर्ट जारी की है, जो 400 पन्नों की है। कहा गया है कि यदि मौजूद दर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो 2030 से 2052 के बीच धरती के औसत तापमान में 1.5 डि०से० की वृद्धि हो सकती है। अनुमान जताया गया है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से इतने गर्म हो जायेंगे कि वहां मानव जीवन मुश्किल हो जायेगा और समुद्र का बढ़ता जल स्तर कई द्वीपों तथा कई देशों के निचले समुद्रतटीय इलाके को निगल लेगा। यह स्थिति पूरी दुनियां के लिए बहुत अधिक खतरनाक होगी, लेकिन भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए की यदि धरती के तापमान में 1.5 डिग्री वृद्धि होगी तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैले गंगा बेसिन (घाटी) क्षेत्र में बारिस में 20 फिसदी की कमी आ सकती है। 20 फिसदी बारिस की कमी का मतलब सूखा पड़ना होता है। गंगा बेसिन या गंगा घाटी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, पंचाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल। कृषि के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, जिसका ज्यादातर क्षेत्र खेती के लिए बारिस पर निर्भर है। नतीजा इतने बड़े क्षेत्र में अकाल पड़ सकता है।

☞ **लू के प्रकोप का बढ़ना :-** ग्लोबील वार्मिंग का असर भारत पर तेजी से पड़ रहा है। देश का वार्षिक औसत तापमान 20वीं सदी की तुलना में 1.2 डिग्री की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट के मुताबिक 1995 पहला और 2016 दूसरा सबसे गर्म सान रहा है। विगत् 116 वर्षों के इतिहास में 15 सबसे अधिक वर्षों में 13 वर्ष 2002 से 2016 के दौरान रहे हैं। इसके चलते हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडू में हर साल समान्य से 9 दिन अधिक लू (गर्म हवा) चली। नतीजा अब देश में कई सौ लोगों की मृत्यु लू से होने लगी है।

ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिस, बाढ़ और वर्फबारी की घटनाएं उतरोतर बढ़ती ही जा रही है। सूखे की बारंबारता में वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप खेती किसानी पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अनाजों के उत्पादन में कमी के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फसलों में कीट लगने और दाना नहीं बनने से फसल चौपट होने लगी है। मसलन दाना नहीं लगने के चलते इस साल बिहार में मक्के की फसल चौपट हो गई। कही बहुत कम बारिस तो कही बहुत अधिक बारिस अब आम बात हो गई है। केरल भारी बारिस से आक्रांत हुआ तो बिहार, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका लगभग सूखा ही है। बुंदेलखण्ड और महाराष्ट्र का सूखा तो किसानों की आत्महत्या की वजह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45 फिसदी, बिहार में 44 फिसदी, झारखण्ड में 40 फिसदी और पश्चिम बंगाल में 24 फिसदी कम बारिस हुई है। नतीजा बिहार के 38 जिलों में से 23 जिलों (पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालंदा और सहरसा) के 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है तथा बाद में सात जिलों (पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय) को मिलाकर 69 और प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इस तरह इन 30 जिलों में से 12 जिले (नालंदा, नवादा, गया, जमुई, शेखपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बांका और सहरसा) पूरी तरह सूखाग्रस्त घोषित किये गये। नतीजा सरकारी अनुमान के अनुसार बिहार में इस बार 15 लाख टन कम धान का पैदावार होगा, जिससे करीब 2600 करोड़ रूपये के नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। इतना ही नहीं, कम बारिस की वजह से खेतों में गायब नमी के चलते किसान चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि यदि खेतों में नमी गायब है तो फसलों की अगली बुआई कैसे संभव हो पायेगा?

धरती के बढ़ती तापमान की वजह से जीवों की कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। 1970-2014 के बीच दुनियांभर में फैले विभिन्न जीवधारियों के आश्रय स्थलों में से 4000 प्रजातियों पर किए गये अध्ययन से पता चला है कि मछली, चिड़ियां, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जीवधारियों की संख्या में 60 फिसदी की कमी आयी है। विशेषकर डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि मच्छरजनित तथा पेट संबंधी बीमारियों में इजाफा हुआ है। देश के कुछ इलाके डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप से ग्रसित है, लेकिन बिहार में डेंगू महामारी का रूप ले लिया है। बिहार के 38

जिलों में से 31 जिलों में डेंगू का प्रकोप है। लेकिन पटनाइट्स डेंगू के डंक से कराह रहे हैं। पटना के तो हर मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप है।

✯ **बिगड़ गई है मानसून की लय :-** ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसून की लय बिगड़ गई है, जो पूरी दुनियां के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो रही है। एक दशक पहले तक रिमझिम बारिस हुआ करती थी, अब झमाझम बारिस होने लगी है। मसलन बिहार में औसतन प्रतिवर्ष 1027 मिलीलीटर बारिस होती थी, जो अब घट गई है। वैसे बारिस का मौसम तीन माह का होता है–असाढ़, सावन और भादो यानि 15 जून से 15 सितम्बर तक। लेकिन अब बारिस के दिनों में उल्लेखनीय कमी हो गई है। 55 से घटकर 37 दिन रह गई है। बारिस के दिनों की घटती संख्या के चलते हैवी रेन (भारी बारिस) की दर अधिक हो गई है। अब बरसात के बदलते ट्रेंड के चलते कई दिनों की बारिस एक ही दिन में हो जाती है। ऐसे दिनों की संख्या यानि हैवी रेन डे की संख्या एक साल में करीब 12–14 हो गई है, जो पहले 3–4 दिन हुआ करती थी। पहले बादल फटने की घटना कभी–कभार घटती थी। अब उतराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना आम हो गई है। बादल फटना वर्षा का चरम यानि सर्वाधिक खतरनाक रूप है। बादल फटने पर उसका सारा का सारा पानी जमीन पर एक साथ आ गिरता है। एक सीमित जगह में सैकड़ों करोड़ लीटर पानी एक साथ जमीन पर आ गिरता है, जिसके कारण प्रभावित इलाके में तेज रफ्तार वाली बाढ़ यानि सैलाव आ जाता है। फिर बादल फटने की घटना अचानक घटती है। नतीजा मजबूत से मजबूत मकान, पुल, सड़क आदि ताश के पत्ते की तरह ढ़हकर पानी में समाते चले जाते हैं, भारी से भारी वाहन जैसे–ट्रक, बस आदि लकड़ी की नाव की भांति पानी के साथ बह जाते हैं और ढ़ेर सारी जिंदगियां देखते ही देखते पानी के साथ बहकर कहां चली जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता। मसलन इस साल केरल में ऐसी मुसलाधार बारिस हुई जैसे पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। आमतौर पर भारी बारिस के चलते उत्पन्न पानी के बहाव को रोकने में वृक्ष बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं लेकिन पिछले 40 वर्षों में केरल के लगभग आधे जंगल साफ किए जा चुके हैं। नतीजा केरल में आयी बाढ़ से करीब 500 लोगों की मौत हो गई और 11 लाख लोग बेघर हो गये। केरल और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य रहे जहां बारिस और बाढ़ ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हिमाचल प्रदेश में पिछले 117 वर्षों में ऐसी बारिस कभी नहीं हुई थी। ऐसी घटनाएं पिछले 7–8 साल से उत्तराखण्ड में हर साल घटने लगी है।

✯ **समुद्र में समा रहे हैं भारत के तटीय इलाके :-** केन्द्रीय भू–विज्ञान के तहत काम करने वाले नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर) के ताजा सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 1990 से 2016 के बीच 26 वर्षों के दौरान 6632 किलोमीटर लंबे समुद्र तटीय इलाकों की 234.25 वर्ग किलोमीटर जमीन भूमि कटाव की वजह से समुद्र में समा गया है, जबकि यह सर्वेक्षण रिपोर्ट अधूरा है, क्योंकि देश के समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है, जिसमें से 6031 किलोमीटर लंबाई का ही सर्वेक्षण किया गया है। एनसीसीआर के निदेशक एम.वी. रमन्ना मूर्ति बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की 99 वर्ग किलोमीटर जमीन समुद्र में समा चुकी है। सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल का 63 फिसदी पुण्डेचेरी का 57 फिसदी, केरल का 40 फिसदी, ओडिसा का 27 फिसदी और आन्ध्र प्रदेश का 27 फिसदी जमीन समुद्र में समा चुका है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 9 राज्यों और दो केन्द्र शासित राज्यों के समुद्र तटीय इलाकों में भूमि कटाव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में समुद्र तटीय इलाकों में भूमि कटाव के चलते सुंदरवन के लोहाचारा और सुपारीभांगा नामक दो द्वीप हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी में समा चुके हैं। इसरो की ओर से सैटेलाइट के द्वारा जुटाये गये ताजा आंकड़ों से साफ है कि बीते एक दशक के दौरान 9900 हेक्टेयर जमीन समुद्र में डूब गया है। सुंदरवन के दो द्वीप बंगाल की खाड़ी में डूब गये हैं और कईयों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि अब सुंदरवन इलाके को दुनियां में डूबते द्वीपों के नाम से जाना जाने लगा है। जादवपुर विश्वविद्यालय के जाने माने पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ० सुगत हाजरा कहते हैं कि सुंदरवन इलाके में द्वीपों के डूबने के चलते वहां की 45 लाख की आबादी का पलायन तेज हो गया है। दरअसल, ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का जलस्तर 3.14 मिलीमिटर की दर से बढ़ रहा है। इससे कम से कम 12 द्वीपों का वजूद संकट में है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक ग्लोबल

बिहार के तापमान में वृद्धी

वर्ष 1951–2010 तक बिहार में मानसून के दौरान तापमान में औसत वृद्धि 0.1 डि०से० और मानसून के तापमान में औसत वृद्धि 0.2 डि०से० हुई है। बिहार सरकार के अनुसार वर्ष 2010 से 2040 तक तापमान में वृद्धि का अनुमान :-

बिहार का इलाका	–	**तापमान में वृद्धि डिग्री सेल्सियस में**
पश्चिमी बिहार	–	0.6 से 1.0
पूर्वी बिहार	–	0.2 से 0.4
उत्तरी बिहार	–	0.1 से 1.6

वार्मिंग बांग्लादेश, म्यानमार और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को डूबो देगी, जिससे भारत में ''क्लाईमेट रिफ्यूजी' यानि जलवायु परिवर्तन की वजह से बने शरणार्थियों की संख्या करीब दो करोड़ हो सकती है।

✯ **आने वाले समय में छोटी सुनामी से भी उतना ही नुकसान होगा, जितनी बड़ी सुनामी से होता है :-** पानी का रंग नीला दिखने के कारण धरती के बढ़े हुए तापमान का अधिक गर्मी लगभग 80 फिसदी गर्मी समुद्र सोख लेता है। इसलिए समुद्र का तापमान तीन हजार मीटर की गहराई तक बढ़ गया है, फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर कई गुणा तेजी से पिघल रहे हैं। इन्ही दो वजहों के चलते सुनामी यानि भीषण समुद्री तुफान पैदा होता है और समुद्र तटीय इलाके के बहुत अंदर तक भीषण तबाही मचाता है। मसलन इंडोनेशिया की ताजा सुनामी में लगभग 1350 लोग मारे गये, जबकि इसके पहले जापान में लगभग 16 हजार लोगों की जाने गयी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन के कारण सुनामी का असर उत्तरोत्तर ज्यादा घातक होता जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में छोटी सुनामी से भी उतनी ही तबाही हो सकती है, जितनी बड़ी सुनामी से होती है।

✯ **धरती की अद्‌भुत प्राकृतिक संरचना का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना :-** गंगा नदी का उद्‌गम स्थल उत्तराखण्ड के गढ़वाल जिले में समुद्र तल से 4100 मिटर की ऊँचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लैशियर है, जहां इस नदी का नाम भागिरथी है। वही से राष्ट्रीय नदी गंगा देश के पांच राज्यों से होते हुए 2525 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बेसिन दुनियां का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसका 80 फिसदी भाग भारत में पड़ता है और शेष बांग्लादेश तथा नेपाल में। गंगा नदी बेसिन का कुछ हिस्सा चीन में भी पड़ता है। गंगा नदी बेसिन भारत के 11 राज्यों के 50 करोड़ से ज्यादा लोग जलापूर्ति के लिए गंगा पर निर्भर करते हैं। यह देश की 40 फिसदी आबादी को पानी उपलब्ध कराता है। गंगा नदी बेसिन भारत में 8 लाख 61 हजार 404 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 26 फिसदी है। लेकिन 1961 में

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर 7360 फीट लंबा विशालकाय फरक्का बांध बनाकर गंगा की धारा को रोका गया है। जिससे फरक्का बांध के पास गंगा में भारी मात्रा में गाद (शिल्ट) जमा हो गया है। 2006 में भागीरथी नदी (गंगा नदी) पर उत्तराखण्ड के गढ़वाल जिले में विशालकाय टिहड़ी बांध बनाकर गंगा की धारा को रोका गया है। 52 वर्ग किलोमीटर में फैले टिहड़ी बांध की लम्बाई 1886 फीट और ऊँचाई 855 फीट है। इस बांध के निर्माण हेतु पहाड़ को इतनी बेहरमी से क्षतिग्रस्त किया गया है कि

इसके आसपास क्षेत्रों का संरक्षण किसी भी तरह से संभव नहीं है। फिर इस बांध के निर्माण के दौरान पहाड़ी जंगल के एक बड़े हिस्से का नामोनिशान मिट गया है। इसके चलते पर्यावरण से कार्बन के अवशोषण में भारी कमी आयी है। फिर रोजाना अरबो लिटर शहर का गंदा पानी गिरने से गंगा नदी दुनियां की छट्ठी सबसे बड़ी प्रदुषित नदी बन गई है। इस तरह जगह-जगह पर बांध बनाकर गंगा की धारा को रोकने से गंगा अविरल कैसे बनी रहेगी? फिर गंगा निरंतर इतना अधिक प्रदुषित हो रही है कि इसके वजूद को ही खतरा पैदा हो गया है।

अरावली पर्वतमाला कोई 65 करोड़ साल पुराना माना जाता है। गुजरात के खेड ब्रह्मा से शुरू होकर कोई 692 किलोमीटर तक फैली इस पर्वतमाला की समाप्ति देश के सबसे ताकतवर स्थान रायसीना (दिल्ली) पर होती है, जहां राष्ट्रपति भवन है। यह पर्वतमाला राजस्थान के 19 जिलों से गुजरती है, जहां 45 हजार से ज्यादा वैध-अवैध खद्दाने हैं। इन खद्दानों में लाल बलुआ पत्थर की खुदाई होती है। नतीजा, ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते चार दशकों में न सिर्फ नदारद हुआ है बल्कि कई जगहों पर ऊँचे शिखर की जगह 150 फीट तक गहरी खाई बन गई है। अवैध खनन का कारनामा है कि राजस्थान स्थित इस पर्वतमाला की 128 पहाड़ियों में से 31 का नामोनिसान तक मिट गया है। 20वीं सदी

के अंत तक इस पर्वतमाला के 80 फिसदी हिस्से में हरियाली थी, जो भू-जल का स्तर ठीक बनाये रखती थी, जमीन की नमी बरकरार रखती थी। कई नदियों तथा जल-प्रपातों को आश्रा देती थी, रेगिस्तान के विस्तार को रोकती थी और मिट्टी के क्षरण को भी रोकती थी, अब ऐसा करने में सक्षम नहीं रह गई है। ऐसा इसलिए कि आज वहां 80 फिसदी की बजाये बामुश्किल 7 प्रतिशत ही हरियाली रह गई है। नतीजा पहाड़ों की कई नदियां जल-प्रपात और झरने लुप्त हो गये हैं तथा कई लुप्त होने के कगार पर हैं। वाली साहिबा, कृष्णावती, दोहन आदि नदियां भी लुप्त हो रही है और जमीन की नमी खत्म होने से रेगिस्तान का विस्तार होने लगा है। ऐसा सारी दुनियां में हो रहा है। बेहद धीरे-धीरे और तुरंत न दिखने वाली गति से विस्तार कर रहे रेगिस्तान का असर सबसे ज्यादा एशिया में है। पहाड़ की अंधाधूंध खुदाई कर और वहां की हरियाली उजाड़कर बड़े-बड़े भवन, बड़ी-बड़ी आवासीय कॉलोनिया, लंबी-चौड़ी सड़के आदि बनाने का क्या लाभ? ऐसे विकास का क्या लाभ जो विनाश के तरफ ले जा रहा है। हम विनाश के नाम पर हरियाली से भरपूर प्राकृतिक संरचना को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त का अपना ही कब्र खोद रहे हैं। पर्यावरण को बचाने हेतु सुप्रिम कोर्ट समय-समय पर सख्त निर्देश जारी करता रहा है, फिर भी राज्य तथा केन्द्र सरकारें सुप्रिम कोर्ट के सख्त से सख्त निर्देश को भी नजरअंदाज करने से नहीं चुक रही है। यदि सरकार ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति इतना अधिक उदासीन बनी रहेगी तो आम जनता कैसे सजग होगी। आम जनता ही जब सजग नहीं रहेगी तो सुनामी, बादल फटने, सूखा, बाढ़, रेगिस्तान का विस्तार, भू-क्षरण आदि ढ़ेर सारी मुसिबतों में घिरी इस धरती को जीवनविहिन होने से रोक पान कैसे संभव हो पायेगा। हम आदमी स्वार्थ में इतने अंधे हो गये है कि हमारी दूरदर्शिता को लकवा मार गया है, इसलिए हम अपना ही कब्र खोदने में जी जान से जुटे हुए हैं। पता नहीं कब हम चेतेंगे और कब हमारी सोच में क्रांति आयेगी, जिससे की हमारा जीवन पुनः पटरी पर लौट सके।

✯ ग्लोबल वार्मिंग का समाधान :-

☞ **हर हालत में बढ़ती आबादी पर लगाम लगानी होगी :-** पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि हर तरह की समस्याओं की जड़ में बेतहाशा बढ़ती आबादी है। इसलिए सिर्फ आबादी नियंत्रित करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इतना भर पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज जो देश और दुनियां कि आबादी इतनी बढ़ी हुई है कि उसमें हर हालत में कमी लानी ही होगी। इसके सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों को इस मामले को लेकर एक मत हो जाना चाहिए, सियासत करने से बाज आना चाहिए, सिर्फ वोट की सियासत करना यह हर हालत में सत्ता पर काबिज होनी की सियासत करने को तिलांजलि देनी होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि शादी-विवाह पर रोक लगा दी जाये, मियां-बीबी अंतरंग संबंध स्थापित न कर सके। आजकल तो कई वैज्ञानिक उपाय उपलब्ध है, जो मियां-बिबी के अंतरंग संबंध में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार कानून बनाकर जनता को इस बात के लिए मजबूर कर देना चाहिए कि 'हम दो और हमारे एक' का सख्ती से पालन करे।

☞ **वृक्षारोपण :-** ग्लोबल वार्मिंग को न सिर्फ नियंत्रित करने बल्कि कम करने का सर्वाधिक वैज्ञानिक, सर्वाधिक कारगर और अतुलनीय और अद्भुत साधन है। जो हमेशा से रहा है, जो आज भी है और भविष्य में भी रहेगा तथा इसका कोई भी विकल्प खोज पाना असंभव है। चाहे भविष्य में विज्ञान कितना भी विकसित क्यों न हो जाये। वृक्ष वातावरण को शीतलता प्रदान करता है। आज से 25-30 वर्ष पहले जब धरती पर पर्याप्त जंगल हुआ करते थे, तब दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में भी वृक्षों की छाव में बैठना उनके द्वारा प्रदत्त शीतलता की बदौलत सुकून भरा लगता था। ऐसा इसलिए की तपीश इतनी अधिक नहीं होती थी। आज तो गर्मी के मौसम में लगता है कि शरीर का हर हिस्सा गर्मी से जल रहा है। परिक्षणों से पता चला है कि एक वृक्ष इतनी शीतलता प्रदान करता है, जितना की एक-एक ए.सी. दस कमरों में कई-कई घंटों तक चलाने से करता है। यही कारण है कि सघन वन से घिरा क्षेत्र का तापमान उसके पहाड़ी वातावरण के ताप से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम पाया गया है। इसलिए यदि भवनों के आस-पास चारो ओर पेड़ों को ठीक से लगा दिया जाये तो एयर कंडिश्नींग की जरूरतों में 30 फिसदी तक की कमी लायी जा सकती है। दरअसल, वृक्षों के अनगिनत पत्तों से लगातार निकलते रहने वाली जल की अंसख्य बुंदकियों आसपास के वातावरण को शीतल बनाये रखने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाती हैं। बात

यह है कि एक ग्राम जल की बुंदकियों को जलवाष्प की परिवर्तित करने में 536 कैलोरी ताप की जरूर पड़ती है, जिसके चलते वृक्षों के आसपास का वातावरण शीतल बना रहता है। मसलन झारखण्ड के गुमला जिला को ही ले लिजिए। आज से 20 वर्ष पहले वहां सघन वन क्षेत्रों की अधिकता थी तो इतना शीतल हुआ करता था कि गुमला को मिनी कश्मीर कहा जाता था, फिर वृक्षों द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक शीतलता का मुकाबला ए.सी. द्वारा प्रदत्त कृत्रिम शीतलता कभी भी नहीं कर सकता है। यही कारण है कि गर्मियों में हरियाली से भरपूर पार्कों तथा बगीचों में खुले आकाश के नीचे वृक्षों की छांव में जो खुशहाली मिलती है, वह ए.सी. द्वारा प्रदत्त बंद कमरों में बैठने से कभी भी नसीब नहीं हो सकती है। इससे स्पष्ट है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में वृक्ष अहम भूमिका निभाते हैं।

पेड़-पौधे वायुमंडल से हर दिन कॉर्बनडाई ऑक्साइड लेते हैं और बदलते में ऑक्सीजन देते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि एक हेक्टेयर वन क्षेत्र द्वारा एक वर्ष में 3. 7 टन कॉर्बनडाई ऑक्साईड गैसे अवशोषित की जाती है और बदले में 2.0 टन ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है। एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वह लगभग 625 वर्ग फीट में उगी वनस्पतियों से प्राप्त होती है। एक एकड़ में लगे पेड़ सलाना इतनी कॉर्बनडाई ऑक्साईड गैस अवशोषित करता है, जितना की एक मोटर कार 41 हजार किलोमीटर चलने पर छोड़ती है। इस तरह हम पाते हैं कि पेड़-पौधे समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु दोहरी भूमिका निभाते हैं-एक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर और दूसरा कॉर्बनडाई ऑक्साईड की मात्रा घटाकर। इसलिए पेड़-पौधे कम होंगे तो प्राकृतिक संतुलन विगड़ जायेगा फिर भी विकास के नाम पर हम इंसान वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य में अंधा इंसान यह भी भूल गया है कि उसके द्वारा छोड़ी गई कॉर्बनडाई ऑक्साईड को कौन ग्रहन करेगा? कुछ लोग तो इतने बेशर्म हो गये हैं कि वृक्षों की पूजा करने के बजाये उनकी आड़ लेकर वृक्षों की जड़ों पर पेशाब कर देते हैं। ऐसा बार-बार करने से वृक्ष सुखने लगते हैं। अंतत: उनका वजूद ही मिट जाता है।

नये इलाकों में वृक्षारोपण के अलावा उन तमाम पुराने इलाकों में जंगल बसाने का प्रयास संजिदगी से अविलंब शुरू कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से वृक्षारोपण हेतु नये इलाकों की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी और काम भी बन जायेगा।

☞ **अधिक से अधिक घरों में गैस पर खाना पकाना होगा :-** कायले, गोईठा और लकड़ी पर खाना पकाने से जितने कार्बन का उत्सर्जन होता है, गैस पर खाना पकाने से 90 फिसदी से भी कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक करीब 6 करोड़ गरीब परिवारों को सिलेंडर और रेगुलेटर के साथ गैस का चूल्हा मुफ्त में मुहैया कराया जा चुका है और इसे शीघ्र ही दस करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचा दिया जायेगा। मोदी सरकार की यह योजना सचमुच काबिले तारीफ है। यदि सरकार के सामने पेट्रोलियम की आपूर्ति की समस्या है तो गोबर गैस और वायोगैस के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। बड़े पैमाने पर गोबर गैस प्लांट लगाना होगा। पशु धन को लेकर हमारा देश दुनियां का सबसे धनी देश है। हमारे देश में केवल गायों की संख्या 19 करोड़ के पार है। इसमें भैंस, बैल, घोड़ा, बकरी, हांथी आदि जानवरों को शामिल नहीं किया गया है। गोबर गैस तैयार करने के लिए हमारे पास कच्चे माल यानि गोबर की कमी नहीं है। इसलिए सरकार को देश के हर गांव में सरकारी खर्चे पर गोबर गैस प्लांट लगवा देना चाहिए। जिससे की देश के हर परिवार में, चाहे गरीब हो या अमीर गैस पर खाना पका सके। ऐसा करने से कार्बन के उत्सर्जन में भारी कमी आ जायेगी और खेतों में डालने के लिए अति उत्तम जैविक खाद की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी। घर बाहर हर जगह स्वच्छता बनी रहेगी, जिससे मच्छर-मक्खी के प्रकोप से निजात मिल जायेगा। दरअसल, जब

ग्लोवल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन

वर्ल्ड रिर्सोस इंस्टीच्यूट की रिपोर्ट के अनुसार समाज के किस क्षेत्र से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है :-

क्षेत्र के नाम		**कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा**
ताप विद्युत गृह	-	25%
वनों का कटाव	-	18%
ट्रांसपोर्ट	-	14%
कृषि	-	13%
उद्योग	-	10%
कूड़ा-कचड़ा	-	04%
अन्य	-	16%

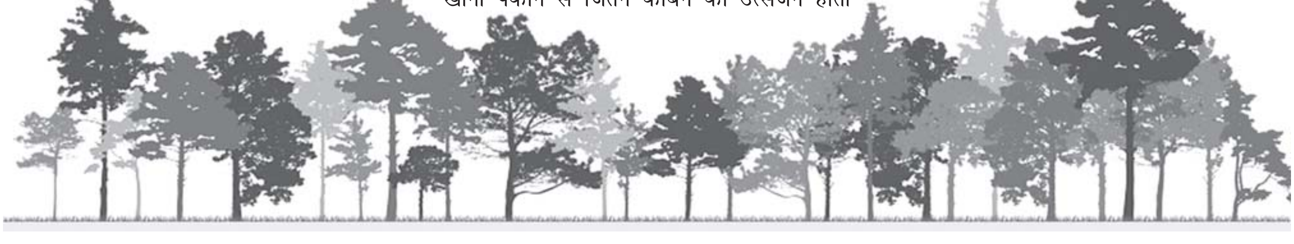

गोबर गैस तैयार किया जाता है तो भारी मात्रा में जैविक खाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। गोबर गैस से सिर्फ खाना ही नहीं पकेगा बल्कि घर द्वार भी रौशन हो जायेगा। नतीजा

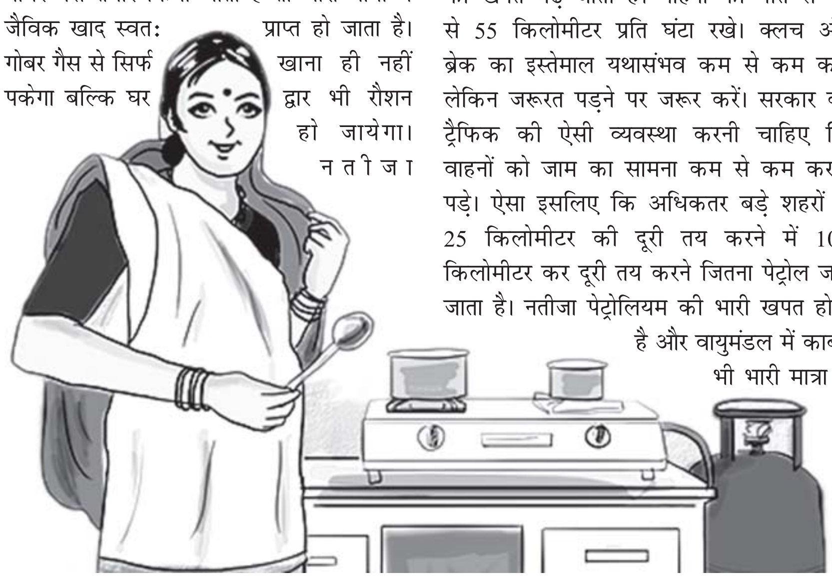

बिजली की काफी बचत होगी। फिर थर्मल पॉवर स्टेशनों में कोयले की खपत में भी भारी कमी आ जायेगी, नतीजा कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी होगी।

☞ **वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या पर लगाम लगाना होगा तथा इनके गलत इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी :-** बहुत छोटी-छोटी दूरी पैदल चलकर पूरा करे, यदि बहुत जल्दबाजी में ना हो तो। बहुत छोटी से कुछ अधिक बड़ी दूरी साईकिल चलाकर पूरा करे। ऐसा करने पर पेट्रोलियम की काफी बचत होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वचालित वाहनों को जरूरत के मुताबिक समय-समय पर सर्विसिंग कराते रहे। वाहनों का समय-समय पर ट्यूनिंग करायें। वाहनों का कार्बोरेटर साफ रखें। टायर में हवा का प्रेशर पर्याप्त रखे, कम न रखें। क्योंकि टायर में हवा का प्रेशर कम रहने से पेट्रोलियम की खपत बढ़ जाती है। वाहनों की गति से 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रखे। क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल यथासंभव कम से कम करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर जरूर करें। सरकार को ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वाहनों को जाम का सामना कम से कम करना पड़े। ऐसा इसलिए कि अधिकतर बड़े शहरों में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 किलोमीटर कर दूरी तय करने जितना पेट्रोल जल जाता है। नतीजा पेट्रोलियम की भारी खपत होती है और वायुमंडल में कार्बन भी भारी मात्रा में उत्सर्जित होता है। सरकार को कानून बना देना चाहिए कि कार सिर्फ वही खरीद सकते हैं, जिनके पास कार पार्किंग की जरूरत हो। सरकार को दस साल से अधिक पुरानी स्वचालित वाहनों के चलाने पर पुर्नतः रोक लगा देनी चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती जल रही हो और वाहनों को 2 मिनट या उससे अधिक समय के लिए खड़ी करनी पड़े तो वाहनों का इंजन बंद कर दे। उपरोक्त उपायों पर अमल करने से पेट्रोलियम की खपत में भारी कमी आ जायेगी, कार्बन काक उत्सर्जन भी बहुत कम होगा तथा विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

☞ **पराली बिल्कुल ही नहीं जलाये :-** हमारे देश में हर साल दो बार में धान की फसल काटने के बाद और गेंहू की फसल काटने के बाद सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर हमारे किसान भाई लगभग 60 करोड़ टन पराली जला डालते हैं। सरकार दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भर देकर रह जाती है। इसके चलते वायुमंडल में बेतहाशा कार्बन का उत्सर्जन होता है। सरकार और सरकारी मुलाजिम पराली जलाने की समस्या के समाधान हेतु रत्तीभर भी प्रयास नहीं करते हैं जबकि इस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। सरकार इतना भर कर दे कि धान और गेंहू की फसलों की कटाई के बाद देश भर में खेतों की जुताई अपने खर्च पर 15-15 दिनों के लिए दो बार में ट्रैक्टर चलावाकर करवा दे। ऐसे में खेतों में पराली बचेगी ही नहीं तो किसानों को पराली जलाने के लिए मिलेगा ही नहीं। किसानों को भी लगेगा कि सरकार उनके भले के लिए कुछ कर रही है। मैं विगत् दो वर्षो से इस समस्या को लेकर पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार तथा सरकारी मुलाजिमों का दरवाजा खटखटा रहा हूं। फिर भी सरकार और सरकारी मुलाजिम कुंभकर्णी निंद में सोये हुए हैं। मोदी सरकार अनाजों के समर्थन मूल्य का भारी इजाफा करने के साथ अनेक तरह से किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी हुई है। हमारे किसान भाई भी अच्छी तरह से समझते हैं कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वराशक्ति घट जाती है। फिर भी किसान भाई जान-बूझकर पराली जला रहे हैं। हास्यास्पद है किसानों का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव। उनका यह बर्ताव शर्मसार करने वाला है, इसलिए उन्हें पराली जलाने से बाज आना चाहिए।

☞ **कूड़ा जलाने पर रोक :-** यदि नगर पालिका और नगर निगम के मुलाजिम अपनी ड्यूटी निभाये, जिसके लिए वेतन लेते हैं तथा आमजनता में जागृति लाया जाये तो कूड़ा से जैविक खाद और बिजली पैदा की जा सकती है। कूड़ा-कचड़ा को जलाने की जरूरत ही नहीं रह जायेगी। नतीजा, हर रोज भारी मात्रा में कार्बन सहित अन्य

विषैली गैसों के उत्सर्जन पर रोक लग जायेगी और लोग धूंआ के चलते बिमार होने से बच जायेंगे।

☞ **पूरे देश में तालाबों का जाल बिछाना होगा :-** लगातार गिरते भूमिगत जलस्तर के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में पीने का पानी पीने के लिए त्राही-त्राही मची हुई है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार के अधिकतर जिलों में पानी की भारी किल्लत हो गई है। कोई-कोई जिला जैसे जमुई जिला में भूमिगत जलस्तर एक हजार फीट से भी अधिक नीचे चला गया है। पूरे बिहार में हर जगह भूमिगत जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जो लगातार और अधिक गिरते ही जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार में भी नदियां न केवल लुप्त होती जा रही है, बल्कि सुखती भी जा रही है। तालाबों का टोटा पड़ गया है। आजादी के समय बिहार में लगभग ढ़ाई लाख तालाब थे, जो 2015 होते-होते 68 वर्षों में महज 98 हजार 401 रह गये और अब तो और भी कम रह गये। आजादी के बाद से अब तक बिहार में सघन वन क्षेत्रों में काफी कमी हुई है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के चलते इस साल बिहार में भयंकर सूखा पड़ गया है, जिसके चलते हमारे किसान भाई बर्बादी के कगार पर पहुंच गये हैं। सूखा के चलते खेतों की नमी गायब हो गई है। ऐसे में हमारे किसान भाई गेंहू की बुआई कैसे करेंगे? अर्थात् सूखे का विपरित प्रभाव आने वाली फसलों पर भी पड़ना तय है। बिहार में खेतों की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां की खेती किसानी पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। ग्लोवल वार्मिंग के चलते अगने साल भी सूखा पड़ने की संभावना बहुत अधिक है। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? पीने के लिए, रोजमर्रा के कार्यों के लिए, सिंचाई आदि के लिए लोग पानी कहां से लायेंगे? ऐसे में एक ही समाधान है, युद्धस्तर पर भारी संख्या में तालाबों का निर्माण कराया जाना। दरअसल प्रायोगिक रूप से प्रमाणित हकीकत है कि आजतक पूरी दुनियां में ऐसा कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का इजाद नहीं किया जा सका है जो भारत की तालाब संस्कृति के आसपास भी पहुंच सके, बराबरी करना तो दूर की बात है। तालाब वर्षाजल का जितना अधिक मात्रा में, जितनी तेजी से और जितना उपयुक्त तरीके से जितनी सफलतापूर्वक सहेज लेता है, उतना आज के सर्वाधिक विकसित किसी भी दूसरी तकनिक द्वारा संभव नहीं है। इतना ही नहीं, भूमिगत जल को रिर्चाज करने का यह एक अद्भुत और अतुलनीय साधन है। ऐसा इसलिए कि तालाब भू-जल को बगैर एक भी सेकेंड के ब्रेक के सालों भर, चौबिसों घंटे हर मौसम में दिन रात रिचार्ज करता रहता है। अर्थात् तालाब भू-जल स्तर को नीचे गिरने से ब्रेक लगाने का सर्वाधिक असरदार साधन है। नि:संदेह जल संग्रहण व जल संरक्षण का सर्वोत्तम साधन है तालाब।

सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की हिस्सेदारी

देश	प्रतिर्ष कार्बन उत्सर्जन की मात्रा	कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी
चीन	37 बिलियन टन	28.21%
अमेरिका	758 मिलियन टन	15.99%
भारत	-	6.2 %
रूस	-	4.53%
जापान	-	3.67%
जर्मनी	-	2.23%
दक्षिण कोरिया	-	1.75%
ईरान	-	1.72%

इसलिए नीतीश सरकार को चाहिए कि एक साल के अंदर पूरे बिहार में कम से कम दस हजार तालाबों का निर्माण युद्धस्तर पर करवायें। यदि एक तालाब की लम्बाई-100 फीट, चौड़ाई-100 फीट और गहराई 10 फीट हो तो ऐसे एक तालाब के निर्माण पर लगभग ढ़ाई लाख रूपये खर्च आयेंगे। इस हिसाब से दस हजार तालाबों के निर्माण पर कुल 250 करोड़ रूपये खर्च आयेंगे। नीतीश सरकार द्वारा पूरे बिहार में पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, पुलिस भवन, अनेक थानों के भवन, बिहार म्यूजियम, बौद्ध ध्यान केन्द्र, विश्वविद्यालयों के भवन आदि निर्माण के ढ़ेर सारे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया है, सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछाया है और पूरे बिहार में घर-घर बिजली पहुंचाने का कार्य किया है, जिससे बिहार की जनता काफी राहत महसूस कर रही है। लेकिन, बिहारवासियों को पानी की कमी कैसे दूर हो, इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए बिहार की जनता को पानी की भयंकर किल्लत से बचाने के लिए एक साल के अंदर कम से कम दस हजार तालाबों का निर्माण अवश्य करावें, वरना पानी की भयंकर कमी को लेकर ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी की कोई अक्ल काम नहीं करेगा। नीतीश बाबू दूरदर्शिता का परिचय दिजिए और ऐसा करके पूरी दुनियां के सामने मिशाल पेश कर दीजिए। आप इंजीनीयर मुख्यमंत्री हैं, आप में ऐसी क्षमता हैं, यश के भागी बने। ऐसा करके देश में ही नहीं पूरी दुनियां में अपने नाम का डंका बजाये।

साथ ही बिहार सरकार को सघन वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए युद्धस्तर पर हर संभव कारगर प्रयास बगैर किसी विलब के शुरू कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि सघन वन वर्षाजल के संग्रहण व संरक्षण का बहुत ही कारगर साधन है, फिर सघन वन नदियों, जलप्रपातों, झीलों, तालाबों आदि कई प्रकार के जलस्त्रोतों को भरपूर जल की आपूर्ति करते हैं।

☞ **झरिया कोलियरी में लगी आग को बुझाना :-** यह सच है कि झरिया कोलियरी में लगी आग भीषण और विक्राल है, इसलिए इसे बुझाना बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा किन्तु आग अवश्य बुझ जायेगी। मेरे पास इसका रामवाण समाधान है, जो व्यवहारिक है और जिसका असर बहुत कम समय में दिखने लगेगा। यदि झारखण्ड सरकार

और भारत सरकार एक सेमिनार का आयोजन कर मुझे विभाग तथा अन्य वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत करने को आमंत्रित करे तो मैं सहज तैयार हूं।

9. उद्योगों की चिमनियों में उनकी ऊँचाई के इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसीपिटेटर लगाने होंगे। जिससे कि कालिख के कण को वायुमंडल में उत्सर्जन पर रोक लग जाये, फिर उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली कार्बनडाई ऑक्साइड और सल्फरडाई ऑक्साइड गैसों को स्क्रबर से गुजारने के बाद ही वायुमंडल में उत्सर्जित किया जाये। ऐसा करने पर वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन पर 90 फिसदी की कमी आ जायेगी।

अधिकतर राजनेता और सरकारी मुलाजिम पर्यावरणीय समस्या को लेकर इतने निकम्मा क्यों हैं। क्या अपने और अपने परिवार के लिए जायज-नाजायज तरीके से यानि जैसे भी हो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति अर्जित व संग्रहित करने के सिवाय और करते क्या हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार तथा रिश्तेदारों को हर तरह का सुख-सुविधा हासिल हो, बाकि आम जनता जाये भाड़ में। गलती ये करे और भुगते केवल आमजनता। लेकिन अधिकतर राजनेता, सरकारी मुलाजिम और इनके सह पर जीने वाले चमचे और भ्रष्ट लोगों का सोचना गलत है, क्योंकि ऐसा संभव दिखता भी है तो बहुत ही थोड़े समय के लिए या यूं कहें कि क्षणभंगुर है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए कि ग्लोवल वार्मिंग के चलते अधिकतर राजनेता चाहे सत्ताधारी पार्टी के हो या विपक्षी पार्टी, इनके चमचे, भ्रष्ट और गद्दार लोग अपने-अपने आलिशान बंगले, महंगी कारे तथा ऐसो-आराम की तमाम वस्तुओं का करेंगे क्या, जब कोई भोगने वाला ही नहीं बचेगा? जब हवा व्यापक रूप से जहरीली हो जायेगी, तो उनके बच्चे सांस लेने के लिए कहां जायेंगे?

वैसे तो पानी की भारी कमी हो जायेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी बचेगा, वह भी प्रदूषित होगा तो उनके बच्चे पीने के लिए शुद्ध जल कहां से लायेंगे। सूखा और बाढ़ के चलते खाद्यान्नों का उत्पादन आर्श्यजनक रूप से कम हो जायेगा तो इनके बच्चे खायेंगे क्या? जब धरती इतनी गर्म हो जायेगी की यहां जिना मुश्किल हो जायेगा तो इनके बच्चे रहने के लिए कहां जायेंगे? समस्या के बारे में कमोवेश सबको पता है, क्योंकि स्वस्थ कैसे रहे, इस समस्या से पूरी दुनियां त्रस्त है। फिर समस्या के बारे में पत्र-पत्रिकाओं में बार-बार और लगातार कुछ न कुछ प्रकाशित होता ही रहता है। प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बार-बार और लगातार सचेत कर रहा है। लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कारगर और व्यवहारिक रूप से अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सके, इसको लेकर एकदम से चुप्पी साध ले रहे हैं। नतीजा, ढ़ाक के तीन पात। यह सब मीडिया के आधे-अधूरे प्रयास का नतीजा है। असल में मीडिया समस्या के विकरालता को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के बजाये यह बताना चाहिए कि समस्या के समाधान की ओर वैज्ञानिक संकल्पना के साथ विश्वास से भरकर व्यवहारिक रूप से सफलतापूर्वक कैसे अग्रसर होते चले जायें? इस समस्या को लेकर आमजनता के बीच ऐसी जागरूकता पैदा कर दे कि वे स्वत: समस्या के समधान हेतु पूरे मन से अंजाम तक पहुंचाने में अविलंब जुट जाये। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। बेरोजगारी के अभिशाप को मिटायें। देश के सभी प्रदेश की राजधानी और देश के सभी प्रदेश के शहरों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें।

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308/9308727077

केरेडारी में बाईपास रोड का निर्माण बहुत जल्द

● ब्रजेश कुमार मिश्रा/धीरज कुमार

बीते माह 28 सितम्बर को झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम चौपाल को प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित करते हुए कहा कि शासन और सरकार के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। पिछले 4 वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय बनाकर पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का कार्य किया है। सरकार सीधे जनता से संवाद कर रही है। शासन से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो रही है। जनता दरबार में लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब और किसान के सर्वांगीण विकास के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हजारीबाग जिले के केरेडारी में बाईपास रोड का निर्माण के जनता की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए केरेडारी में दिसंबर 2018 से बाईपास रोड के निर्माण किए जाने की घोषणा की। उन्होंने जुलाई 2019 तक बाईपास रोड का निर्माण पूर्ण हो सके इस पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया।

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आगे कहा कि हम सभी को मिलकर पूरे राज्य में स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हम सबों को साफ सफाई के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी लोगों के अथक प्रयास से ही हम स्वच्छ एवं स्वस्थ झारखंड का निर्माण कर सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में पूरे राज्य की जल सहिया, महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका का महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा राज्य 4 वर्ष पूर्व मात्र 16 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त था, आज 96 प्रतिशत ODF हो चुका है। यह उछाल राज्य की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वच्छता अपनाने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। हजारीबाग जिला भी स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत अच्छा कार्य किया है। शौचालय के निर्माण कार्य में राज्य की रानी मिस्त्रीओं ने पूरे देश में राज्य का मान बढ़ाया है। स्वच्छ झारखण्ड के सपने को पूरा करने के लिए सरकार और समाज के साथ चलना होगा। स्वच्छता ही सेवा के मंत्र को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के समस्या को समझते हुए पूरे देश में उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बनाई. झारखंड में भी उज्जवला योजना को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर एलपीजी गैस के साथ–साथ चूल्हा एवं पहली रिफिलिंग निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय स्थापित कर करोड़ों वंचित, शोषित, गरीब के जिंदगी में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का संचालन कर रही है। योजनाओं का संचालन धरातल पर उतर सके इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जनता दरबार के माध्यम से सीधे जनता से संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक समृद्ध झारखंड का निर्माण करना है। राज्य के किसान खुशहाल हो इस हेतु सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई है। कृषि के साथ–साथ पशुधन एवं बागवानी के क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। बताते चले कि गरीबी इलाज में बाधा नहीं बनेगी, गरीब भी सम्मान के साथ अपना इलाज करा पाएँगे। देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत झारखंड से हुई है। इस योजना से देश की लगभग पचास करोड़ की आबादी को लाभ होगा। अब लोगों को इलाज में एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सरकार लोगों का मुफ्त में इलाज करवाएगी। झारखंड सरकार द्वारा भी इस योजना को प्रतिबद्धता के साथ राज्य के सभी सरकारी अस्पताल एवं सूचीबद्ध गैर सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि हजारीबाग जिले में विस्थापितों के प्रति सरकार का पूरा फोकस है। विस्थापितों को उचित मुआवजा एवं रहने के लिए आवास उपलब्ध हो इस हेतु सरकार एनटीपीसी, सीसीएल एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामले का निपटारा जल्द से जल्द करें। ग्रामीणों के साथ बैठक कर जमीन अधिग्रहण से संबंधित राशि का भुगतान त्वरित गति से हो। केरेडारी क्षेत्र में सड़क पानी, बिजली, शिक्षा इत्यादि सर्वांगीण विकास के लिए एनटीपीसी, सीसीएल, पथ निर्माण विभाग एवं उपायुक्त हजारीबाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

सनद रहे कि इस अवसर महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं जल सहिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभवों को साझा किया एवं अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी श्रीमती संगम देवी को मुख्यमंत्री ने समाज के हित में कार्य करने हेतु 50000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा, राजस्व सचिव श्री के के सोन, सी सी एल सीएमडी श्री गोपाल सिंह, उपायुक्त हजारीबाग, पूर्व विधायक श्री लोकनाथ महतो, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, जल सहिया, आंगनवाड़ी कर्मी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ●

आधार
कहीं आधार तो कहीं निराधार!

● ऋतुपर्ण दवे

अब 'आधार' कानूनों में उलझनों की लड़ाई जीतकर संवैधानिक हो गया है। यकीनन निगरानी और निजता को लेकर खूब सुर्खियों में था, आगे भी रहेगा। सच यही है कि श्आधारश प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक तकनीक से देश की ज्यादातर आबादी इतने बड़े फैसले के बाद भी बिलकुल बेखबर है। इसी 26 सितंबर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आए ऐतिहासिक फैसले ने इसकी संवैधानिकता पर मुहर तो जरूर लगा दी लेकिन हकीकत यह है कि अब आधार कार्ड कई मायनों में एक पहचान पत्र बनकर रह गया है। 5 जजों चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने सुनवाई की। इस पूरे मामले में कुल 38 सुनवाइयां हुईं, जो इसी साल 17 जनवरी से शुरू हुई थीं। इसमें जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ की टिप्पणी कि आधार ने इंसान की बहुलतावादी पहचान को नकार दिया और उसे केवल 12 अंकों में सीमित कर दिया, बेहद तल्ख थी। देश की सुप्रीम अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 'आधार' कहां जरूरी है और कहां नहीं। जहां स्कूलों में दाखिले के लिए आधार की अनिवार्यता जरूरी नहीं है, वहीं कोई भी मोबाइल कंपनी आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती है। जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि आधार कार्ड की डुप्लीकेसी संभव नहीं है और इससे गरीबों को ताकत मिली है। वहीं फैसले में कहा गया, शिक्षा हमें अंगूठे से दस्तखत पर लाती है और तकनीक हमें वापस अंगूठे के निशान पर ले जा रही है। इस फैसले से निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां अपने–अपने मायने और नफा–नुकसान निकालेंगी लेकिन आधार को लेकर उलझनें और भ्रम जरूर छंटेगा। अब इस पर सियासी दंगल थमेगा या नया मोड़ लेगा, यह आगे दिखेगा। आधार की वैधता को 2012 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस केएस पुट्टास्वामी थे। 2010 में मनमोहन सिंह की यूपीए–1 सरकार में इसे जब लॉन्च किया गया, तो उन्होंने ही इसे निजता का हनन बताकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

वे अब 92 साल के हैं जिन्होंने निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में कई और जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुईं और सभी को एकसाथ जोड़कर सुनवाई चली। आधार को लेकर कई रोचक आरोप–प्रत्यारोप भी चले। बात निजता के हनन से इसके डेटा लीक और चुनावों में उपयोग तक पहुंची। अमेरिका के चुनावों में फेसबुक और कैंब्रिज एनालिटिका विवाद जैसी घटनाओं की संभावनाएं आधार में तलाशे जाने लगीं। संभवतः फैसले के बाद आधार की संवैधानिकता पर सवाल भी नहीं उठेंगे और जहां मोबाइल सिम लेने, स्कूल में बच्चों के एडमिशन, मोबाइल वॉलेट में केवाईसी, बैंक में खाता खोलने, सीबीएसई, यूजीसी और नीट जैसी परीक्षाओं, म्युचुअल फंड और शेयर मार्केट में केवाईसी के लिए जरूरी नहीं होगा, वहीं 14 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार नहीं होने पर उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन पैन कार्ड बनवाने में आधार कार्ड जरूरी होगा, क्योंकि इसमें लिंक कराने से वित्तीय स्थितियों के लाभ के लिए यह उपयोगी होगा। आयकर रिटर्न्स दाखिल करने के लिए भी आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है। सरकारी लाभकारी योजनाओं में आधार का लिंक होना जरूरी है और सबसिडी आधारित योजनाओं में भी इसे जरूरी बनाया गया है। श्आधारश एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यह प्राइवेट कंपनियों के साथ डेटा साझा करने की इजाजत देता था। जहां 5 जजों की बेंच ने माना कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है, कोर्ट के फैसले का मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां, ई–कॉमर्स कंपनियां, प्राइवेट बैंक और दूसरी ऐसी कंपनियां सर्विसेज के लिए ग्राहकों से बायोमैट्रिक और दूसरे डेटा नहीं मांग सकेंगी। हालांकि केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा। आधार सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र ने कहा था कि डेटा सुरक्षित है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। केंद्र ने यह भी तर्क रखा कि आधार समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें बिचौलियों के बिना लाभ मिलते हैं और आधार ने सरकार के राजकोष में 55,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। लेकिन इसमें कितने ऐसे लोग होंगे, जो आधार के बिना योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए होंगे या फिर आधार सत्यापन मशीनें उनके हाथ के निशानों को नहीं पढ़ पा रही होंगी? वहीं अब भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और आधार को चुनौती देने वालों का यह भी आरोप है कि आधार के बिना राजस्थान, झारखंड और अन्य जगहों पर कई लोगों की योजनाओं का लाभ न ले पाने से मृत्यु हुई है, इसके डेटा कहां हैं? आधार को लेकर जाने–माने बुद्धिजीवी और बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्णगांधी का हालिया विश्लेषण चर्चाओं में रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि सूचना का अधिकार कानून ने जनता को सरकार के हर कदम पर निगरानी रखने का अधिकार और जरिया दे दिया है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आधार कानून के जरिए सरकार हर नागरिक पर निगरानी की व्यवस्था बना दे। अब सब कुछ साफ है लेकिन ''आधार कहीं आधार तो कहीं निराधार जरूर हो गया''। ●

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। बेरोजगारी के अभिशाप को मिटायें। देश के सभी प्रदेश की राजधानी और देश के सभी प्रदेश के शहरों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें।

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308/9308727077

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485

E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

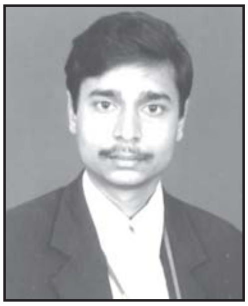

✯ पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (Order of maintenance of children Parents)

☞ पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश।

☞ पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश का उपबन्ध धारा 125 में है।

☞ धारा 125 की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं सिविल प्रकृति की है।

☞ मो. अहमद खाँ बनाम शाहबानो बेगम के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान सभी धर्मावलम्बियों के प्रति एक समान लागू होंगे।

☞ स्त्री, पति द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद भी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है।

☞ पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह शून्य होता है अत: दूसरी पत्नी भरण-पोषण का अधिकार नहीं रखती,परन्तु उसके द्वारा उत्पन्न बच्चे भरण-पोषण का अधिकार रखते हैं।

☞ धारा 125 के अन्तर्गत आवेदन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिया जाता है।

☞ भरण-पोषण की मांग करने वाला व्यक्ति अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए।

☞ जिस व्यक्ति से भरण-पोषण की मांग की जाती है उसे पर्याप्त साधनों वाला (समर्थ व्यक्ति) होना चाहिए।

☞ धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण की राशि निर्धारित नहीं है।

☞ उत्तर प्रदेश में भरण-पोषण की राशि अधिकतम 5,000 (पाँच हजार) रूपये निर्धारित है।

☞ अन्तरिम भरण-पोषण का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा किया गया है।

☞ अन्तरिम भरण-पोषण के मासिक भत्ते और कार्यवाहियों के खर्चे के लिए आवेदन का निस्तारण ऐसे आवेदन के ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर यथासम्भव कर दिया जाना चाहिए।

☞ न चुकाये गये पूरे या उसके भाग के लिए एक मास से अनधिक अवधि के लिये या चुका देने के समय के लिए कारावास का दण्डादेश दे सकता है।

☞ कोई स्त्री भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी जो-

(1) जारता की दशा में रह रही है; अथवा (2)वह पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इन्कार कर देती है; अथवा (3) यदि वे पारस्परिक सम्पति से पृथक रह रहे हैं।

☞ भरण-पोषण सम्बन्धी धनराशि की अदायगी के बारे में निम्नलिखित शर्त्तें महत्वपूर्ण हैं-

(1) व्यक्ति जिसके विरूद्ध भरण-पोषण का दावा किया गया है पर्याप्त साधनों वाला हो।

(2) भरण-पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

(3) भरण-पोषण करने से इन्कार किया हो।

☞ सविता बेन सोमभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य (2.005 सु. को) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 125 के संदर्भ में पत्नी से आशय केवल वैध रूप से विवाहित पत्नी से है न कि किसी ऐसी स्त्री से जो किसी विवाहित पुरूष के साथ पत्नी बनकर रह रही है। धारा 125 के अन्तर्गत अवैध सन्तान को भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अवैध रूप से किसी पुरूष के साथ पत्नी के रूप में रह रही किसी स्त्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

☞ धारा 125 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध धारा 397 के अन्तर्गत पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है।

✯ पुलिस को इतिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ (Information to the Police and their Powers to Investigate)

☞ संज्ञेय अपराध की पुलिस अधिकारी को सूचना देना F.I.R. है।

☞ F.I.R. किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है।

☞ असंज्ञेय अपराध की सूचना उसी थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, जिसके भीतर अपराध घटित हुआ है।

☞ F.I.R. दर्ज करना पुलिस सांविधिक कर्तव्य है।

☞ F.I.R. साक्ष्य नहीं है।

☞ F.I.R. लिखित या मौखिक दी जा सकती है।

☞ F.I.R. इतिला देने वाले के बयान का खण्डन या सम्पुष्टि करने में प्रयोग की जाती है।

☞ यदि प्रथम इतिला देने वाला व्यक्ति बाद में अभियुक्त बने तो वह उसके विरूद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जा सकती है।

☞ यदि किसी ऐसे पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण किया है, जिसको ऐसी शक्ति नहीं थी, तब भी उसके द्वारा अन्वेषण अवैध नहीं होगा। (धारा 156(2))

☞ यदि पुलिस अधिकारी गश्त में है और इतना समय नहीं है कि थाने पर भेजकर लिखवाये तो वैसे भी अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

☞ F.I.R. पर इतिलाकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक है जब वह लिखित हो।

☞ इतिलाकर्ता को एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। (धारा 154(2), 207)

☞ गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि पुलिस अभिरक्षा है।

☞ पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड 15 दिन की इस अवधि में ही दिया जा सकता है।

☞ प्रथम 15 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त को रिमाण्ड पर पुलिस अभिरक्षा में नहीं दिया जा सकता है।

☞ प्रथम 15 दिन की अवधि में पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा दोनों पर रिमाण्ड दिया जा सकता है।

☞ 15 दिन के पश्चात् केवल न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड दिया जा सकता है।

लोकतंत्र की जगह तानाशाही की वकालत कर रहे डोभाल

● उर्मिलेश (वरिष्ठ पत्रकार)

अक्सर देखा गया है कि जब पूर्व राजघरानों से जुड़ा कोई व्यक्ति, रिटायर सेनाधिकारी या सेवानिवृत्त अफसर लोकतांत्रिक राजनीति या सत्ता संरचना का हिस्सा बनता है तो उसका मिजाज जनता पर शासन करने का होता है। लेकिन उसका मिजाज जनता की आकांक्षा और जरूरत के हिसाब से शासन चलाने का नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करिबी अफसर माने जाने वाले अजीत डोभाल का ताजा बयान इसी मिजाज और मानस की अभिव्यक्ति है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर में अपने व्याख्यान में तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं। 'पहली बात ये कि देश को अगले 10 वर्षों तक एक ऐसी मजबूत और स्थायी सरकार चाहिए, जो अस्थायी किस्म के 'गठबंधन सरकारों जैसी कमजोर' न हो। दूसरी ये कि वो जरूरत के हिसाब से कठोर फैसले भी ले सके और तीसरी बात ये कि इस वक्त देश को बाहरी (शत्रु) शक्तियों के मुकाबले अंदर की (शत्रु) शक्तियों से ज्यादा खतरा है। बहुत संभव है कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा पुलिस और खुफिया संगठनों में बिताने वाले डोभाल साहब को लग रहा हो कि उन्होंने अपने व्याख्यान में विचार के कुछ बिल्कुल नए बिंदू पेश किए हैं, पर लगभग इसी तरह के विचार देश की जनता के बीच साल 1974–77 के दौर में भी खूब प्रचारित हुए थे। गठबंधन राजनीति की व्यर्थता पर तो बार–बार ऐसी बातें कही गईं। इतनी कहीं गईं कि मीडिया और मध्यम वर्ग के मुखर हिस्से में इसे राजनीति का 100 फीसदी सच बनाकर पेश किया जाने लगा।

दिलचस्प बात ये है कि डोभाल के व्याख्यान का विषय था– सपनों का भारत : 2030। उन्होंने अपने भाषण में ये बताने की कोशिश की कि किस तरह सपनों के भारत निर्माण की मुश्किलों से बचा जाए। मुश्किलों या बाधाओं की सूची में उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, जन–स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों, मौजूदा आर्थिक नीतियों के चलते तेजी से बढ़ती गैर–बराबरी, लिंगभेद, समाज में बढ़ता तनाव, सांप्रदायिक हिंसा के विविध रूपों और भ्रष्टाचार आदि की कोई चर्चा नहीं की। दिगर बात है कि गठबंधन सरकारों की आशंका और अंदरूनी (शत्रु) शक्तियों से बचाव आदि को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। मजे की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबद्ध तमाम विकास एजेंसियां भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के लिए टिकाऊ या सतत विकास के जिन 17 सूत्री लक्ष्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बता रही हैं, उनमें किसी को भी डोभाल ने याद नहीं किया। जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र के उक्त 17 सूत्री लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि पूर्व की जनसंघ या आज की भाजपा ने अतीत में हमेशा गठबंधन सरकारों की पैरोकारी की। अफसर होने के बावजूद डोभाल ने संघ विचारधारा से अपनी निकटता कभी छुपाई नहीं। फिर वे आज गठबंधन सरकारों की धारणा को सिरे से क्यों खारिज कर रहे हैं?

गौरतलब है कि दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, सभी ने गठबंधन सरकारों की सार्थकता की महिमा गाई। आज भी देश के ज्यादातर राज्यों में गठबंधन के सहारे ही भाजपा राज

कर रही है। फिर मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंतिम चरण में गठबंधन की राजनीति पर संघ–भाजपा बौद्धिकों के तेवर क्यों बदल रहे हैं? क्या संघ–भाजपा के विचारकों को भविष्य में फिर एक नए तरह की गठबंधन सरकार की संभावना नजर आ रही है? इतिहास गवाह है कि भारत में कुछेक अपवादों को छोड़कर प्रचंड बहुमत वाली ज्यादातर सरकारों ने समस्याओं का जितना समाधान किया, उससे ज़्यादा समस्याओं को पैदा किया। प्रचंड बहुमत की कई सरकारें निरंकुशता और तानाशाही की तरफ बढ़ीं, तो कइयों ने भारी संकट पैदा किए। सनद् रहे कि इमरजेंसी लागू करने वाली सरकार भी एक दल की प्रचंड बहुमत वाली ही सरकार थी। राजीव गांधी की अगुवाई में भी एक बार जनता ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया था। उसके हश्र से देश अच्छी तरह वाकिफ है। दूसरी तरफ गठबंधन सरकारों का रिकार्ड देखिए। आजादी के बाद भारतीय राज्यों में जिन सरकारों ने बेहतरीन काम किए, उनमें 90 फीसदी से ज्यादा गठबंधन सरकारें रही हैं। वही केरल को प्रगतिशील राज्य बनाने का श्रेय वाम–लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार को जाता है। कर्नाटक को सुखी और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम देवराज अर्स की गठबंधन सरकार ने ही उठाए। तमिलनाडु में शुरुआत की द्रविड़ संगठनों की सरकारें भी अपनी अंदरूनी प्रकृति में सामाजिक गठबंधन की ही सरकारें थीं। जम्मू–कश्मीर के अब तक के इतिहास में जिन दो सरकारों ने अपेक्षाकृत बेहतर काम किए, वे दोनों गठबंधन की ही सरकारें थीं। शेख अब्दुल्ला की अगुवाई की पहली सरकार पूरी तरह कांग्रेस के समर्थन पर टिकी थी, जिसे साल 1953 में कांग्रेस ने गिरा दिया और शेख को हटाकर अपनी पसंद के नेता की अगुवाई में नयी सरकार बनाई। फिर नवंबर 2002 में मुफ्ती सईद की अगुवाई में कांग्रेस–पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी। शेख सरकार ने जहाँ अपने भूमि सुधार कार्यक्रम से सूबे को समृद्ध और खुशहाल बनाया, वहीं मुफ्ती की पहली सरकार ने आतंकवाद से तबाह सूबे को राहत का मरहम लगाया। हालांकि स्थितियों में काफी सुधार आया, जिसे केंद्र की मौजूदा मजबूत सरकार ने फिर पटरी से उतार दिया और हालात अब साल 2002 के पहले जैसे हो गए हैं। दूसरी तरफ अधिकतम समय बहुमत की सरकारों वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हालात देखिए। मानव विकास सूचकांक, कानून व्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में इनका पिछड़ापन पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना रहता है। मध्य प्रदेश बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए कुख्यात है, जबकि दलितों और महिलाओं पर अत्याचार के लिए यूपी कुख्यात है। अंतरराष्ट्रीय फलक पर देखें तो जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के अनेक विकसित लोकतांत्रिक देशों में गठबंधन या दलीय तालमेल की सरकारें लंबे समय से अच्छा काम करती रही हैं।

गौरतलब है कि डोभाल कह रहे हैं कि अंदरूनी (शत्रु) शक्तियों से देश को ज्यादा खतरा है, फिर उनकी सलाह पर चलने वाली सरकार फ्रांस, रूस, अमेरिका और इसराइल से इतने सारे हथियार, युद्धक विमान, गोला–बारूद, मिसाइलें आदि खरीदने में देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा क्यों गंवा रही है? अंदरूनी (शत्रु) शक्तियों से निपटने के लिए वो जनता को गोलबंद कर सकती है। घरेलू संकट से निपटने भर के हरबा–हथियारों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। डोभाल को ये चिन्हित करना चाहिए था कि ये अंदरूनी शत्रु शक्तियाँ कौन–कौन सी हैं? सिर्फ अर्बन नक्स या अन्य विपक्षी भी? दिवंगत गौरी लंकेश जैसे पत्रकार या दादरी के अखलाक जैसे आम ग्रामीण?

साल 1973–77 के दौर में हमने तब के शासक नेताओं के मुँह से विदेशी हाथ के साथ देश के अंदर के विघटनकारी तत्वों से खतरे की बातें अक्सर सुनी थीं। बार–बार खतरे की बात करते–करते जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा तो इमरजेंसी लागू कर दी गई। क्या भारत उसी तरह के इतिहास की पुनरावृत्ति की तरफ बढ़ रहा है? ये भी बताएं कि कठोर फैसले कौन से वाले? डोभाल को बताना चाहिए कि क्या नए रूप और तरीके के साथ इतिहास दुहराने की कवायद चल रही है। सीबीआई मुख्यालय में दो दिन पहले आधी रात की सर्जिकल स्ट्राइक कोई सामान्य घटना नहीं लगती। जिस आनन–फानन में एक विवादास्पद और संघ–प्रिय अफसर को संस्था की बागडोर सौंपी गई, वो शासन के लोकतांत्रिक मिजाज का परिचायक तो नहीं है। डोभाल साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे संविधान के तहत देश में सरकार पाँच साल के लिए चुनी जाती है। लेकिन वो 10 साल के लिए मजबूत और निर्णय लेने वाली सरकार की निरंतरता की बात कर रहे हैं। हालांकि नए जनादेश के बगैर ये कैसे संभव है? वो कठोर फैसले लेने वाली सरकार की पैरोकारी कर रहे हैं। क्या नोट बंदी जैसे कठोर फैसले? रिजर्व बैंक के आधिकारिक आंकड़े बता चुके हैं कि वो कठोर फैसला सरकार की नीतिगत मूर्खता और व्यर्थता के सिवाए कुछ भी नहीं था। वही 100 से अधिक लोगों की मौत और हजारों लघु व मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों की बंदी से उत्पन्न लाखों लोगों के बेरोजगार किये जाने जैसे कठोर फैसलों को भला कोई भी समझदार और मानवीय सोच का व्यक्ति कैसे जायज ठहरा सकता है? और जो डोभाल भूल गए... । ये महज संयोग नहीं है कि दुनिया के अनेक प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने मोदी सरकार की नोटबंदी को गैर जरूरी और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह कदम बताया। अपने लंबे व्याख्यान में डोभाल ने भारत और चीन की बेवजह तुलना की है। दोनों की स्थितियों और व्यवस्थाओं का फर्क दोनों मुल्कों के लिए विकास की अलग–अलग रणनीति की माँग करता है। भारत ने आजाद मुल्क बनने के बाद अपने विकास के लिए जो रास्ता चुना, उसमें जनतंत्र, समानता और बंधुत्व, तीन सबसे अहम पहलू हैं। डोभाल का बताया रास्ता इन तीनों को नजरंदाज करता है। ●

दीपावली एवं छट्ठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पंचायत एवं प्रखण्ड के सम्पूर्णवासियों को हार्दिक बधाई।
-: निवेदक :-
पप्पु साह, मुखिया
ग्राम पंचायत-पसौर, भोजपुर ।

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

www.shruticommunicationtrust.org

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- Sector - 1, Block - 14, Flat No.- 501, Khelgaon Houseing Colony, Hotwar, Ranchi
Mob.- 9431073769, 9308727077

देशरत्न व भारतरत्न
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
3 दिसम्बर 1884 – 26 फरवरी 1963
कई धर्मों की जन्मस्थली, लोकतंत्र की जननी, त्रेता और द्वापरयुग सहित अखण्ड भारत की राजधानी का गौरव रखने वाला मगध को आज अपना ही देश अपमानित करता है।
देशरत्न व भारतरत्न की 134 वीं जन्मोत्सव महामेला
देशरत्न विशेषांक
"देश में अधिनियमों की भूमिका"
राष्ट्रीय सेमिनार
"देशरत्न केवल सच सम्मान-2018"
दिनांक- 9 दिसम्बर 2018 रविवार
समय- 3 बजे अपराह्न
स्थान - मावलंकर सभागार, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया
रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के सामने, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
-निवेदक-
केवल सच
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
www.kewalsach.com
www.kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ
Mob. 09431073769, 9308727077
Kewal Sach TIMES
A National Magazine
www.kewalsachtimes.com
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
www.ks3.org.in
www.shruticommunicationtrust.org
प्रधान कार्यालय- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
झारखण्ड कार्यालय- सेक्टर-1, ब्लॉक-22, फ्लैट-303, खेलगाँव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, होटवार, राँची (झारखण्ड)
सम्पर्क संख्या :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
राकेश तिवारी
सदस्य (AIZCCRCI)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
सचिव – सक्षम झारखण्ड प्रांत
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS)
ब्रजेश मिश्र
संस्थापक सह संपादक